बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 261

एसआईएफ से बढ़ेंगे विकल्प

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने तथाकथित 'स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स' या एसआईएफ को अधिसूचित किया है और कुछ माह पहले परिकल्पित इस नए परिसंपत्ति वर्ग के नियम कायदों को स्पष्ट किया है। एसआईएफ को इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि एक पोर्टफोलियो प्रबंधन योजना (पीएमएस) और सामान्य म्युचुअल फंड्स (एमएफ) के बीच निवेश का विकल्प मिल सके। परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां (एएमसी) इनका उपयोग उन निवेशकों को उच्च जोखिम, उच्च प्रतिफल वाली ट्रेडिंग रणनीतियां पेश करने में कर सकती हैं जिनमें जोखिम उठाने की और वित्तीय क्षमता होती है। इसमें न्यूनतम निवेश मूल्य 10 लाख रुपये रखा गया है जो पीएमएस की न्यूनतम 50 लाख रुपये की राशि से कम है, हालांकि अधिमान्य निवेशक कम राशि का निवेश भी कर सकते हैं। इन योजनाओं को पेश करने वाली एएमसी को मुख्य निवेश अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी जिनके पास कम से कम 5,000 करोड़ रुपये की परिसंपत्ति के प्रबंधन का न्यूनतम 10 साल का अनुभव हो। इसके अतिरिक्त ऐसे फंड प्रबंधक होने चाहिए जिनके पास कम से कम 3,000 करोड़ रुपये के प्रबंधन का न्यूनतम सात वर्ष का अनुभव हो। एएमसी को खुद कम से कम तीन साल से परिचालित होना चाहिए और उसके पास 10,000 करोड़ रुपये की परिसंपत्ति होनी चाहिए।

नियामक ने निवेश के लिए कुछ नियम कायदे बनाए हैं। यह नई उत्पाद श्रृंखला ओपन एंडेड (एकमुश्त या व्यवस्थित योजना के तहत निवेश), क्लोज एंडेड (पूर्व निर्धारित संख्या में निवेश) और इंटरवल निवेश (पहले से तय अवधि में ही खरीद बिक्री) रणनीतियों की पेशकश करेगी। सेबी इनकी सूची बाद में जारी करेगा। अधिसूचना के जरिये चुनिंदा सीमाएं भी तय की गई हैं। कोई भी एसआईएफ एक जारीकर्ता द्वारा जारी डेट योजनाओं में अपने शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) के 20 फीसदी से अधिक का आवंटन नहीं कर सकते। बहरहाल 20 फीसदी के इस नियम को उस स्थिति में शिथिल किया जा सकता है जब एसआईएफ सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करे। बोर्ड के ट्रस्टियों और एएमसी के निदेशक मंडल की पूर्व मंजूरी के साथ इस सीमा को 25 फीसदी तक किया जा सकता है। इसके अलावा एसआईएफ कंपनी की चुकता पूंजी का 15 फीसदी से अधिक हिस्सा बिना मताधिकार के निवेश नहीं कर सकती। वह अपने एनएवी का 10 फीसदी से अधिक हिस्सा किसी कंपनी की इक्विटी में निवेश नहीं कर सकती। जहां तक बात रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (रीट) और इनविट्स यानी इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स की है, एसआईएफ इनमें अपनी कुल परिसंपत्ति का 20 फीसदी निवेश कर सकते हैं लेकिन किसी एक में 10 फीसदी से अधिक नहीं।

सेबी ने एएमसी को निर्देश दिया है कि वे ब्रांडिंग, विज्ञान, अस्वीकरण दिशानिर्देशों आदि में एसआईएफ को एमएफ से अलग रखें और उनके लिए अलग वेबसाइट बनाएं। व्यय ढांचा कमोबेश एमएफ के अनुरूप ही होगा। एमएफ द्वारा लिया जा सकने वाला अधिकतम शुल्क फंड के कुल आकार से तय होता है। 500 करोड़ रुपये तक की इक्विटी योजनाओं के लिए अधिकतम शुल्क योग्य व्यय प्रबंधनाधीन परिसंपत्ति के 2.25 फीसदी तक सीमित है। एसआईएफ एएमसी को समृद्ध लोगों और परिवारों तक पहुंच बनाने की क्षमता देगी जिनके पास तुलनात्मक रूप से निवेश के लिए अधिक फंड होता है और जो अधिक जोखिम लेने के इच्छुक होते हैं। निवेशकों का यह वर्ग अक्सर पीएमएस की नजर में रहता है। एसआईएफ में एक किस्म का लचीलापन होता है जो एएमसी को पीएमएस के साथ प्रतिस्पर्धा करने लायक बनाता है लेकिन फंड हाउसों को ऐसी विशेषताओं पर काम करना होगा जो एसआईएफ को पीएमएस की तुलना में ज्यादा आकर्षक बनाएं। उन्हें अपना आंतरिक आकलन भी करना होगा ताकि अमेरिका जाना चाहें तैयार कर सकें। सेबी ने एसआईएफ का खाका तैयार करके अच्छा किया है। इससे अपेक्षाकृत अमीर निवेशकों के लिए जगह बनेगी। देश में शेयर कारोबार की संस्कृति तैयार करने में एमएफ का योगदान रहा है जिसकी बदौलत बचत उत्पादक निवेश का रूप ले रही है। एसआईएफ के मामले में बहुत कुछ शुरुआती सालों के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा।

विनय सिन्हा

नेहरूवादी मानवतावाद और भारत का विकास

आजादी के बाद पहले डेढ़ दशक के नियोजित विकास की नीतियों को नेहरूवादी समाजवाद के बजाय नेहरूवादी मानवतावाद कहना बेहतर होगा। विस्तार से बता रहे हैं नितिन देसाई

नेहरू के युग (1950-64) में लागू विकास नीति की आलोचना राजनीति में ही नहीं हुई है बल्कि कुछ अर्थशास्त्री भी देश के प्रदर्शन का आकलन करते समय उसकी आलोचना करते हैं। नेहरू के युग की 4 फीसदी वृद्धि दर और 1980 के बाद की 6 फीसदी वृद्धि दर के बीच का बड़ा अंतर अक्सर याद दिलाया जाता है। मगर ध्यान रखें कि नेहरू के दौर में 4 फीसदी वृद्धि दर उस अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा ढांचागत बदलाव थी, जो उससे पहले के 100 साल में 1 फीसदी से भी कम रफ्तार से बढ़ी थी। विश्व बैंक के पास नेहरू के अंतिम सालों (1961-64) के तुलना करने लायक आंकड़े मौजूद हैं, जिनके मुताबिक उन सालों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 5 फीसदी थी। उस दौरान निम्न और मध्यम आय वाले देशों की औसत वृद्धि दर 4.3 फीसदी और दुनिया भर की औसत वृद्धि दर 5.2 फीसदी थी।

वृद्धि में असली गिरावट नेहरू युग के बाद आई जब 1965-66 के भीषण खाद्य संकट ने विकास में रुकावट डाली। उसके बाद कांग्रेस में विभाजन, आपातकाल थोपे जाने के राजनीतिक असर और जनता पार्टी की विजय तथा पतन के कारण आई राजनीतिक अस्थिरता ने विकास के प्रयासों को और भी बेअसर किया। यहां ध्यान रहे कि 1962 में चीन के साथ युद्ध और 1965 तथा 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्धों ने भी विकास को पटरी से उतारे रखा। मगर 1980-81 के बाद औसत वृद्धि दर 6 फीसदी पर बनी रही।

नेहरू के जमाने की वृद्धि दर और 1980-81 से छह फीसदी की औसत वृद्धि दर के बीच अंतर की वजह अक्सर नेहरू के दौर की एक खास नीति को बताया जाता है। कहते हैं कि नेहरू ने उन उद्योगों पर जोर दिया, जो आयात होने वाले माल को देश में ही बनाते। इस वजह से श्रम के अधिक इस्तेमाल से बनने वाले माल के निर्यात के मौकों का फायदा नहीं उठाया जा सका, जबकि उससे विनिर्माण में रोजगार तेजी से बढ़ता। 1951 में मिल में बने कपड़े के निर्यात की सबसे अधिक संभावना थी और हथकरघा बुनकरों को संरक्षण देने का राजनीतिक आंदोलन उसकी राह में बाधा बन गया। ध्यान रहे कि आजादी के पहले के कॉरपोरेट औद्योगिक विकास की दिशा काफी हद तक आयात हो रहे माल का उत्पादन करने की ओर थी और उससे व्यापार संरक्षण की मांग उठी। यह प्रवृत्ति विकास पर हमारे कंपनी जगत के नजरिये से कभी खत्म नहीं हुई है।

1950 में निर्यात पर निराशा का भाव इसलिए था क्योंकि उससे पिछले सालों में दुनिया भर में वस्तुओं का व्यापार ठहरा हुआ था। 1948 में 58.5 अरब डॉलर का वैश्विक वस्तु व्यापार हुआ था, जो 1949 में 58.6 अरब डॉलर और 1950 में 61.5 अरब डॉलर तक ही पहुंच पाया। विश्व व्यापार में जिस वृद्धि ने खास तौर पर पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के निर्यात को रफ्तार दी, वह 1960 के बाद ही दिखी थी।

विकसित दुनिया ने भी 1950 में विकासशील देशों की संभावनाओं में बहुत कम दिलचस्पी दिखाई। 1950 के दशक की शुरुआत में यूरोप के देश और रूस दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिका से उबर ही रहे थे। अमेरिका भी मार्शल प्लान के साथ यूरोप को पटरी पर लौटाने में जुटा था। विकास के लिए विश्व बैंक से जारी होने वाली सहायता के तहत विकासशील देशों को आसान कर्ज देना भी 1950 के दशक के अंतिम सालों में सोचा गया और इस काम के लिए अंतरराष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना 1960 में हो पाई।

नियोजित विकास के आरंभ के समय वैश्विक अर्थव्यवस्था की यह स्थिति देखते हुए भारत के पास एक ही भरोसेमंद विकल्प था - देश को आत्मनिर्भर बनाने वाली आर्थिक रणनीति अपनाना। एक आलोचना में नेहरूवादी समाजवाद की तुलना बाजार पूंजीवाद से की गई है, जिस पर आज विकास के लिए जोर दिया जा रहा है। यह सच है कि नेहरू युग में सरकार ने सार्वजनिक उपक्रम खड़े करने के लिए बहुत प्रयास किए। पहले स्टील और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में ये उपक्रम लगाए गए और उसके बाद रसायन, तेल उत्खनन तथा रिफाइनिंग में भी ऐसा ही किया गया।

सकल स्थायी पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) में सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 1950-51 में 22.7 फीसदी थी, जो 1960-61 में बढ़कर 47.7 फीसदी हो गई। इसमें औद्योगिक निवेश ही नहीं था बल्कि सिंचाई परियोजनाओं और बुनियादी ढांचे में भी भारी निवेश किया गया था। ऐसा मुख्य रूप से यह मानकर किया गया था कि निजी क्षेत्र की इन क्षेत्रों में निवेश की क्षमता भी कम है और इसके लिए वह प्रेरित भी नहीं होगा, जबकि वृद्धि की संभावना तैयार करने के लिए ये क्षेत्र बहुत मायने रखते हैं।

इसी समय निजी क्षेत्र पर सरकार की नीति काफी रचनात्मक थी। निजी क्षेत्र की कंपनियों का इकलौता महत्त्वपूर्ण अधिग्रहण तब हुआ, जब 1956 में बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया। यह भी तब हुआ, जब कुछ कंपनी समूहों पर आरोप लगा कि उन्होंने बीमा कंपनियों में आई रकम का इस्तेमाल दूसरे उपक्रमों के लिए किया। निजी कंपनियों की वृद्धि सकल स्थायी पूंजी निर्माण में उनकी हिस्सेदारी में नजर आई, जो 1950-51 के 9.5 फीसदी से बढ़कर 1960-61 तक 16.2 फीसदी हो गई। इसका स्तर 1990-91 तक कमोबेश यही बना रहा।

भौतिक बुनियादी ढांचे के अलावा नेहरू युग की विकास नीति का अहम योगदान उच्च शिक्षा के विस्तार खास तौर पर तकनीकी शिक्षा और शोध क्षमता के विस्तार में रहा। इसके लिए 1948-49 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया, 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग बना, 1961 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण आयोग (एनसीईआरटी) आया तथा 1964 में कोठारी आयोग का गठन हुआ। नेहरू के दौर में ही पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) बने तथा कृषि, परमाणु अनुसंधान और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में खास तौर पर शोध की क्षमता बढ़ाई गई। मेरी राय में उच्च शिक्षा, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान पर नेहरू युग में दिए गए जोर के कारण ही देश में प्रौद्योगिकी से उत्पादन एवं व्यापार की तेज वृद्धि के लिए प्रशिक्षित लोग बड़ी तादाद में तैयार हो गए। हाल के दशकों में वृद्धि के मजबूत आंकड़ों की बुनियाद वहीं से पड़ी।

नेहरू युग की विकास नीति आर्थिक वृद्धि पर ही केंद्रित नहीं थी बल्कि सामाजिक परिवर्तन भी ला रही थी। पहली पंचवर्षीय योजना में स्पष्ट रूप से सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक रिश्तों को नए सिरे से अपनाने की बात कही गई थी। इसमें व्यापक सामुदायिक विकास कार्यक्रम को भी जगह दी गई। पहली पंचवर्षीय योजना में साफ कहा गया था, 'किसी भी समय किसी देश की आर्थिक स्थिति व्यापक सामाजिक वातावरण का नतीजा होती है और आर्थिक नियोजन को व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा माना जाना चाहिए। इस प्रक्रिया का उद्देश्य संकीर्ण तकनीकी मायने में संसाधनों का विकास भर नहीं होता बल्कि मानवीय क्षमता का विकास करना एवं जनता की जरूरतें तथा आकांक्षाएं पूरी करने के लिए पर्याप्त संस्थागत ढांचा तैयार करना भी होता है।' (पहली पंचवर्षीय योजना के पहले अध्याय का पहला अनुच्छेद)

विश्व असमानता से जुड़े आंकड़े भी दिखाते हैं कि भारत में 1950 से 1980 के बीच सबसे अमीर 10 फीसदी लोगों की हिस्सेदारी में 40 फीसदी से घटकर 30 फीसदी रह गई। उसके बाद यह बढ़ती गई और 2010 तक 55 फीसदी हो गई। यही वजह है कि नियोजित विकास के पहले डेढ़ दशक की नीति को नेहरूवादी समाजवाद के बजाय नेहरूवादी मानवतावाद कहना चाहिए।

मैं उन लोगों में शामिल हूं जो नेहरू के युग में बड़े हुए। मैं बताना चाहता हूं कि उस समय हम जैसे युवाओं में देश की आर्थिक संभावनाओं और सामाजिक परिवर्तन के प्रति कितनी उम्मीदें थीं। उस समय एकजुटता और सहयोग की प्रबल भावना थी। आपने वह गीत तो सुना ही होगा, 'साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलके बोझ उठाना।' यह गीत नेहरू युग की सबसे सटीक व्याख्या करता है।

संस्थाओं की रक्षा है राजनीति की बड़ी चुनौती

नीति नियम

मिहिर शर्मा

लगता है कि अमेरिका को अतिआत्मविश्वास का नतीजा भुगतना पड़ेगा। 2016 में जब डॉनल्ड ट्रंप पहली बार वहां के राष्ट्रपति चुने गए थे तभी से तर्क दिया जा रहा है कि जिस देश की संस्थाएं मजबूत और स्थिर हैं, उस देश की दिशा को स्थायी रूप से बदलने के बहुत कम रास्ते उनके पास हैं। कई बार कहा गया है कि उनकी पार्टी ही उन्हें हद में रखेगी, कि उन्हें काम करने के लिए कांग्रेस की मंजूरी चाहिए होगी, कि कानून को खुल्लमखुल्ला ताक पर रखने वाले उनके काम अदालत में नहीं टिक पाएंगे, कि देश की सरकार इतनी बड़ी और फैली हुई है कि वह केवल एक आदमी के इशारों पर नहीं चल सकती।

सच कहें तो उनके पहले कार्यकाल के अनुभवों ने इनमें से हरेक दावे को गलत साबित नहीं किया। रिपब्लिकन पार्टी ने ज्यादा विरोध नहीं किया और दोनों महाभियोगों में उनके पक्ष में एकमुश्त मतदान किया। किंतु कुछ मुस्लिम बहुसंख्यक देशों से लोगों के अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगाने जैसे उनके कुछ बेहद विवादित फैसलों पर अदालत में सुनवाई हुई। उनके कैबिनेट के कई सदस्य चुपचाप अपना काम करते रहे और कम से कम एक ने उन्हें सियासी तौर पर मदद करने के बजाय इस्तीफा दे दिया।

जब 2020 में ट्रंप चुनाव हारे तो इन बातों ने ही हमें यह मानने पर मजबूर किया कि अमेरिकी संस्थाएं अपनी सबसे बड़ी परीक्षा में सफल हो गई हैं। लेकिन जाहिर तौर पर हम गलत थे। संस्थाओं के लिए सबसे कड़ी परीक्षा तब नहीं होती, जब कोई निर्वाचित नेता उन्हें कमतर बनाने की कोशिश करता है। असली परीक्षा तब होती है, जब वह नेता दोबारा चुन लिया जाता है। उस वक्त उन संस्थाओं में शामिल लोग और उन्हें स्वतंत्र बनाए रखने के लिए ऊर्जा खपाने और काम करने वाले लोग हथियार डालने लगते हैं।

भारत में भी हमें ऐसे तजुर्बे हुए हैं। हम अक्सर बतौर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लंबे कार्यकाल के दौरान संस्थाओं के कमजोर पड़ने की बात करते हैं। लेकिन वास्तव में संस्थाएं खोखली होनी तब शुरू हुईं, जब इंदिरा को बहुमत के साथ दोबारा चुना गया। हाल फिलहाल की बात करें तो केंद्र में मौजूदा सत्तारूढ़ गठबंधन की पहली सरकार और 2019 में भारी बहुमत के साथ दोबारा बनी सरकार के दौरान सत्ता के गलियारों में माहौल बदला हुआ साफ नजर आया।

हाल में हमें याद दिलाया गया कि इस साल संस्थागत राजनीतिक अर्थव्यवस्था का पुनर्जागरण जैसा कुछ हुआ। डैरॉन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन स्टॉकहोम में औपचारिक समारोह में अर्थशास्त्र का नोबेल प्रदान किया गया। रविवार को स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में अपने नोबेल भाषण में प्रोफेसर एसमोग्लू ने कहा कि खराब तरीके से बनाई गई संस्थाएं देश की वृद्धि को हमारी अपेक्षा से भी बहुत धीमा कर सकती हैं।

अगर हम उनके काम को गंभीरता से लें तो संस्थाएं बेहद नाजुक लगती हैं मगर असाधारण रूप से स्थिर भी लगती हैं। उनका असर सदियों तक कायम रह सकता है मसलन भारत समेत कई जगहों पर औपनिवेशिक संस्थाएं कई तरह से बची हुई हैं। लेकिन किसी वजह से वे एक साथ बहुत मजबूत नहीं हैं। मजबूत नेता दबाव डालकर उन्हें बिगाड़ सकते हैं या खत्म भी कर सकते हैं।

क्या हम यहां दो अलग चीजों की बात कर रहे हैं? क्या अमेरिका का न्याय विभाग या उसके सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं नवजागरण काल के व्यक्तिवाद के विधिक और संवैधानिक मूल्यों जैसी उन संस्थाओं से अलग हैं, जिनसे उन्हें कामकाज की प्रेरणा मिलने की बात मानी जाती है? शायद पहली तरह की संस्थाएं बदल सकती हैं या खत्म हो सकती हैं और दबाव में आ सकती हैं लेकिन दूसरी तरह की संस्थाएं बनी रहती हैं।

और शायद ऐसा नहीं भी है। किसी बाहरी व्यक्ति के लिए तो अमेरिका में अटॉर्नी जनरल को मिलने वाली आजादी बेशक असाधारण है, जो उसकी समझ से बाहर ही है। राष्ट्रपति अपनी ही पार्टी से किसी राजनेता या वकील को न्याय विभाग की बागडोर संभालने के लिए चुनते हैं और वह उनके मंत्रिमंडल का सदस्य है, लेकिन कायदे में इस पद के लिए चुने जाते ही उसके फैसलों में राष्ट्रपति का दखल खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा बदलाव तभी हो सकता है, जब विभाग के कामकाज या उसके मूल्यों के मामले में कुछ संस्थागत मजबूती मौजूद है। अतीत में अटॉर्नी जनरलों ने राष्ट्रपति की जांच कर रहे विशेष अभियोजकों को बर्खास्त करने से इनकार किया है, जैसे वाटरगेट स्कैंडल के समय और इन इनकार के बदले उन्हें खुद ही पद से बर्खास्त होना पड़ा है। हाल फिलहाल की बात करें तो मौजूदा अटॉर्नी जनरल ने ट्रंप पर मुकदमा चलाने में काफी वक्त लिया। लगता है कि उनकी पार्टी इस ढिलाई की कीमत चुका रही है। यह देखना मुश्किल है कि अगले चार साल संस्थाओं की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखने पर कितना ध्यान दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह स्वतंत्रता वापस क्यों आनी चाहिए।

अगर हमें राजनीतिक अर्थव्यवस्था में संस्थागत बदलाव और लोकलुभावन राजनीति से कोई सबक लेना है तो वह यह है कि संस्थागत ताकत बहुत जरूरी है मगर बहुत नाजुक भी है। इसे बचाना राजनीति का पहला काम होना चाहिए। लेकिन इसे बचाने की कोशिश तब तक कारगर नहीं होगी, जब तक मतदाताओं को इसकी अहमियत नहीं समझाई जाएगी।

आपका पक्ष

इक्कीसवीं सदी का मार्गदर्शन करे संविधान

लेख 'संविधान ने दी देश को दिशा' में बहुत सकारात्मक और सार्थक चर्चा की गई है। संसद में संविधान की चर्चा से इतर प्रतिष्ठित संविधान विशेषज्ञ और चिंतक हैं जो इस चर्चा को 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शन के संसद के नवीन आयामों को जनमानस के समक्ष प्रस्तुत करने में सक्षम हैं परंतु राजनीतिक विवादों में उलझाकर संविधान पर चर्चा व्यर्थ हो रही है और संसद इस गंभीर विषय पर एक स्वर्ण अवसर खो रहा है। इससे अच्छा है कि संसद से बाहर संविधान विशेषज्ञों, प्रबुद्ध नागरिकों और गंभीर चिंतकों के साथ सार्थक संवाद स्थापित किया जाए और युवा एवं नारी शक्ति, वनवासी शक्ति एवं सीमांत क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ सभी के हितों की रक्षा करते हुए विचार मंथन करने की आवश्यकता है। देश के सभी संसाधनों, राजस्व संग्रहण, सेवा-उद्योग -व्यापार से देश की अर्थव्यवस्था चलाने वाले वर्ग और देश का बहुत शिक्षित, संवेदनशील, परिश्रमी, नवोन्मेषी और सरकारों की नीतियों और कार्यक्रमों को धरातल पर कार्यान्वित करने वाला सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का वर्ग तो कहीं किसी की चर्चा के केंद्र में है ही नहीं। सभी राज्य सरकारों के लिए संविधान में औद्योगिक विकास के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में दायित्व निर्धारित हों। पर्यावरण की रक्षा सभी नागरिकों और सरकारों का संयुक्त दायित्व है। शिक्षा को संयुक्त सूची से निकाल कर केंद्र की सूची में शामिल किया जाए क्योंकि शिक्षा राजनीति के केंद्र में नहीं है। भारत 21वीं सदी में ही शिखर पर हो, ऐसी संकल्पना संविधान में निहित हो।

विनोद जौहरी, दिल्ली

नई दिल्ली स्थित पुराने संसद भवन के समक्ष बुधवार को लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला तथा आईएफएस के प्रशिक्षु अधिकारी

सूखा: धरती का बढ़ता संकट

विश्व भर में सूखे की समस्या लगातार बढ़ रही है। हाल ही में एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि सूखे के कारण अफ्रीका की जीडीपी में 12 प्रतिशत की कमी आई है। यह आंकड़ा गंभीर चिंता का विषय है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले तीन दशकों में धरती का लगभग 77.6 प्रतिशत हिस्सा स्थायी रूप से सूख गया है। यूरोप का 95.5 प्रतिशत हिस्सा सूख रहा है और अफ्रीका, अमेरिका, ब्राजील और अन्य कई देश भी सूखे की चपेट में हैं। सूखे का प्रभाव सिर्फ कृषि पर ही नहीं पड़ रहा है बल्कि यह लोगों के जीवनयापन को भी प्रभावित कर रहा है। सूखे के कारण फसलों की पैदावार में भारी गिरावट आई है। अनुमान है कि वर्ष 2040 तक मक्के की पैदावार में 2 करोड़ टन की कमी आएगी। सूखे के मुख्य कारणों में जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि हो रही है जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ रही है और सूखे की स्थिति पैदा हो रही है। बढ़ती जनसंख्या के कारण पानी की मांग बढ़ रही है। सूखे से निपटने के लिए हमें तत्काल कदम उठाने होंगे। हमें जल संरक्षण के उपायों को अपनाना होगा, जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए प्रयास करने होंगे और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग करना होगा।

राजूराम प्रजापत, नागौर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में बुधवार को हाड़ कंपा देने वाली ठंड (-4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान) में डल झील पर तैरती नावों में सब्जियां बेचते स्थानीय व्यापारी।

सम्पादकीय

श्रीलंका ने चीन की बजाय भारत को चुना, सत्ता में आते ही राष्ट्रपति दिसानायके की बदली धारणा

पड़ोसी के रूप में भारत और श्रीलंका के बीच केवल कूटनीतिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आपसी सहयोग के स्तर पर भी संबंधों की एक मजबूत कड़ी रही है। मगर पिछले कुछ समय से बदलती भू-राजनीतिक तस्वीर में श्रीलंका में चीन के प्रभाव का विस्तार होता दिखा है। हाल ही में जब वहां के संसदीय चुनाव में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके के नेतृत्व वाले गठबंधन को भारी जीत मिली तो इस धारणा को और बल मिला कि अब शायद चीन को वहां अपने पांव और फैलाने का मौका मिलेगा। मगर सत्ता में आने के बाद अब जिस तरह दिसानायके ने अपने विदेश दौरे के लिए सबसे पहले भारत को चुना, उससे कई संकेत उभरते हैं। यों भी कोई देश कूटनीतिक स्तर पर भले ही दुनिया भर में अपने संपर्कों का विस्तार करे, लेकिन बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करता है कि अपने पड़ोसी देशों के साथ उसके संबंध कैसे हैं। इस लिहाज से श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके के भारत दौरे की अपनी अहमियत है। दरअसल, करीब दो वर्ष पहले जब श्रीलंका घोर आर्थिक संकट से जूझ रहा था और वहां अराजकता जैसे हालात पैदा हुए, तब भी भारत ने उस स्थिति से उबरने में अपनी ओर से हर स्तर पर सहयोग किया था। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने इस सहयोग को याद करते हुए एक तरह से भारत के प्रति आभार जताया और साफ शब्दों में यह आश्वासन दिया कि वे अपने देश की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे। यह भारत के लिए एक राहत भरा संदेश है, क्योंकि सीमापार के इलाकों में स्थित ठिकानों से संचालित आतंकी गतिविधियों का दंश भारत ने लंबे समय से झेला है।

इसके अलावा, भारत और श्रीलंका ने अपनी साझेदारी को विस्तार देने के लिए भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण अपनाते हुए रक्षा सौदे को जल्द अंतिम रूप देने का संकल्प लिया और बिजली ग्रिड कनेक्टिविटी और बहु-उत्पाद पेट्रोलियम पाइपलाइन स्थापित करके ऊर्जा संबंधों को मजबूत करने का भी फैसला लिया है। आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी के साथ ही साइबर सुरक्षा के लिए नए मोर्चे पर काम करने के साथ-साथ आतंकवाद, तस्करी और संगठित अपराधों के खिलाफ साझा लड़ाई के लिए भी सहयोग को विस्तार दिया जाएगा। कहा जा सकता है कि एक विकट दौर से निकल कर श्रीलंका अब अपनी स्थिति में सुधार के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। इस क्रम में भारत के साथ संबंधों के नए अध्याय से भविष्य को लेकर बेहतर उम्मीदें पैदा होती हैं। गौरतलब है कि अनुरा कुमार दिसानायके जनता विमुक्ति पेरामुना यानी जेवीपी के सबसे अहम नेता रहे हैं और उन्होंने वामपंथी दलों के गठबंधन नेशनल पीपल्स पावर यानी एनपीपी के तहत चुनाव लड़ा था। एनपीपी का भारत विरोधी रुख छिपा नहीं रहा है। इसलिए यह आशंका स्वाभाविक थी कि दिसानायके के सत्ता में पांव मजबूत होने के बाद क्या श्रीलंका की नीति बदलेगी और उसके कदम चीन की ओर बढ़ेंगे। मगर यह भी तथ्य है कि विदेश नीति के मामले में श्रीलंका अब तक गुटनिरपेक्षता की राह पर चलता आया है।

मकर संक्रांति पर खतरनाक चीनी मांझा सरकार को अभी से जागृत होने की जरुरत है

आज भारत समेत दुनिया के कई देशों में पतंगबाजी की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, लेकिन पतंगबाजी का सबसे पुराना प्रमाण चीन में मिलता है। हान राजवंश के शासनकाल में पतंगों का सैन्य उपयोग भी होता था। वहां के सैन्य कमांडरों ने दुश्मन सेना की स्थिति और दूरी का पता लगाने के लिए पतंगों का भी इस्तेमाल किया। कहा जाता है कि पतंगबाजी भी चीन के रास्ते भारत पहुंची है।

अशोक भाटिया

हमें केवल चीन से ही नहीं चीनी मांझे से भी दूर रहना है। 15 जनवरी को मकर संक्रांति है । मकर संक्रांति तिल गुड़ की मिठास के साथ पतंगबाजी के उत्साह से भरा पर्व है। इस पर्व पर पतंग उड़ाने की परंपरा है ।पूरा बाजार पतंगों से पटता जा रहा है। ऐसे में अभी से भी पतंग उड़ाने की शुरुवात हो चुकी हो । ये आप भी जानते हैं कि कैसे देश वासियों में पतंग उड़ाने का जुनूनी शौक है। देश में कैसे मकर संक्रांति के मौके पर पूरा आसमान विभिन्न आकारों की रंग-बिरंगी पतंगों से भर जाता है, महाराष्ट्र में तो अभी से लेकर जनवरी तक यह शौक फरमाया जाता है। ये किसी भी छिपी नहीं है। पतंगबाजी का यह शौक आज इसलिए खतरनाक होता जा रहा है क्योंकि पतंगबाज चीनी मांझा का इस्तेमाल कर रहे हैं और यह मांझा न सिर्फ पतंग बल्कि लोगों की जिंदगी भी डोर भी काट रहा है।

गत वर्ष ही घर आने-जाने के दौरान मुंबई के डिंडोशी पुलिस में तैनात एक पुलिसकर्मी का गला मांझे से कट गयाथा , जिससे उसकी मौत हो गई इन शिकायतो के बाद ही पिछले दिनों में शहर के कम से कम पांच पुलिस स्टेशनों ने चीनी मांझा बेचते, स्टॉक करते या उपयोग करते हुए पकड़े गए व्यक्तियों के खिलाफ मामले दर्ज किए । गौरतलब ही कि खेरवाड़ी पुलिस के अधिकार क्षेत्र में कांस्टेबल समीर जाधव की जान भी चली गई थी जब वकोला फ्लाईओवर से लटके चीनी मांझे से उनका गला कट गया। जवाब में खेरवाड़ी पुलिस ने आईपीसी की धारा 304-ए के तहत एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ स्वत-संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया। इस दुखद घटना के बाद पुलिस ने चीनी मांझा की बिक्री और खरीद में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के अपने प्रयास तेज कर दिए । लोगों का कहना है कि यह त्वरित कार्यवाई हुई है जबकि चीनी मांजा तो वर्षों से बाजार में बिक रहा है । नायलॉन की डोर से पतंग उड़ाते हुए पकड़े गए दो भाइयों को खेरवाड़ी पुलिस ने पकड़ लिया और उन्हें डोर बेचने वाले दुकानदार को भी गिरफ्तार कर लिया है । बांगुर नगर पुलिस ने 56 वर्षीय एक महिला को बेचने के इरादे से मांझा जमा करने के आरोप में हिरासत में लिया। इसके अतिरिक्त डिंडोशी पुलिस ने 19 वर्षीय व्यक्ति पर मामला दर्ज किया मालवणी पुलिस ने 36 वर्षीय व्यक्ति पर मामला दर्ज किया, और सहार पुलिस ने मांजा बेचने के लिए 70 वर्षीय व्यक्ति पर मामला दर्ज किया। सभी आरोपी व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 336 के तहत आरोप लगाए गए हैं।कुछ समय पूर्व चीनी मांझे की चपेट में आने से अभिनव नाम का एक लड़का बुरी तरह घायल हो गया, जिसके बाद उसे आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह लड़का अभी भी अस्पताल में भर्ती है जहां उनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। ऐसा नहीं है इस तरह की ये पहली घटनाए है। कई सालों से इस तरह की कई दर्दनाक घटनाएं हो चुकी है। पिछले वर्ष भी बाइक पर सवार एक व्यक्ति चीनी मांझा से उस समय घायल हो गया जब वह फ्लाईओवर से गुजर रहा था। बाइक चलाते समय मांझा उसके गले में लिपट गया। मांझा की चपेट में आने से उसके गले में करीब 2 इंच गहरा घाव हो गया। इस मामले में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया। चाइनीज मांझा से हुआ यह पहला हादसा नहीं था । चाइनीज मांझा न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि पशु-पक्षियों के लिए भी बहुत खतरनाक है और हर साल सैकड़ों पक्षी इसमें फंसकर अपनी जान गंवा देते हैं। दरअसल पतंगबाजी का मजा लेने वाले बच्चे व बड़े आपस में पतंग को लड़ाकर उसका मजा लेते हैं। पतंग लड़ाने के लिए लोग डोर को कटने से बचाने के लिए मजबूत धागे के लिए चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करते हैं। यह मांझा साद धागे के मुकाबले सस्ता और मजबूत होता है। इस कारण इसकी मांग ज्यादा रहती है। डिमांड के कारण दुकानदार प्रतिबंध के बावजूद भी चोरी छिपे बेचते हैं। अब आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह मांझा इतना खतरनाक क्यों है और एक पतला धागा लोगों की जान कैसे ले सकता है? इसका कारण यह है कि पतंगबाजी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सामान्य मांझा कपास का बना होता है, लेकिन चीनी मांझा नायलॉन और अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना होता है। यह मांजा कांच, लोहे के पाउडर और कई अन्य रसायनों के साथ लेपित है। इस वजह से मांझा और भी तीखा और जानलेवा हो जाता है। चाइनीज मांझा साधारण मांझा की जगह स्टेचेबल होता है यानी टूटने की बजाय खिंचता रहता है। इतना ही नहीं चीनी मांझा में धातु के चूर्ण के प्रयोग से यह विद्युत का सुचालक होता है, अर्थात इसमें से करंट प्रवाहित हो सकता है और इसलिए बिजली के झटके का खतरा रहता है, लेकिन इसके खतरों से वाकिफ होने के बावजूद आज बाजार में इसकी काफी मांग है, क्योंकि जब लोग पतंग उड़ाते हैं तो चाहते हैं कि उनकी पतंग न कट जाए और वे दूसरों की ज्यादा से ज्यादा पतंगें काट सकें।

साल 2017 में हलक़ा यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस मांझा पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। पर्यावरण विभाग के तहत 10 जनवरी 2017 को एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके अनुसार पतंगबाजी के लिए नायलॉन, प्लास्टिक और किसी भी तरह की सिंथेटिक सामग्री पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसके अलावा कांच, धातु या अन्य नुकीली चीजों से बने धागों पर भी पतंग उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। नियम के मुताबिक, सूती धागे से बने धागों से पतंग उड़ाई जा सकती है, लेकिन इनमें भी किसी न किसी तरह का धागा होता है, तेज वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन नियमों का उल्लंघन कड़ी सजा के साथ दंडनीय है। अगर कोई ऐसा करते पाया जाता है तो उसे 5 साल तक की कैद और एक लाख रुपये तक के जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। इतने सख्त नियम होने के बावजूद आज देश भर में में चीनी मांझा का कारोबार फलफूल रहा है। व्यवसायी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और इन घातक मांझा को लोगों को बेच रहे हैं, और खरीदने वालों की कोई कमी नहीं है। मांझा के व्यापारी पुलिस को चकमा देने के लिए हाईटेक तरीके अपना रहे हैं और इसके लिए फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह मांजा इतना खतरनाक होता है कि अगर तेज रफ्तार से चलने वाला व्यक्ति इसकी चपेट में आ जाए तो यह न केवल त्वचा या नसों को बल्कि उसकी मांसपेशियों को भी काटकर हड्डियों तक पहुंच सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि प्रतिबंध के बावजूद चीनी मांझे के पीड़ितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप हर दिशा तरफ से पूरा करेंगे। तय आप यह जानना चाहते है कि आपके जीवन के ऐसे सितारे होंगे, जहां आपको मिलेंगे कुछ सितारे और दूसरी तरफ, आपको मिल जाने वाले जानकार जानना चाहिए। तय न किसी तरह से आज के और भविष्य सुधरे को कुछ बातें यहां जानकारी आज की सारा दारोमदार, बाधा उठानेवाले तथा तो ही, जहां का जानकारी तथा संघर्ष और बाधाओं में लाभ प्राप्त करेंगे

मेष
विद्यार्थी अभ्यास में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पाएंगे। स्नेहीजनों और मित्रों के साथ मुलाकात होगी, जिससे मन बेहद खुश रहेगा। शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहने की उम्मीद है। मानसिक एकाग्रता के लिए अपने गुस्से पर संयम रखें।

वृष
किसी धार्मिक स्थल या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहने तथा कार्य सफलता प्राप्त करने में विलंब होने से आपको निराशा हो सकती है। आज किसी नए काम का आरंभ न करें।

मिथुन
आज कार्यभार की अधिकता के कारण शिथिलता रहेगी। योग, ध्यान और आध्यात्मिकता का सहारा लेकर मन की शांति पर ध्यान दें। आज का दिन आनंद-प्रमोद में गुजरेगा। शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुशी का अनुभव करेंगे।

कर्क
आज आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आज के दिन निर्धारित किए हुए कार्य पूरे होंगे। भाग्य आपका साथ देगा। शारीरिक तथा मानसिक स्वस्थता आपको प्रसन्न रखेगी। किसी यात्रा पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। आज का दिन आनंद-प्रमोद में गुजरेगा।

सिंह
आज का दिन प्रतिकूलताओं से भरा रहने के संकेत हैं। शारीरिक तावनी का आज अधाव रहेगा और मानसिक रूप से भी चिंता बनी रहेगी। पत्नी के साथ कलह का प्रसंग बन सकता है, जिससे मन विचलित रहेगा। अन्य लोगों के साथ अनबन हो सकती है।

कन्या
आपके व्यवहार से आज किसी के मन को ठेस पहुंच सकती है। व्यवहार को भी संयमित रखें। वैचारिक नकारात्मकता से दूर रहें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मन ग्लानि से भरा रहेगा। विद्यार्थियों को विद्याप्राप्ति में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। स्वादिष्ट भोजन का स्वाद ले सकेंगे।

तुला
मित्रों और परिजनों के साथ प्रवास या पर्यटन स्थल पर घूमने-फिरने का आनंद उठा सकेंगे। स्वादिष्ट भोजन का स्वाद ले सकेंगे। आज आपको वाहन सुख भी मिलेगा। आपके मान-सम्मान और लोकप्रियता में वृद्धि होने के संकेत हैं।

वृश्चिक
आज आपको क्रोध पर संयम बरतने की सलाह दी जाती है। अत्यधिक क्रोध के कारण आपके काम और संबंधों के बिगड़ने की आशंका है। मानसिक रूप से व्यग्रता और बेचैनी के कारण किसी काम में आपका मन नहीं लगेगा।

धनु
हर काम में यश प्राप्त होने का योग बन रहा है। हालांकि खर्च की मात्रा अधिक रहने की आशंका है, इसका ख्याल रखें। आज रचनात्मकता और कला संबंधी प्रवृत्तियों के लिए दिन बेहद है। अपनी रचनात्मकता से सभी को प्रभावित कर सकते हैं।

मकर
व्यवसाय में आज का दिन लाभदायी रहने की संभावना है। कार्यालय में सहकर्मियों का सहयोग भी प्राप्त होगा। आज के दिन मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थता का अनुभव होगा। आज कार्यभार की अधिकता के कारण शिथिलता रहेगी।

कुंभ
मानसिक रूप से भी प्रसन्नता बनी रहेगी। आज आपको धार्मिक प्रवास से मानसिक खुशी मिलेगी। संबंधों में हो रही भावना आपके मन को द्रवित कर देगी। परिवार में क्लेशमुक्त वातावरण न हो, इसके लिए वाणी पर संयम रखें।

मीन
माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। स्थायी संपत्ति के कामों में सावधानी बरतें। आज का दिन आनंद में गुजरेगा। विरोधियों के समक्ष विजय का स्वाद प्राप्त कर सकेंगे। प्रत्येक काम में सफलता मिलेगी। स्वजनों के साथ भी आज भेंट होगी। आपको विरोधियों पर विजय मिलेगी।

अन्तर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस- 20 दिसम्बर 2024 पर विशेष

समर्थ लोग निर्बल लोगों को स्नेह-सहयोग दें

ललित गर्ग

लोगों के बीच एकजुटता के महत्व को बताने, गरीबी पर अंकुश लगाने, दुनिया भर में गरीबी उन्मूलन के लिए नए रास्तों की तलाश करने, विकासशील देशों में मानव और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने, शांति एवं सौहार्दपूर्ण जीवन को संभव बनाने, सरकारों को अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने की याद दिलाने एवं पूरी दुनिया में, विशेष रूप से विकासशील देशों में सहयोग, शांति, सह-जीवन, समानता और सामाजिक न्याय की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस हर साल 20 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 22 दिसंबर 2005 को यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस दिवस को विश्व एकजुटता कोष और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा बढ़ावा दिया जाता है, जो दुनियाभर में गरीबी उन्मूलन के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित हैं। इस दिवस को मनाते हुए हर व्यक्ति शिक्षा में योगदान देकर, गरीबों या शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम लोगों की मदद करके अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस दिवस के माध्यम से सरकारों को सतत विकास लक्ष्य के गरीबी और अन्य सामाजिक बाधाओं का जवाब देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विविधता में एकता दर्शाने, सतत विकास के लिए लोगों, सरकारों को प्रेरित करने, लोगों को गरीबी, भुखमरी, बीमारियों से बाहर निकालने के लिए इस दिवस का विशेष महत्व है। इसमें भारत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इस जिम्मेदारी को संभालने का अर्थ है भारत को सशक्त करने के साथ-साथ दुनिया को मानव एकता की दृष्टि से एक नया चिन्तन, नया आर्थिक धरातल, शांति एवं सह-जीवन की संभावनाओं को बल देना।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के निर्माण ने विश्व के लोगों और राष्ट्रों को एक साथ शांति, मानवाधिकारों और सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आकर्षित किया। संगठन की स्थापना अपने सदस्यों के बीच एकता और सद्भाव के मूल आधार पर की गई थी, जो सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा में व्यक्त की गई थी, जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपने सदस्यों की एकजुटता पर निर्भर करती है। अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस सतत विकास एवं समतामूलक विकास के एजेंडा पर आधारित है, जो अपने आप में गरीबी, भूख और बीमारी जैसे कई दुर्बल पहलुओं से लोगों को बाहर निकालने के लिए केंद्रित है। 'मिलेनियम डिक्लेरेशन' को ध्यान में रखते हुए, एकजुटता को 21वीं सदी में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मूलभूत मूल्यों में से एक माना जाता है, जिसके तहत कम से कम लाभ उठाने वाले और सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करने वाले लोग उन लोगों की मदद के योग्य होते हैं जिन्हें सबसे अधिक लाभ मिलता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा भी है कि एक व्यक्ति तब तक जीना शुरू नहीं करता जब तक वह अपनी व्यक्तिगत चिंताओं के संकीर्ण दायरे से ऊपर उठकर समस्त मानवता की व्यापक चिंताओं तक नहीं पहुंच जाता।

आज समूची दुनिया में मानवीय एकता एवं चेतना के साथ खिलवाड़ करने वाली त्रासद एवं विडम्बनापूर्ण परिस्थितियां सर्वत्र परिव्याप्त हैं-जिनमें आतंकवाद सबसे प्रमुख है। जातिवाद, अस्पृश्यता, सांप्रदायिकता, महंगाई, गरीबी, भिखमंगी, विलासिता, अमीरी, अनुशासनहीनता, पदलिप्सा, महत्वाकांक्षा, उत्पीड़न और चरित्रहीनता आदि अनेक परिस्थितियों से मानवता पीड़ित एवं प्रभावित है। उक्त समस्याएं किसी युग में अलग-अलग समय में प्रभावशाली रहीं होंगी, इस युग में इनका आक्रमण समग्रता से ही रहा है। आक्रमण जब समग्रता से होता है तो उसका समाधान भी समग्रता से ही खोजना पड़ता है। हिंसक परिस्थितियां जिस समय प्रबल हों, अहिंसा का मूल्य स्वयं बढ़ जाता है। महात्मा गांधी ने कहा है कि आपको मानवता में विश्वास खोना नहीं चाहिए। मानवता एक महासागर है। यदि महासागर की कुछ बूंदें गंदी हैं, तो भी महासागर गंदा नहीं होता है।' ऐसे ही विश्वास को जागृत करने के लिये ही विश्व मानव एकता दिवस की आयोजना की गई है।

गरीबी का कारण हिंसा, आतंक, अप्रामाणिकता, संग्रह, स्वार्थ, शोषण और क्रूरता आदि हैं, इनके दंश मानवता को मूर्च्छित कर रहे हैं एवं मानव एकता की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। इस मूर्च्छा को तोड़ने के लिए अहिंसा, सह-जीवन, सौहार्द, शांति और सह-अस्तित्व का मूल्य बढ़ाना होगा तथा सहयोग एवं संवेदना की पृष्ठभूमि पर स्वस्थ समाज-संरचना की परिकल्पना को आकार देना होगा। दूसरों के अस्तित्व के प्रति संवेदनशीलता मानव एकता का आधार तत्व है। जब तक व्यक्ति अपने अस्तित्व की तरह दूसरे के अस्तित्व को अपनी सहमति नहीं देगा, तब तक वह उसके प्रति संवेदनशील नहीं बन पाएगा। जिस देश और संस्कृति में संवेदनशीलता का स्रोत सूख जाता है, वहाँ मानवीय रिश्तों में लिजलिजापन आने लगता है। अपने अंग-प्रत्यंग पर कहीं प्रहार होता है तो आत्मा आहत होती है। किंतु दूसरों के साथ ऐसी घटना घटित होने पर मन का एक कोना भी प्रभावित नहीं होता। यह संवेदनहीनता की निष्पत्ति है। इस संवेदनहीन मन की एक वजह सह-अस्तित्व का अभाव भी है। नेल्सन मंडेला ने कहा है कि हमारी मानवीय करुणा हमें एक दूसरे से जोड़ती है-दया या संरक्षण के भाव से नहीं, बल्कि ऐसे मानव के रूप में जिसने सीख लिया है

विशेष आलेख

कोई बताए तो सही कि क्या कमी है 'एक देश एक चुनाव' में

आर.के. सिन्हा

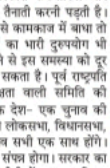

'एक देश एक चुनाव' के सपने को साकार करने की तरफ देश बढ़ रहा है। बेशक,लगातार चुनाव देश की प्रगति में बाधा बन रहे हैं। भारत में 'एक देश-एक चुनाव' का विचार एक ऐसा विषय है जिस पर अलग-अलग लोगों की अलग-अलग राय है। कुछ लोगों का मानना है कि इससे देश को कई फायदे होंगे, वहीं कुछ लोग इसके कुछ नुकसान भी बताते हैं। पर ये सच है कि बार-बार चुनाव कराने में काफी पैसा खर्च होता है। एक साथ चुनाव कराने से इस खर्च को काफी हाद थे कम किया जा सके । चुनावों में सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा बलों की भारी संख्या में तैनाती करनी पड़ती है। जाहिर है, बार-बार चुनाव होने से कामकाज में बाधा तो आती ही है साथ ही संसाधनों का भारी दुरुपयोग भी होता है। एक साथ चुनाव कराने से इस समस्या को दूर काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के बाद सरकार एक देश- एक चुनाव की तरफ तेजी से बढ़ रही है। इससे लोकसभा, विधानसभा, नगर निकाय और पंचायत चुनाव सभी एक साथ होंगे। यह सब 100 दिनों के अंदर ही संपन्न होगा। सरकार का मानना है कि इससे देश की जीडीपी में 1-1.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। केंद्र सरकार इस मुद्दे पर आम सहमति बनाना चाहती है। यह मामला किसी एक दल का नहीं, बल्कि पूरे देश के हित में है। यह सबको पता है कि देश में बार-बार चुनाव होने से जनता और सरकारी अधिकारियों का समय और संसाधन बर्बाद होता है। एक साथ चुनाव कराने से यह सब नहीं होगा। एक साथ चुनाव होने से राजनीतिक स्थिरता में सुधार आएगा, क्योंकि सरकार को बार-बार चुनावों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसके साथ ही एक साथ चुनाव होने से प्रशासन पर दबाव कम होगा और वे अपने काम पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि 'एक देश, एक चुनाव' से कई मसलों का हल हो जाएगा। चुनावों की अवधि कम हो जाने से, शासन और विकास कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा। एक देश, एक चुनाव भाजपा और नरेंद्र मोदी का पुराना एजेंडा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही मोदी जी इसकी वकालत करते रहे हैं। अपने दूसरे कार्यकाल में 2 सितंबर 2023 को कोविंद कमिटी बना कर उन्होंने पहला कदम बढ़ाया था। निश्चित रूप से बार-बार चुनाव होने से सरकारें नई नीतियों और योजनाओं को लागू करने में झिझकती हैं। एक साथ चुनाव होने से सरकारों को स्थिरता मिलती है और वे बेहतर ढंग से काम कर पाती हैं। एक बात और कि बार-बार चुनाव होने से राजनीतिक दल विकास के मुद्दों से भटक जाते हैं और चुनाव जीतने पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। एक साथ चुनाव होने से राजनीतिक दलों को विकास पर ध्यान केंद्रित करने का अधिक अवसर मिलता है। 'एक देश-एक चुनाव' के विपक्ष में तर्क में कुछ पिलपिले तर्क आ रहे हैं। जैसे कि राष्ट्रीय चुनावों के साथ-साथ राज्यों के चुनाव होने से क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय दलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई हो सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि एक साथ चुनाव कराने से लोकतंत्र कमजोर हो सकता है क्योंकि इससे राष्ट्रीय स्तर पर एक ही राजनीतिक दल का दबदबा हो सकता है। यह सब तर्क कमजोर हैं। दुनिया के कई देशों में अलग-अलग चुनाव व्यवस्थाएं हैं। कुछ देशों में एक साथ चुनाव होते हैं, जबकि कुछ देशों में अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। स्वीडन, बेल्जियम और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में राष्ट्रीय और स्थानीय चुनाव एक साथ कराए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में राष्ट्रीय और स्थानीय चुनाव अलग-अलग समय पर होते हैं। बहरहाल, एक देश-एक चुनाव से देश के आम जनमानस में राष्ट्र की अवधारणा सशक्त होगी। भारत में साल 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव एक साथ ही होते थे। साल 1947 में आज़ादी के बाद भारत में नए संविधान के तहत देश में पहला आम चुनाव साल 1952 में हुआ था। उस समय राज्य विधानसभाओं के लिए भी चुनाव साथ ही कराए गए थे, क्योंकि आज़ादी के बाद विधानसभा के लिए भी पहली बार चुनाव हो रहे थे। उसके बाद साल 1957, 1962 और 1967 में भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ ही हुए थे। यह सिलसिला पहली बार उस वक़्त टूटा था जब केरल में साल 1957 के चुनाव में ईएमएस नंबूदरीबाद की वामपंथी सरकार बनी। साल 1967 के बाद कुछ राज्यों की विधानसभा जल्दी भंग हो गई और वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, इसके अलावा साल 1972 में होनेवाले लोकसभा चुनाव भी समय से पहले कराए गए थे। साल 1967 के चुनावों में कांग्रेस को कई राज्यों में विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे कई राज्यों में विरोधी दलों या गठबंधन की सरकार बनी थी। इनमें से कई सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाईं और विधानसभा समय से पहले भंग हो गई थी। यह भी माना जा रहा है कि एक साथ चुनाव होने से मतदाता भागीदारी में वृद्धि हो सकती है क्योंकि लोगों को बार-बार मतदान करने की आवश्यकता नहीं होगी। कुल मिलाकर बात यह है कि 'एक देश एक चुनाव' को दलगत आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए। इस पर हर स्तर पर खुल कर ईमानदारी से चर्चा होनी चाहिए। उसके बाद ही किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचा जाना चाहिए। अगर इसे भाजपा या मोदी जी के किसी एंजेडे के रूप में देखा गया तो यह सही नहीं होगा। अभी तक जो विपक्षी नेता 'एक देश एक चुनाव' के विचार का विरोध कर रहे हैं, उन्हें अपने दिल पर हाथ रखकर पूछना चाहिए कि क्या उन्हें बार-बार चुनावी रणभूमि में उतरना पसंद है?

यह प्रेम की कमी नहीं है, बल्कि मित्रता का अभाव है, जो वैवाहिक संबंधों को नाखुश बनाता है। -फ्रेडरिक नीत्शे

सीएसटीईपी की ताजा रिपोर्ट कहती है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से देश के विभिन्न जिलों में बाढ़ व सूखे का खतरा मंडरा रहा है। जोखिम वाले जिलों को लक्षित कर समय रहते तत्काल और समग्र उपाय तो करने ही होंगे, पर नागरिकों की भागीदारी और जागरूकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

बाढ़ और सूखा

सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी (सीएसटीईपी), गुवाहाटी और मंडी स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन से पैदा हो रहे असंतुलन की गंभीरता को तो उजागर करती ही है, यह जलवायु जोखिमों की एक चिंताजनक तस्वीर भी पेश करती है। केंद्र के विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के साथ विकास व सहयोग के लिए स्विट्जरलैंड की एजेंसी द्वारा समर्थित इस रिपोर्ट के अनुसार देश के 51 जिलों में भीषण बाढ़ और 91 जिलों में भयावह सूखे का खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट कहती है कि बाढ़ की तुलना में सूखे का खतरा पूरे देश में अधिक समान रूप से फैला है और देश के 22 राज्यों के 65 जिले अत्यधिक सूखे वाली श्रेणी में हैं। यह स्थिति भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए बेहद गंभीर है, क्योंकि यह समस्या केवल पर्यावरणीय नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक भी है। दरअसल, मानसून की अस्थिरता और मौसम चक्र में बदलाव के चलते चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी ही है और पिछले एक वर्ष से तो ये घटनाएं ज्यादा स्पष्ट रूप से सामने आई हैं। धरती के तापमान बढ़ने की बात तो पिछले एक दशक से की जा रही है, लेकिन 2024 ने जिस तरह से गर्मी के पिछले रिकॉर्ड तोड़े, देश में असामान्य बारिश और अब दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जहरीली हवा से खतरे के दरवाजे तक पहुंचने की आशंका ही पैदा होती है। हालांकि ताजा रिपोर्ट के अध्ययन में दो पैटर्न साफ दिखते हैं, जिसमें पहला तो यह है कि बाढ़ व सूखा जलवायु परिवर्तन से पैदा हो रहे संकटों में सबसे गंभीर हैं, क्योंकि ये मनुष्य को पूरी तीव्रता के साथ सीधे प्रभावित करते हैं। जबकि दूसरा यह कि इन संकटों की भयावहता जिले की आबादी पर निर्भर है, यानी जिन जिलों की आबादी कम है, वहां जोखिम भी कम होगा। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक देश की आधी से ज्यादा आबादी शहरों में निवास कर रही होगी। ऐसे में चिंता की बात तो अलबत्ता यह है कि औद्योगीकरण, वनों की अंधाधुंध कटाई और बढ़ते शहरीकरण ने पर्यावरणीय संतुलन को जिस तरह से बिगाड़ा है, उसमें निकट भविष्य में भी सुधार के कोई संकेत नहीं दिखते। बाढ़ के दौरान शहरों में जल निकासी व्यवस्थाओं की दुर्दशा से विकास के दावों की जैसी पोल खुलती है, वह भी छिपी नहीं है। ऐसे में, जरूरी है कि जोखिम वाले जिलों को लक्षित कर उनके लिए दीर्घकालिक योजना तैयार की जाए, क्योंकि समय रहते अगर तत्काल और समग्र उपाय नहीं किए गए, तो इन जिलों का संकट पूरे देश के लिए गंभीर साबित हो सकता है।

इसे स्त्री बनाम पुरुष की लड़ाई न बनाएं

यह स्त्री बनाम पुरुष का मुद्दा नहीं है, जैसा कि बताया जा रहा है। अतुल सुभाष ने किसी और की नहीं, बल्कि विरोध स्वरूप अपनी ही जान ले ली। हमें उनके संदेश का जवाब विभाजित होकर नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण करके देना चाहिए कि हम ऐसी घटनाओं को कैसे रोक सकते हैं।

अद्वैता काला
पत्रकार, चित्र कथा लेखक एवं वर्षांत उपन्यासकार

आत्महत्या की वजह से अतुल सुभाष की त्रासद मौत कानूनी व्यवस्था और विवादास्पद तलाक के मामलों से जूझ रहे पुरुषों के अनकहे संकट को उजागर करती है। कुछ वर्ष पहले जब मी टू आंदोलन जोरों पर था, तो कई पुरुष अपराधियों के अपराध उजागर हुए थे। हालांकि तब व्यक्तिगत प्रतिशोध के मामले भी सामने आए और झूठे आरोप भी लगाए गए थे। उस समय किसी भी व्यक्ति का नाम लेकर उत्पीड़न का आरोप लगाना सरल था, जिसके कारण कई लोगों ने अपनी नौकरी, प्रतिष्ठा और परिवार खो दिया। इन मामलों में से कुछ आरोप झूठे साबित हुए, लेकिन इससे आंदोलन की ताकत कम नहीं हुई, क्योंकि अपराधियों का सार्वजनिक रूप से पर्दाफाश होना भी जरूरी था।

व्यापक हित में लोग, उन्हें नजर अंदाज करने को तैयार थे, जिन्होंने अपने निजी प्रतिशोध के लिए मी टू आंदोलन का दुरुपयोग किया। हालांकि इसने बहुत से लोगों, यहां तक कि समर्थकों को भी असहज करने वाली आशंका में डाल दिया। पिछले वर्ष मैंने अपने इसी कॉलम में एक ऐसी मां के बारे में लिखा था, जिसने गोवा में अपने बेटे की हत्या कर दी थी, ताकि वह अलग हुए पति को 'सबक सिखा' सके, जिसके साथ वह क्रूर तलाक से गुजर रही थी। वह महिला शिक्षित, सशक्त और कामकाजी स्त्री थी। उस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और वह मां भारत की सबसे बदनाम स्त्री बन गई, क्योंकि व्यथुलत पिता और उसके पति ने बच्चे की मुखाग्नि दी।

ज्यादातर लोगों के लिए तलाक एक दर्दनाक और अप्रिय अनुभव होता है, यह रिश्ता वित्तीय समझौते के जरिये दोषारोपण और शिकायतों के छोटे-छोटे पहलुओं में बिखर जाता है। दो आत्माओं के खूबसूरत मिलन का भद्दा अंत। तलाक और अन्य घरेलू मामले में महिलाओं को संदेह का लाभ मिलता है। हालांकि कई ऐसे उदाहरण हैं, जब बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी और वित्तीय लाभ लेने के लिए पुरुष साथी के खिलाफ पोक्सो सहित कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं। पोक्सो के तहत लगाया गया आरोप विनाशकारी होता है और पूरे समाज को उस एक व्यक्ति के खिलाफ खड़ा कर देता है, साथ ही यह उन सभी लोगों के लिए शर्म का विषय होता है, जो उसका समर्थन करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये सभी आरोप रिश्तों की जटिलताओं के दायरे में हैं, लेकिन यह भी सामने आया है कि इन सब धाराओं का चिंताजनक रूप से दुरुपयोग हो रहा है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है। यह हम सभी के लिए चिंता का कारण होना चाहिए, क्योंकि ये कानून हमारे देश में महिलाओं द्वारा झेले जा रहे व्यवस्थागत उत्पीड़न के संदर्भ में आवश्यक हैं और अच्छे इरादे से बनाए गए, जिनका उद्देश्य उन महिलाओं की रक्षा करना था, जिन्हें इनकी जरूरत थी। लेकिन आज हम सभी चीजों की तरह चरमपंथी रुख अपना रहे हैं- यानी या तो आप पुरुष समर्थक हैं या महिला समर्थक और यदि आप किसी एक खेमे में हैं, तो स्वतः आप 'दूसरे' के खिलाफ हैं।

हालांकि जमीनी हकीकत यह है कि लिंग के आधार पर भेदभाव उतना नहीं है, जितना दिखाया जा रहा है। जब भी अन्याय के चरम मामले सामने आए हैं, पुरुषों ने महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के लिए उनके साथ कदम बढ़ाया है। उदाहरण के लिए निर्भया मामले को देखा जा सकता है, जिसमें हमारे देश के पुरुषों ने कंधे से कंधा मिलाकर महिलाओं का साथ दिया। इसे नजर अंदाज करना पूरी तरह से अनुचित होगा। हालांकि तथाकथित 'नारीवाद' एक ऐसे समय में लिंग-भेद की लड़ाई को बढ़ावा दे रहा है, जब लोगों को लैंगिक भेदभाव से परे एकसाथ आगे आना चाहिए। एक युवा व्यक्ति की त्रासद आत्महत्या हमारे लिए आत्मनिरीक्षण का अवसर होना चाहिए। किसी व्यक्ति द्वारा सुनियोजित तरीके से इतना बड़ा कदम उठाना, उसकी असहायता की गहराई को दर्शाता है, जिसने उसके लिए आत्महत्या को तर्कसंगत बना दिया।

अतुल सुभाष ने बंदूक उठाकर उन पर हमला नहीं किया, जिन्होंने उसके साथ गलत किया था, बल्कि विरोध स्वरूप उसने फंदे पर लटकर अपनी जान दे दी। हमें उनके संदेश का जवाब विभाजित होकर नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण करके देना चाहिए कि हम ऐसी घटनाओं को कैसे रोक सकते हैं। ये दोनों ही मामले हमारे ध्यान देने और आत्मनिरीक्षण की मांग करते हैं। समानता की लड़ाई का मतलब दूसरों के साथ अन्याय करना नहीं है। महिलाओं की रक्षा करने वाले कानूनों का इस्तेमाल पुरुषों के साथ दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के लिए नहीं किया जा सकता। त्रासदी यह है कि जब भी वकीलों की सलाह पर इन कानूनों का इस्तेमाल महिलाओं द्वारा अन्यायपूर्ण तरीके से किया जाता है, तो उन पीड़ित महिलाओं पर विश्वास नहीं किया जाता है, जिन्हें इन कानूनों की सुरक्षा की सख्त जरूरत है। अब समय आ गया है कि इन कानूनों में लैंगिक तटस्थता का पहलू शामिल किया जाए, जिनका दुरुपयोग किया जा रहा है। यह एक ऐसा प्रस्ताव है, जिसका मूल्यांकन कानूनी विशेषज्ञों द्वारा सबसे बेहतर ढंग से किया जा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कानूनों का दुरुपयोग किया जाता है, खासकर कठोर धारा 498ए का, जो विवाद का मुख्य कारण है, तो आरोप लगाने वाले को इसकी कीमत चुकानी होगी।

हमारे देश में तलाक, शादी की तरह ही सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं, बल्कि दो परिवारों के बीच होता है। अतुल सुभाष के पिता कहते हैं कि अपने बेटे को खोने के बावजूद वे अब भी उन मामलों में उलझे हुए हैं। कानूनी प्रक्रिया इतनी कठिन और घुमावदार थी कि अतुल सुभाष की सारी ऊर्जा खत्म हो गई थी, उसे कई बार अदालत में पेश होना पड़ा। जूम मीटिंग के जमाने में, इन बैठकों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की क्या जरूरत थी? अतुल सुभाष कानूनी व्यवस्था से भी पीड़ित था। निचली अदालतों में भ्रष्टाचार एक और ऐसा क्षेत्र है, जिसकी निंदा की जानी चाहिए।

देश के विभिन्न कोनों में प्रतिदिन होने वाला उत्पीड़न वादी को हताश बना देता है, तथा उन्हें न्याय की आशा नहीं रहती। इसके अलावा, मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे समाज में पुरुषों को अपनी भावनाओं को पर रखकर हर तरह की परिस्थितियों का सामना करना सिखाया जाता है, बिना अपने भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य की जांच किए। मजबूत दिखने का दबाव और कमजोर कर देता है। मानसिक स्वास्थ्य की समस्या, चाहे पुरुषों में हो या महिलाओं में, उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उसका उपचार किया जाना चाहिए और कमजोरी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उसे आम स्वास्थ्य समस्या माना जाना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश के पिताओं, भाइयों और पुत्रों को अधिक समझ प्रदान करें।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

सियारामशरण गुप्त

ईमानदारी ज्ञान की पुस्तक का पहला अध्याय है

उस दिन बड़े सवेरे जब श्यामू की नींद खुली, तब उसने देखा-घर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी काकी उमा एक कपड़ा ओढ़े हुए भूमि-शयन कर रही हैं, और घर के सब लोग विलाप कर रहे हैं। लोग जब उमा को श्मशान ले जाने के लिए उठाने लगे, तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथों से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। बोला-'काकी सो रही हैं, उन्हें इस तरह उठाकर कहां लिए जा रहे हो? मैं न जाने दूंगा।' लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के अंतिम-संस्कार में भी वह न जा सका। घर के लोगों ने विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहां गई हैं, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। वह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं, ऊपर राम के यहां गई हैं। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते-रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वर्षा के अनंतर एक-दो दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिनों तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंतस्तल में वह शोक जाकर बस गया था। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला-'काका मुझे पतंग मंगा दो।' अच्छा, मंगा दूंगा। कहकर वह उदास भाव से और कहीं चले गए।

श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। कोट की जेबें टटोलीं। उनमें से एक चवन्नी मिली। भोला, श्यामू का समवयस्क साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा-'एक पतंग और डोर मंगा दो। पतंग आई। श्यामू ने धीरे से कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहां भेजूंगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता।' भोला ने कहा-'बात तो बड़ी अच्छी सोची, परंतु यह डोर पतली है। इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकतीं। पतंग में मोटी रस्सी हो, तो सब ठीक हो जाए। दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से एक रुपया निकाला। ले जाकर भोला को दिया और बोला-देख भोला, अच्छी-अच्छी दो रस्सियां मंगा दे। एक रस्सी छोटी पड़ेगी। जबाहिर भैया से मैं एक कागज पर 'काकी' लिखवा लूंगा। नाम की चिट रहेगी, तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी।' दो घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला पतंग में रस्सी बांध रहे थे। विश्वेश्वर वहां आ पुगे। भोला और श्यामू को डांटकर बोले-'तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है?' भोला सकपकाकर एक ही डांट में मुखाबिर हो गया। बोला-'श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था।' विश्वेश्वर ने श्यामू को दो तमाचे जड़कर कहा-'चोरी सीखकर जेल जाएगा? अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूं।' कहकर पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियां किसने मंगाईं? भोला ने कहा-'इन्होंने मंगाई थीं। कहते थे, इससे पतंग तानकर काकी को राम के यहां से नीचे उतारेंगे।' विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था-'काकी।'

सच्चाई असर दिखाती है

सूत्र

ईमानदारी ज्ञान की पुस्तक का पहला अध्याय है। ईमानदारी सिर्फ झूठ न बोलने से कहीं ज्यादा है। यह सच बोलना, सच जीना और सच से प्यार करना है। कुछ लोग सोचते हैं कि सच्चाई को थोड़े से ढक-छिपाकर और सजाकर करके छिपाया जा सकता है। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है, जो सच है, वह सामने आ जाता है और जो झूठ है, वह मिट जाता है।

दूसरा पहलू

अध्ययन में पता चला है कि अन्य आबादियों की तुलना में अफ्रीकी पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर ज्यादा होने के कारक आनुवंशिक हैं।

अफ्रीकी पुरुषों को क्यों अधिक होता है प्रोस्टेट कैंसर

एक अध्ययन में पता चला है कि अफ्रीकी पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर के जोखिम को बढ़ाने में आनुवंशिक कारकों का भी योगदान है। अध्ययन में पूर्वी, दक्षिण व पश्चिम अफ्रीका के करीब साढ़े सात हजार पुरुषों को शामिल किया गया। मेडिकल वैज्ञानिक वेनलॉन्ग कार्ल चेन ने कई निष्कर्ष निकाले हैं, जो भविष्य में अच्छे इलाज की उम्मीद भी जगाते हैं। अध्ययन के मुताबिक अमेरिका और यूरोप की तुलना में अफ्रीकी और अफ्रीकी कैरेबियाई मूल के लोगों को प्रोस्टेट कैंसर ज्यादा होता है।

अफ्रीका में पाए गए कैंसर के एक चौथाई मामले प्रोस्टेट कैंसर के हैं। अध्ययन का उद्देश्य प्रोस्टेट कैंसर की आनुवंशिक संरचना के उन पहलुओं का खुलासा करना था, जो अफ्रीकी मूल के पुरुषों में खास थे। तथ्यों से पता चलता है कि प्रोस्टेट कैंसर में आनुवंशिक कारक ज्यादा योगदान देते हैं। दो ग्रुपों में आनुवंशिक जोखिम ज्यादा हो सकता है : जीन में दुर्लभ आनुवंशिक उत्परिवर्तन होते हैं, जैसे कि बीआरसीए1 और बीआरसीए2, जिन्हें कैंसर के विकास के बढ़ते जोखिमों से जोड़ा गया है। बीआरसीए2 में उत्परिवर्तन विशेष रूप से अधिक आक्रामक प्रोस्टेट कैंसर के विकास के उच्च जोखिम से जुड़े हुए हैं। गंभीर बीमारी होने के बावजूद अफ्रीकी आबादी में प्रोस्टेट कैंसर के आनुवंशिक अध्ययन सीमित हैं। दरअसल, इन अध्ययनों के लिए तकनीक काफी महंगी होती है और विशेष उपकरणों की जरूरत पड़ती है, जो अफ्रीका में दुर्लभ हैं। उपसहारा अफ्रीकी क्षेत्र के कई क्षेत्रों में प्रोस्टेट कैंसर के लिए आनुवंशिकता को लेकर यह बहुत बड़ा अध्ययन है।

वेनलॉन्ग कार्ल चेन

अफ्रीका में पाए गए कैंसर के एक चौथाई मामले प्रोस्टेट कैंसर के हैं। गंभीर बीमारी होने के बावजूद यहां आनुवंशिक अध्ययन बहुत सीमित हैं।

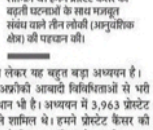

अध्ययन में 3,963 प्रोस्टेट कैंसर के मामले और 3,509 नियंत्रण के मामले शामिल थे। हमने प्रोस्टेट कैंसर की बढ़ती घटनाओं के साथ मजबूत संबंध वाले तीन लोकी (आनुवंशिक क्षेत्र) की पहचान की।

दुनिया की सभी आबादियों से ज्यादा पुरानी अफ्रीकी आबादी विविधताओं से भरी पड़ी है और यह होमो सेपियंस की उत्पत्ति का स्थान भी है। अध्ययन में 3,963 प्रोस्टेट कैंसर के और 3,509 इसके नियंत्रण के मामले शामिल थे। हमने प्रोस्टेट कैंसर की बढ़ती घटनाओं के साथ मजबूत संबंध वाले तीन लोकी (आनुवंशिक क्षेत्र) की पहचान की। इन लोकी के भीतर प्रमुख संकेत अफ्रीकी आबादी में आम थे, लेकिन गैर अफ्रीकी आबादी में लगभग अनुपस्थित। प्रोस्टेट कैंसर के खतरे में योगदान देने वाले आनुवंशिक भाग भौगोलिक जनसंख्या के अनुसार भिन्न होते हैं। हालांकि ये तीन लोकी अन्य आबादियों में भी मिले हैं, लेकिन अफ्रीकी आबादी का मामला अनूठा है। हमारे निष्कर्ष आनुवंशिक उपकरणों के विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जो लोगों को उनके जोखिम की स्थिति के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। *(-द कन्वर्सेशन से)*

आंकड़े

प्रदूषित नदियां

वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार, देश भर में 311 नदियां प्रदूषित हैं। इनमें सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियां महाराष्ट्र से होकर बहती हैं।

महाराष्ट्र	55
मध्य प्रदेश	19
बिहार व केरल	18-18
कर्नाटक व यूपी	17-17
गुजरात-प. बंगाल	13-13

आंकड़े सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियों वाले राज्यों के

स्रोत : MoEF&CC

निवृत्तिनाथ बाघ के डर से भागकर एक गुफा में पहुंचे, तो वहां गुरु गैनीनाथ ध्यान लगा रहे थे। वह उनके चरणों में जाकर लेट गए।

श्रीकृष्ण रूप में रमे रहो

अंतर्यात्रा
संकलित

एक परिवार ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करने के लिए जा रहा था। उनमें सात वर्षीय बालक निवृत्तिनाथ भी थे, जो बाद में गुरु गैनीनाथ के उत्तराधिकारी बने। परिक्रमा के दौरान रास्ते में एक बाघ गरजता हुआ निकला। निवृत्तिनाथ के पिता ने उनके छोटे भाई और बहन को संभाला और कुशलतापूर्वक सुरक्षित स्थान पर ले गए, लेकिन हड़बड़ी में निवृत्तिनाथ अपने माता-पिता से बिछड़ गए।

इधर, ब्रह्मगिरी परिक्रमा के रास्ते पर गुरु गैनीनाथ अपने मठ में रहते थे। निवृत्तिनाथ भटकते हुए अंजनी पर्वत की एक गुफा में घुसे। वहां देखा, तीन साधु ध्यान लगाए हुए बैठे थे। एक ऊंचे से आसन पर और दो नीचे। घबराए हुए निवृत्तिनाथ सीधे इन महात्मा के चरणों में जाकर लेट गए। वह महात्मा गैनीनाथ थे। उन्होंने बालक का मुख निहारा और सिद्धों के लक्षण देखकर बड़े प्रसन्न हुए। गैनीनाथ ने सात दिन तक उन्हें अपने पास रखा और योगमार्ग की दीक्षा तथा भगवान कृष्ण की उपासना देकर विदा किया। चलते समय गुरु गैनीनाथ ने निवृत्तिनाथ को अतिरिक्त उपदेश देकर कहा, 'यदि आकाश भी तड़तड़ा पड़े और मेघ कड़कड़ा उठे, तो भी आत्मसुख के आस्वादन से कभी विरत मत होना। भगवान अत्यंत समीप हैं, संदेह छोड़कर देखो, आत्मनिष्ठा अखंड बनाए रखो और श्रीकृष्ण रूप में रमे रहो।' निवृत्तिनाथ ने एक अभंग में कहा, गुरु गैनीनाथ जी ने हमें जो 'सस्यक अनन्यता दी' उससे हमारा कुल पवित्र हो गया।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 08 नवंबर, 1962

दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध प्रतिबंध लगाए जाएं

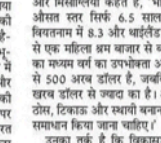

दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाए जायें जनरल ली

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव पारित कर सदस्य देशों से अनुरोध किया कि वे दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध आर्थिक व कूटनीतिक प्रतिबंध लागू करें, क्योंकि वह हर बार रंगभेद विरोधी प्रस्तावों की उपेक्षा करता रहा है।

थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है

प्रधानमंत्री मोदी भारत में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। लेकिन अगला वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने के लिए अभी कसर बाकी है।

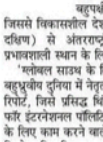

पत्रलेखा चटर्जी

विकास

हाल के वर्षों में पश्चिमी नेतृत्व वाली उदार व्यवस्था से असंतोष दुनिया भर में एक नारा बनकर उभरा है। कूटनीतिक गलियारों से लेकर अर्थव्यवस्था और सुरक्षा नीतियों तक बहुध्रुवीय मंचों में गिरावट आई है, जिससे विकासशील देशों या ग्लोबल साउथ (वैश्विक दक्षिण) से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर और अधिक प्रभावशाली स्थान के लिए आवाजें उठ रही हैं।

'ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिस्पर्धा: एशिया और एक बहुध्रुवीय दुनिया में नेतृत्व की खोज' शीर्षक से एक नई रिपोर्ट, जिसे प्रसिद्ध थिंक टैंक द इंटेलियस इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्टडीज (आईएसपीआई) के लिए काम करने वाले विद्वानों फिलिपो फासुलो और निकोला मिसाग्लिया द्वारा संपादित किया गया है, में कहा गया है, 'फिर भी, न तो ग्लोबल नॉर्थ और न ही ग्लोबल साउथ को एकीकृत ब्लॉक के रूप में देखा जा सकता है। सुधार का आह्वान अक्सर विभिन्न दिशाओं की तरफ खींचता है। इस विकसित होते परिदृश्य में भारत और चीन अग्रणी दावेदार के रूप में उभरे हैं, जिनमें से प्रत्येक एक अधिक संतुलित वैश्विक व्यवस्था को आकार देने की होड़ में लगा है।'

बेशक चीन और भारत, दोनों एक बेहद संतुलित विश्व व्यवस्था को आकार देने की होड़ में शामिल हैं, लेकिन यह चीन के लिए आसान नहीं होने वाला है, जो खुद को उदार लोकतंत्र के पारंपरिक पाश्चात्य मॉडल के विकल्प के रूप में स्थापित करना चाहता है। यह भारत के लिए भी आसान नहीं है, जिसका भू-राजनीतिक प्रभाव वैश्विक मंचों पर बढ़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व करने की भारत की कोशिश, उसकी विदेश नीति में नई दृढ़ता से उपजी है- यह आत्मविश्वास आर्थिक विकास और चीन के भू-राजनीतिक प्रतिबल तथा पश्चिम के लिए सेतु के रूप में उसकी बढ़ती हुई स्थिति से उत्पन्न हुआ है। फासुलो और मिसाग्लिया ने कहा, 'वैश्विक मंच पर भारत की विश्वसनीयता केवल चीन के साथ उसकी प्रतिद्वंद्विता पर निर्भर नहीं है। यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि भारत अपनी महत्वपूर्ण आंतरिक चुनौतियों का समाधान किस प्रकार करता है।'

वे बताते हैं कि 'नरेंद्र मोदी-जो 2024 में तीसरे कार्यकाल के लिए कम बहुमत के साथ पुनः निर्वाचित हुए हैं-ने भारत की नौकरशाही को आधुनिक बनाने और अक्षमताओं को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजिटल उपकरणों के प्रसार को बढ़ावा दिया है और यह कि भारत सरकार ने 'मेक इन इंडिया' अभियान के जरिये बुनियादी ढांचे, नियामक सुधार और घरेलू उत्पादन में महत्वपूर्ण निवेश भी किया है।' हालांकि भारत को वास्तव में नया चीन बनने (अगले वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने) के लिए अपनी मानव पूंजी में निर्णायक रूप से अधिक निवेश करना होगा।'

एक अरब से ज्यादा की आबादी वाले देश में कुछ भारतीय हमेशा बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कुछ लोगों ने हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया भी है। लेकिन किसी भी देश का भविष्य बहुसंख्यक लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर निर्भर करता है, केवल कुछ लोगों पर नहीं। इसलिए स्वास्थ्य, शिक्षा, उन्नत प्रशिक्षण, भारत के कार्यबल में महिलाओं का समावेशन ज्यादा महत्वपूर्ण है। खासकर इस गलाकाट प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित दौर में। फासुलो और मिसाग्लिया कहते हैं, 'भारत में स्कूली शिक्षा का औसत स्तर सिर्फ 6.5 साल है (इसकी तुलना में वियतनाम में 8.3 और थाईलैंड में 8.9 वर्ष है), तीन में से एक महिला श्रम बाजार से बाहर रहती है, और भारत का मध्यम वर्ग का उपभोक्ता आधार आश्चर्यजनक रूप से 500 अरब डॉलर है, जबकि वैश्विक बाजार 300 खरब डॉलर से ज्यादा का है। अगर भारत के उदय को ठोस, टिकाऊ और स्थायी बनाना है, तो इन चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिए।'

उनका तर्क है कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत ने लोकतांत्रिक प्रणाली के माध्यम से आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाया है, जो अपूर्ण होने के बावजूद मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश का लोकतंत्र 'सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषायी रूप से बहुल समाज में राजनीतिक विभाजन, अपकेंद्रित ताकतों और कभी-कभार होने वाली हिंसक घटनाओं को नियंत्रित करने में कामयाब रहा है।' स्पष्ट रूप से, भारत की कहानी इस बात पर निर्भर करती है कि देश अपनी बाहरी चुनौतियों के साथ-साथ आंतरिक चुनौतियों का भी कुशलतापूर्वक प्रबंधन करता है। आंतरिक संतुलन काफी हद तक सामाजिक सद्भाव पर निर्भर करेगा। भारत अपनी मौजूदा दरारों को और गहरा करने का जोखिम नहीं उठा सकता। 1947 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजाद होने के बाद से भारत ने बहुत कुछ हासिल किया है। लेकिन चैन से सोने से पहले हमें अभी बहुत कुछ करना है।

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • बृहस्पतिवार • 19 दिसम्बर • 2024
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

जीवन का उद्देश्य है कि उद्देश्य भरा जीवन हो।
-राबर्ट ब्राने

संबंधों की नई दिशाएं

श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने अपना पदभार संभालने के बाद सबसे पहले भारत की राजकीय यात्रा की जो न केवल दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और भौगोलिक निकटता को दर्शाता है, बल्कि कोलंबो के लिए नई दिल्ली के महत्व को भी दिखाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति दिसानायके के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य से पता चलता है कि दोनों देशों के बीच आने वाले दिनों में आर्थिक और राजनीतिक साझेदारी और अधिक मजबूत होगी। राष्ट्रपति दिसानायके ने प्रधानमंत्री मोदी को आश्वस्त किया कि वह श्रीलंका की भूमि का इस्तेमाल भारत के हितों के खिलाफ नहीं होने देंगे। हालांकि श्रीलंका की पूर्ववर्ती सरकारें भी इस तरह का आश्वासन

भारत को देती रही हैं, लेकिन राष्ट्रपति दिसानायके के आश्वासन का राजनीतिक महत्व ज्यादा है। दिसानायके की राजनीतिक पार्टी जनता विमुक्ति पेरामुना (जेवीपी) की विचारधारा वामपंथी झुकाव वाली है और इसे चीन समर्थक माना जाता है। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रीलंका के हंबनटोटा पोर्ट में चीन के जहाजों का खड़ा होना भारत की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। पूर्ववर्ती विक्रमसिंघे की सरकार ने चीनी जहाजों को आने पर रोक लगा रखी है, लेकिन अब इसकी मियाद पूरी होने वाली है। देखना है कि दिसानायके की सरकार भारत और चीन के बीच किस तरह संतुलन बना कर चलती है। पिछले दिनों जब श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तब भारत ने काफी सहयोग दिया था। अपनी इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति दिसानायके ने मुसीबत में भारत की सहायता का उल्लेख भी किया। हालांकि चीन ने भी श्रीलंका की मदद की है। वास्तव में श्रीलंका की भू-रणनीतिक स्थिति भारत और चीन, दोनों के लिए अहम है। कोलंबो में चीन और भारत, दोनों की कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं चल रही हैं। लेकिन राष्ट्रपति दिसानायके की भारत की यात्रा से स्पष्ट होता है कि वे द्विपक्षीय संबंधों में अपार संभावनाएं देख रहे हैं और इसे जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने व्यावहारिक कूटनीति पर बल दिया। दशकों से पारिवारिक पार्टियों के प्रभुत्व को तोड़ कर राष्ट्रपति बनने वाले दिसानायके के नेतृत्व वाले गठबंधन नेशनल पीपुल्स पॉवर (एनपीपी) को संसदीय चुनाव में दो तिहाई बहुमत प्राप्त हुआ है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस विराट जनादेश से दिसानायके भारत के साथ श्रीलंका के द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयां दे पाएंगे।

अवैध कब्जों की राजनीति

सुप्रीम कोर्ट ने बिना पूर्णता और अधिवास प्रमाणपत्र के फ्लैट या मकान पर कब्जा न देने का सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है। मानचित्र पास करते समय ही बिल्डर या प्लॉट के मालिक से इसका वचन-पत्र लिया जाए। इस प्रमाणपत्र के आधार पर ही बिजली-पानी, सीवर का कनेक्शन दिया जाए। बैंकों से भी कहा है कि स्वीकृत मानचित्र वाली प्रापर्टी पर ही कर्ज दिया जाए। उप्र के मेरठ के शास्त्री नगर में रिहाइशी प्लाट पर दुकानों के निर्माण पर सख्त कार्रवाई का आदेश देते हुए कई दुकानें ढहाने का आदेश भी शीर्ष अदालत ने दिया। अदालत ने 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को जायज बताते हुए कहा कि बिना आवास विकास के इंजीनियरों की मिलीभगत के इतने बड़े स्तर पर अवैध निर्माण संभव नहीं। अवैध कब्जों के प्रति सरकारी रवैया ढुलमुल रहा है। मकान पर कब्जा देने संबंधी जो निर्देश शीर्ष अदालत ने दिए, वे पहले भी नियमों में शामिल हैं। मगर सरकारी लापरवाही

और विभागों की मिलीभगत के चलते उनकी अनदेखी होती है। इसके लिए तत्कालीन सरकार भी अधिकारियों के साथ दोषी है। अवैध निर्माण को गिराना हमेशा समस्या का समाधान नहीं होता। तथाकथित अवैध मालिकान, जो इन प्रापर्टियों को अपना बता कर बेच गए, से वसूली कैसे होगी। क्या सारा खमियाजा सिर्फ वर्तमान अवैध मालिकों को भोगना होगा। आवास विकास परिषद भू-माफिया के साथ मिलीभगत कर सरकारी जमीनों पर साजिशन कब्जे करवाती है। जिन कब्जेदारों को जमीनें नियमित करवाने का प्रलोभन दे कर राजनीतिक दल अपने मकसदों में कामयाब होते हैं। बेशक, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को लेकर राजनीतिक दल अपने वोट बैंक को प्राथमिकता देकर ही बात करते हैं। निस्संदेह किन्हीं कारणों या आपसी झगड़ों के चलते यह मामला कानून की नजरों में आया होगा परंतु जिन तमाम जमीनों पर पुलों से अवैध कब्जे हैं, उन्हें मुक्त कराने के प्रति सरकारें लापरवाह क्यों हैं? उन्हें अपनी जमीनों का लेखा-जोखा सुव्यवस्थित रखने के प्रति जवाबदेह क्यों नहीं होनी चाहिए। उन अवैध कब्जेदारों को छूट मिलनी चाहिए जो कानून के शिकंजे से दूर रह गए हैं। सरकारी महकमों को अवैध कब्जों के प्रति जवाबदेह बनाने का जिम्मा अदालत ही निभा सकती है वरना तो खुद सरकारें हमेशा यूं ही आंखें मूंदे रहेंगी।

कटाक्ष/ सहीराम

दो पाले, दोनों अपने

जी वैसे तो संसद में पक्ष और विपक्ष होता है, जैसा कि लोकतंत्र का कायदा है। लेकिन इधर लगता है कि संसद में दो पाले हैं। एक में अडानी खड़े हैं और दूसरे में जॉर्ज सोरोस। अडानी क्योंकि अपने हैं यानी यहीं के हैं, लेकिन वास्तव में वो कहां के हैं यह कोई नहीं जानता। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं, जो उन्हें हिन्दुस्तान से ज्यादा गुजरात का ही मानते हैं, लेकिन क्या पता वो आस्ट्रेलिया के हों, केन्या के हों, बांग्लादेश के हों या हो सकता है श्रीलंका के ही हों, क्योंकि इन तमाम देशों में उनका धंधा है। जैसे वे दुनिया में हर कहीं के हैं, वैसे ही वे गुजरात के ही नहीं, आंध्र प्रदेश के भी, कर्नाटक के भी, बंगाल के भी और भी देश में न जाने कहां-कहां के हैं। फिर भी वे अपने हैं तो इसलिए उस पाले को राष्ट्रवाद का पाला माना जा रहा है। दूसरे पाले में जॉर्ज सोरास हैं, जो अमेरिका के हैं। लेकिन वे भी अडानी की तरह ही दुनिया में हर कहीं के हैं। सेठ लोग हर कहीं के होते हैं, उन पर विदेशी होने, घुसपैठिए होने, शरणार्थी होने का ठप्पा उस तरह से नहीं लगता है, जैसे लुटे-पिटे, उजड़े हुओं या रोजी-रोटी के लिए भटकने वाले लोगों पर लगते हैं। पर क्योंकि सोरोस अमेरिका के हैं तो उनके पाले को विदेशियों, देशद्रोहियों का पाला माना जा रहा है।

अब चूंकि दूसरे पाले वाले अडानी पर ही हमलावर थे, इसलिए उनके पाले वालों को इस बात का अफसोस था कि उस पाले में अडानी जैसा कोई तगड़ा बंदा क्यों नहीं है, जिस पर वे हमला कर सकें। उन्हें याद आया कि यार, हम तो इतने दिन से सोरोस का नाम रटते रहे हैं। अब क्यों भूल रहे हैं। सो, वे सोरोस को ले आए। दूसरे पाले वालों ने इस पर एतराज किया कि यार, हमारे पाले में इसे क्यों खड़ा कर रहे हो। इस पर पहले पाले वालों ने कहा कि बराबरी के लिए जरूरी है। बल्कि उन्होंने तो रेफरियों से भी हां करवा दी कि भाई, तुम्हें इनको अपने पाले में रख लेना चाहिए। हमें भी सुविधा होगी। एक तो बराबरी का खेल चलेगा, फिर लोग हमें भी कुछ श्रेय दे देंगे कि बड़ा अच्छा खेल खिलवा रहे हैं। बस उसके बाद से उधर वाले अडानी पर झपटते हैं और इधर वाले सोरोस पर। रेफरी लोग भी अडानी पर हमले को फाउल दे देते हैं और सोरोस पर हमले का मजा लेते हैं। आखिर, रेफरी लोग भी तो अपने ही हैं। इस तरह अडानी भी अपने, सोरोस और रेफरी भी अपने।

संतुलन बनाए रखना चुनौती

सुस्त विकास और महंगाई

डॉ. जयंतीलाल भंडारी

हाल में 12 दिसम्बर को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दर बीते महीने नवम्बर में 5.48 प्रतिशत रही। इससे पहले अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 6.21 प्रतिशत थी। इसी प्रकार नवम्बर में थोक मूल्य मुद्रास्फीति घट कर 1.89 प्रतिशत पर आ गई जो अक्टूबर में 2.36 प्रतिशत थी। यद्यपि महंगाई दर में कमी आई है, फिर भी अभी यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के महंगाई के निर्धारित दायरे से अधिक है।

गौरतलब है कि 11 दिसम्बर को आरबीआई के नवनियुक्त 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि वे महंगाई नियंत्रण और विकास दर के बीच उपयुक्त संतुलन बनाने की डगर पर आगे बढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था के लिए सर्वोत्तम काम करने की कोशिश भी करेंगे। गौरतलब है कि इस समय देश में धीमी विकास दर और महंगाई की चुनौती का परिदृश्य उभरता दिखाई दे रहा है। बीते दिनों राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि इसके पहले अप्रैल-जून की पहली तिमाही में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इस सुस्त विकास दर के परिदृश्य से प्रभावित हुए विना हाल में 6 दिसम्बर को आरबीआई ने मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में विकास दर बढ़ाने के लिए ब्याज दर में कमी नहीं करते हुए महंगाई नियंत्रण को प्राथमिकता दी है।

उल्लेखनीय है कि आरबीआई ने लगातार 11वीं बार ब्याज दर यानी नीतिगत दर (रेपो) में कोई बदलाव नहीं किया और इसे 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा। रेपो वह ब्याज दर है, जिस पर कमर्शियल बैंक अपनी तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई से कर्ज लेते हैं। आरबीआई मुद्रास्फीति को काबू में रखने के लिए इस दर का उपयोग करता है। हालांकि अर्थव्यवस्था में नकदी बढ़ाने के मकसद से आरबीआई ने कैश रिजर्व रेश्यो (सीआरआर) को 4.5 प्रतिशत से घटा कर चार प्रतिशत कर दिया। इस कदम से बैंकों में 1.16 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी उपलब्ध होगी। इससे बैंकिंग क्षेत्र में नकदी की स्थिति में सुधार होगा। ज्ञातव्य है कि सीआरआर के तहत कमर्शियल बैंकों को अपनी जमा का एक निर्धारित हिस्सा कैश रिजर्व के रूप में आरबीआई के पास रखना होता है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में आरबीआई ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 7.2 प्रतिशत पर घटा कर 6.6 प्रतिशत कर दिया है। आरबीआई ने चालू

वित्त वर्ष में खुदरा महंगाई के अनुमान को भी 4.5 प्रतिशत बढ़ा कर 4.8 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है।

आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास ने दिसम्बर, 2024 की मौद्रिक नीति के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में कहा था कि निकट भविष्य में, कुछ नरमी के बावजूद, खाद्य कीमतों पर दबाव बने रहने से चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में मुख्य महंगाई के ऊंचे स्तर पर बने रहने की संभावना है। उन्होंने कहा था कि महंगाई के मद्देनजर वैश्विक अर्थव्यवस्था में अभी व्हिड प्रतिफल में वृद्धि, जिंस कीमतों में उतार-चढ़ाव और बढ़ते भू-राजनीतिक जोखिम जैसी कई तरह की बाधाएं हैं। आयात शुल्क में वृद्धि और वैश्विक कीमतों में वृद्धि के बाद घरेलू खाद्य तेल की कीमतों की बदलती दिशा पर भी बारीकी से नजर रखने की जरूरत है।

दास ने कहा था कि रिकॉर्ड खरीफ उत्पादन के अनुमान से चावल और तुअर दाल की बढ़ी हुई कीमतों में राहत मिलेगी। सब्जियों की कीमतों में भी सुधार की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि आगे चल कर, खाद्य मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के लिए एक अच्छा रबी सीजन महत्वपूर्ण होगा। प्रारंभिक संकेत पर्याप्त मिट्टी की नमी और जलाशय के स्तर की ओर इशारा करते हैं, जो रबी की बुवाई के लिए अनुकूल हैं। ऐसे में चालू वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में विकास दर बढ़ने की उम्मीद है। निस्संदेह आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति समीक्षा के तहत महंगाई नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाना सही कदम है। वस्तुतः पिछले दो महीनों अक्टूबर-नवम्बर, 2024 में महंगाई दर के बढ़ने की स्थिति आश्चर्यचकित करने वाली रही है।

पिछले माह आरबीआई ने 2-11 नवम्बर, 2024 में परिवारों को महंगाई को लेकर कैसी उम्मीदें हैं, इस विषय पर सर्वेक्षण कराया था। आरबीआई के सर्वेक्षण से अंदाजा मिलता है कि सितम्बर, 2024 के चरण की तुलना में नवम्बर के सर्वेक्षण में शामिल प्रतिभागियों में एक बड़े वर्ग को लगता है कि नये साल 2025 में कीमतें और महंगाई, दोनों ही बढ़ेंगी। यह बढ़ोतरी मुख्य तौर पर खाद्य वस्तुओं और घर से जुड़े खर्चों के बढ़ते दबाव की वजह से होगी। इस बीच, उपभोक्ता आत्मविश्वास सर्वेक्षण से अंदाजा मिला है कि सर्वेक्षण के प्रतिभागियों की मौजूदा कमाई की धारणा में भले ही कमी आई हो लेकिन उन्हें इस बात की उम्मीद है कि भविष्य में आमदनी बढ़ेगी, रोजगार की स्थिति में भी सुधार आएगा। निस्संदेह खाद्य पदार्थों की महंगाई रोकने के लिए सरकार द्वारा तात्कालिक उपायों के साथ दीर्घकालीन उपायों पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी होगा।

इस समय ग्रामीण भारत में जल्द खराब होने वाले ऐसे कृषि उत्पादों की आपूर्ति शृंखला बेहतर करने पर प्राथमिकता से काम करना होगा, जिनकी खाद्य महंगाई के उतार-चढ़ाव में ज्यादा भूमिका होती है। ऐसे में सरकार को खाद्य उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ कृषि उपज की बर्बादी रोकने के बहुआयामी प्रयासों के तहत खाद्य भंडारण और वेयरहाउसिंग की कारगर व्यवस्था की डगर पर बढ़ना होगा। उम्मीद करें कि आरबीआई के नये गवर्नर संजय मल्होत्रा सरकार के साथ आरबीआई के विभिन्न समन्वित रणनीतिक प्रयासों से महंगाई को नियंत्रित करने और सुस्त विकास दर को बढ़ाने के परिप्रेक्ष्य में नई रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे। इससे आरबीआई के लक्ष्य के मुताबिक, खुदरा महंगाई दर चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 4.5 प्रतिशत तथा आगामी वित्त वर्ष 2025-26 में चार प्रतिशत के दायरे में रहते हुए दिखाई दे सकेगी।

(लेख में विचार निजी हैं)

पिछले माह आरबीआई ने 2-11 नवम्बर, 2024 में परिवारों को महंगाई को लेकर कैसी उम्मीदें हैं, इस विषय पर सर्वेक्षण कराया था। आरबीआई के सर्वेक्षण से अंदाजा मिलता है कि सितम्बर, 2024 के चरण की तुलना में नवम्बर के सर्वेक्षण में शामिल प्रतिभागियों में एक बड़े वर्ग को लगता है कि 2025 में कीमतें और महंगाई, दोनों ही बढ़ेंगी। यह बढ़ोतरी मुख्य तौर पर खाद्य वस्तुओं और घर से जुड़े खर्चों के बढ़ते दबाव की वजह से होगी

'इंडिया इन फ्यूचर टेंस' के लिए 47 शब्दों की पहचान

- 'जुगाड़', 'क्यू कार्वन', 'कल्चरलॉमिक्स', 'डिजिटल नोमैड' और '15-मिनट सिटी' उन 47 शब्दों में शुमार हैं, जिन्हें नये शब्दकोश 'इंडिया इन फ्यूचर टेंस : 47 वर्ड्स फॉर 2047' में जगह मिली है
- इस शब्दकोश में उन प्रमुख 'ट्रेंड्स' से जुड़े शब्द शामिल हैं, जो भारत के 100 वर्ष पूरे होने पर 2047 में महत्वपूर्ण होंगे
- यह शब्दकोश 'नेक्स्ट जेनरेशन इंडिया कोलोज' की पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को 2047 तक एक स्थायी और समृद्ध भारत को आकार देने के लिए आवश्यक ज्ञान और भाषा से सशक्त बनाना है

(स्रोत : मीडिया इन्पुट्स)

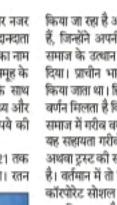

एक देश-एक चुनाव वाले विधेयक को मुसलमान विरोधी बताया जा रहा है। अब मुसलमान का इस विधेयक से क्या नुकसान है, यह समझ नहीं आ रहा है?

अमिताभ अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार
@Aamitabh2

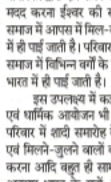

मान्यता

प्रह्लाद सबनानी

दान करने से होता है गरीब कल्याण

भारत में हिन्दू सनातन संस्कृति के संस्कारों में दान-दक्षिणा की प्रथा का अलग ही महत्व है। भारत में विभिन्न त्यौहारों एवं महापुरुषों के जन्म दिवस पर मठों मंदिरों, गुरुद्वारों एवं अन्य पूजा स्थलों पर समाज के संपन्न नागरिकों द्वारा दान करने की प्रथा अति प्राचीन है। गरीब की मदद करना ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा माना जाता है। समाज में आपस में मिल-बांट कर खाने-पीने की प्रथा भारत में ही पाई जाती है। परिवार में किसी भी खुशी की घटना को समाज में विभिन्न वर्गों के बीच आपस में बांटने की प्रथा भी भारत में ही पाई जाती है।

इस उपलक्ष्य में कई बार तो बड़े स्तर पर सामाजिक एवं धार्मिक आयोजन भी किए जाते हैं। जन्म दिन मनाना, परिवार में शादी समारोह के पश्चात नाते-रिश्तेदारों, दोस्तों एवं मिलने-जुलने वालों को विशेष आयोजनों में आमंत्रित करना आदि बहुत ही सामान्य चलन है। एक अनुमान के अनुसार भारत के मठों, मंदिरों, गुरुद्वारों एवं अन्य पूजा स्थलों पर प्रति दिन 10 करोड़ से अधिक लोगों को प्रसाद के रूप में भोजन वितरित किया जाता है। पूरी दुनिया में भारत ही ऐसा देश है, जिसमें निवासरत नागरिक, चाहे वह कितना भी गरीब क्यों न हो, अपनी कमाई में से कुछ राशि का दान तो जरूर करता है। भारतीय शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि हिन्दू सनातन संस्कृति के अनुरूप महर्षि दधीच ने तो देवताओं को असुरों पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने शरीर को ही दान में दे दिया था, जिसे इतिहास में उच्चतम बलिदान की संज्ञा दी जाती है।

आज के युग में जब अर्थ को अत्यधिक महत्व मिल रहा है, तब अधिक से अधिक धन का दान करना ही शुभ कार्य माना जा रहा है। इस दृष्टि से वैश्विक स्तर पर नजर डालने पर ध्यान में आता है कि दुनिया में सबसे बड़े दानदाता के रूप में भारत के टाटा उद्योग समूह के रतन टाटा का नाम सबसे ऊपर उभर कर आता है। इस सूची में टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा का नाम भी सम्मान के साथ लिया जाता है, जिन्होंने अपने जीवन में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में 8.29 लाख करोड़ रुपये की राशि का महादान किया था।

रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने वर्ष 2021 तक 8.59 लाख करोड़ की राशि का महादान किया था। रतन

टाटा केवल भारत स्थित संस्थानों को ही दान नहीं देते थे बल्कि वैश्विक स्तर पर समाज की भलाई के लिए कार्य कर रहे संस्थानों को भी दान देते थे। रतन टाटा के पूर्वज पारसी समुदाय से थे और ईरान से आकर भारत में रच-बस गए थे। रतन टाटा ने न केवल भारतीय हिन्दू सनातन संस्कृति के संस्कारों को अपने जीवन में उतारा, बल्कि इन संस्कारों का अपने जीवनकाल में अक्षरशः अनुपालन भी किया। टाटा समूह का वर्णन तो यहां केवल उदाहरण के रूप में किया जा रहा है अन्यथा भारत में ऐसे कई औद्योगिक घराने हैं, जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति को ही ट्रस्ट के माध्यम से समाज के उत्थान एवं समाज की भलाई के लिए दान में दे दिया है। प्राचीन भारत में यह कार्य राजा-महाराजाओं द्वारा किया जाता था। हिन्दू सनातन संस्कृति के विभिन्न शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि ईश्वर ने जिसको संपन्न बनाया है, उसे समाज में गरीब वर्ग की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। यह सहायता गरीबों को सीधे उपलब्ध कराई जा सकती है अथवा ट्रस्ट की स्थापना कर भी उनकी मदद की जा सकती है। वर्तमान में तो निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर-कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी) के संबंध में कानून ही बना दिया गया है। जिन कंपनियों की संपत्ति 500 करोड़ रुपये से अधिक है अथवा जिन कंपनियों का वार्षिक व्यापार 1000 करोड़ रुपये से अधिक है अथवा जिन कंपनियों का वार्षिक शुद्ध लाभ 5 करोड़ से अधिक है, उन्हें इस कानून के अंतर्गत अपने वार्षिक शुद्ध लाभ के दो प्रतिशत की राशि का उपयोग समाज की भलाई के लिए चलाई जा रही परियोजनाओं पर खर्च करना आवश्यक होता है। इन विभिन्न मदों पर खर्च की जाने वाली राशि का प्रति वर्ष अंकेक्षण भी कराना होता है, ताकि जाना जा सके राशि का उपयोग समाज की भलाई के लिए किया गया है एवं इसका दुरुपयोग नहीं हुआ है।

भारत में गरीब वर्ग/परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने में संपन्न वर्ग द्वारा किए जाने वाले दान आदि की राशि से भी बहुत मदद मिलती है। सीएसआर के अंतर्गत चलाई जा रहीं विभिन्न योजनाओं का सीधा लाभ भी समाज के गरीब वर्ग को मिलता है। अतः विश्व में शायद भारत ही ऐसा देश है जहां सरकार एवं समाज मिल कर गरीब वर्ग की भलाई हेतु कार्य करते दिखाई देते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि हिन्दू सनातन संस्कृति का विस्तार यदि वैश्विक स्तर पर होता है, तो पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है एवं बहुत संभव है कि वैश्विक स्तर पर गरीबी का नाश होकर चहुं ओर खुशहाली फैलती दिखाई दे।

कूर्म शिक्षा

डॉ. ज्ञानानंद दास

मनुष्य देह की प्रवृत्ति मायिक संसार के भोग की तरफ होना स्वाभाविक है, क्योंकि यह देह ही मायिक है। विभिन्न आकर्षक विषयों का आनंद लेने में सारा संसार एक ही धारा में तना हुआ है किंतु इसका अंतिम परिणाम दुःख है, और सभी को इसका न्यूनाधिक अनुभव भी होता है। फिर भी लोग इस प्रकार विषय वासना के वशीभूत होकर कष्ट भोगते हैं। क्या इस जाल से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं? इसका उपाय भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं-जब कोई व्यक्ति कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को (आकर्षण के विषयों से) पूरी तरह खींच लेता है, तो उसकी प्रज्ञा स्थिर और सुदृढ़ हो जाती है। कछुआ अपनी सुरक्षा और आवश्यकता के अनुसार अपने अंगों को खोलता और समेटता है। इसी तरह, मनुष्य को भी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए उन्हें केवल उचित समय और परिस्थितियों में उपयोग करना चाहिए। उसी तरह हमें भी अपनी इच्छाओं और इंद्रियों को नियंत्रित करना सीखना चाहिए ताकि वे हमारा ध्यान लालसा और आसक्ति की तरफ भटकाए नहीं। इसके साथ ही जैसे कछुआ बाहरी खतरों से बचने के लिए अपने अंगों को भीतर समेटता है, वैसे ही हमें भी लोभ, मोह, क्रोध और भोग-विलास जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों से बचने के लिए अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। इस प्रकार हम जीवन में संयम और आत्म-नियंत्रण को उतार सकते हैं, और स्थिर, शांत और सफल जीवन जी सकते हैं। आज हर इंसान किसी न किसी तरह के तनाव का अनुभव कर रहा है क्योंकि इंद्रिय सुखों की प्राप्ति से मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता। इसलिए भगवान श्रीकृष्ण कछुए का दृष्टांत देकर अर्जुन को संयम, नियम, और त्याग का पाठ पढ़ा रहे हैं। महंत स्वामी महाराज समझाते हैं-मनुष्य की पांच इंद्रियां होती हैं। त्वचा, श्रवण, आंख, जीभ और नाक। इन इंद्रियों के मुख्य पांच विषय भी हैं-स्पर्श, शब्द, रूप, रस और गंध। इन विषयों का अत्यधिक लोभ, मोह, और अहंकार जैसे विकारों को जन्म देता है, जो व्यक्ति को आध्यात्मिक और मानसिक रूप से कमजोर करते हैं। इसीलिए भगवान श्रीकृष्ण इंद्रियों को कछुए की तरह अपने कवच में बंद करके नियमित संयम का उपदेश देते हैं।

रीडर्स मेल

बेवहज है ईवीएम पर विवाद

जब विपक्ष किसी जगह चुनाव हारता है, वह अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर थोप देता है। इसके जवाब में सत्ता पक्ष का भी घिसा-पिटा जवाब आता है कि विपक्ष जीत गया तो मशीन ठीक। हार गए तो मशीन खराब। यही ईवीएम मशीन विवाद का विषय रही है, और सरकार विरोधी दलों के विरोध के बाद भी अपनी चलाती है। जम्मू-कश्मीर में जहां विरोधी दल की सरकार है, उसने ईवीएम मशीन को ठीक बताया और कांग्रेस को नसीहत दी कि वह ईवीएम मशीन का विरोध बंद करे। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री की बात यूं ही हजम नहीं होती। जहां विपक्षी दल की सरकारें हैं, वे केंद्र की सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ कैसे बोलें। केंद्र सरकार और विपक्षी राज्य सरकारों का छत्तीस का आंकड़ा रहता है। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री पूर्ववर्ती विरोधी राज्य सरकारों के पतन देख चुके हैं। उन्हें भी केंद्र सरकार से डर लग रहा है। इसलिए वे मोदी स्वर में बोल रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि ईवीएम का मुद्दा अनंतकाल तक कायम नहीं रहना चाहिए। जरूरी है कि सरकार पहल करके आम सहमति बनाने के प्रयास करे।

दिलीप गुप्ता, छोटी बमनपुरी, बरेली

दिल्ली बनी 'गैस चैंबर सिटी'

इस साल ठंड ने थोड़ी देरी से दस्तक दी। इससे दिल्ली वालों की परेशानी दोगुनी हो गई क्योंकि हर साल अक्टूबर-नवम्बर-दिसम्बर में फैलने वाला प्रदूषण अपने समय पर ही था। दिल्लीवासियों की जिंदगी आज के समय में किसी गैस चैंबर में फंसे कैदी की तरह हो गई है। एक तरफ ठंड की मार लोगों को जीने नहीं दे रही है, तो दूसरी तरफ, प्रदूषण के कारण लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। दीपावली के बाद हालांकि ठंड और कोहरे के साथ लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, क्योंकि वायु की गुणवत्ता 450 के पास पहुंच गई थी। बीच में थोड़ी हवा और मौसम के एकदम करवट लेने के बाद लोगों को प्रदूषण से राहत मिली थी। लेकिन, अब एक बार फिर से प्रदूषण अपने पैर पसार रहा है। दूसरी तरफ, ठंड भी लगातार बढ़ रही है, जहां न्यूनतम तापमान एकल अंक में पहुंच गया है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार को प्रदूषण के खिलाफ कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। थोड़े समय के लिए प्रतिबंध लगाना दिल्ली जैसी 'गैस चैंबर सिटी' के लिए काफी नहीं है।

अंकित श्वेताभ, नई दिल्ली

बनी हुई है अखबारों की जरूरत

यद्यपि की आज मोबाइल का दौर है। लोग सभी तरह की सूचनाएं तुरंत पा लेते हैं। हर एक बच्चे के घर में भी मोबाइल और टीवी की उपलब्धता होती है, इन सबके बावजूद बच्चे अपने पाठ्य पुस्तक के साथ-साथ समाज और देश-दुनिया की गतिविधियों से रूबरू होते रहें और शुद्ध-शुद्ध पढ़ने की क्षमता का विकास हो, इसके लिए आवश्यक है कि वो समाचार पत्र का भी अवलोकन करते रहें, इसके लिए आंत आवश्यक है कि कम से कम सभी विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर दो-तीन समाचार पत्र जरूर उपलब्ध होने चाहिए ताकि विद्यार्थी को सहायता से यह उपलब्ध हों और वे इनसे अपने ज्ञान और सूचना में वृद्धि कर सकें।

मिथिलेश कुमार, भागलपुर
letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया आबदी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सहारा सदन, नवभारत टाइम्स, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश सिंह* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
वर्ष-34, अंक 123
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी पहलुओं के लिए उत्तरदायी

कल्पमेधा

चालबाज और धूर्त को सबसे अधिक बेचैनी उस समय होती है, जब उसका पाला किसी सच्चे आदमी से पड़ता है।

- कोल्टन

चुनाव का वक्त

एक राष्ट्र एक चुनाव मौजूदा केंद्र सरकार का महत्त्वाकांक्षी विचार है। यह नारा उसने अपने पिछले कार्यकाल में ही दिया था। मगर इसे लेकर विरोध शुरू हो गया और विपक्षी दलों ने न केवल इसे अव्यावहारिक, बल्कि असंवैधानिक भी करा दिया था। सरकार ने इस पर विचार और सुझाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुआई में एक समिति गठित कर दी। उस समिति के गठन पर भी सवाल उठे कि उसके सदस्यों के पास अपेक्षित योग्यता नहीं है। मगर समिति ने विभिन्न दलों से बातचीत की, जिसमें से अनेक दलों ने इस विचार का विरोध किया था, फिर भी समिति ने सुझाव दिया कि देश में सभी चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। इसके पीछे बड़ा तर्क है कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव अलग-अलग समय पर कराए जाने से धन और समय की काफी बर्बादी होती है। इस तर्क को खारिज करने के लिए भी अनेक उदाहरण और तर्क पेश किए गए। मगर सरकार ने इससे संबंधित दो विधेयक संसद में पेश कर दिए। एक विधेयक एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर था और दूसरा केंद्र और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान में संशोधन से संबंधित था।

संविधान संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में सत्तापक्ष को दो तिहाई बहुमत की जरूरत थी। वह नहीं मिल पाया और स्वाभाविक रूप से दोनों विधेयक पारित नहीं हो सके। अब सरकार ने इन विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति के पास समीक्षा के लिए भेजने का फैसला किया है। निस्संदेह यह संवैधानिक दृष्टि से संवेदनशील मुद्दा है और इसे आनन-फानन पारित करा लेने से आने वाले वक्त में कई तरह की जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अलग-अलग चुनाव होने से न केवल खर्च कुछ अधिक होता है, बल्कि निर्वाचन आयोग और सरकार के कामकाज में भी बाधाएं आती हैं। मगर ऐसा करने के लिए जिन सरकारों का कार्यकाल बढ़ाना या घटाना पड़ेगा, उससे संवैधानिक मूल्यों को ठेस पहुंचने का खतरा रहेगा ही। फिर, यह भी कोई गारंटी नहीं कि कहीं मध्यावधि चुनाव की नौबत नहीं आएगी। उस स्थिति में कब तक सरकार का काम मुल्तवी रखा जाएगा। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लंबे समय तक किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए रखना अच्छी बात नहीं होती।

एक राष्ट्र एक चुनाव संबंधी विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को सौंपने का फैसला उचित है। मगर इसके बावजूद यह अपेक्षा बनी रहेगी कि समिति के समक्ष निष्पक्ष तरीके से बहसें हों, तर्क और सुझाव रखे जाएं। सरकार उन सुझावों को उदारतापूर्वक स्वीकार करे। क्योंकि पिछले कुछ समय से संयुक्त संसदीय समिति के सामने रखे गए कुछ मामले विवादों में देखे गए हैं। उन पर हुई बहसें सवालों के घेरे में रही हैं, विपक्षी सदस्य उन पर सत्तापक्ष की मनमानियों के आरोप लगा कर खुद को अलग करते देखे गए हैं। एक साथ चुनाव कराने संबंधी विधेयक को सरकार अगर हार-जीत का मसला न बनाए और अपना हठ छोड़ कर थोड़ा लचीला रुख अपनाएगी, तभी कोई सार्थक नतीजा निकलने की उम्मीद बन सकती है। वैसे ही चुनाव प्रक्रिया पिछले कुछ समय से सवालों के घेरे में है, सरकार को अगर सचमुच धन और समय की बर्बादी की चिंता है, तो उसके दूसरे भी व्यावहारिक उपाय जुटाए जा सकते हैं।

सार्थक कदम

राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी (एनटीए) में सुधार की दिशा में सार्थक पहल हुई है। अपने गठन से लेकर अभी तक पर्चाफोड़ सहित कई विवादों में रही एनटीए अब केवल उच्च शिक्षा प्रवेश परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री की घोषणा के बाद उम्मीद बनी है कि इससे न केवल परीक्षार्थियों की शिकायतें कम होंगी, बल्कि अनावश्यक विवाद भी नहीं उठेंगे। पहले कई परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी खामियां सामने आई थीं। वहीं मेडिकल में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के प्रश्नपत्र लीक होने और दूसरी अनियमितताओं के कारण कई परीक्षाएं रद्द कर दी गई थीं। इस पर न केवल सवाल उठे, बल्कि लाखों परीक्षार्थियों का भरोसा भी टूटा था। एनटीए की साख भी धूमिल हुई थी। केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा शुरू करने में देरी पर समय की भरपाई के लिए कृपांक देने के मामले में भी भारी विवाद हुआ था। तब एजंसी को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। तमाम गड़बड़ियों की वजह से ही एजंसी के महानिदेशक को हटाना पड़ा था। इसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी के कामकाज में सुधार को लेकर कवायद शुरू हुई। यह अच्छी बात है कि अब एनटीए भर्ती परीक्षाएं आयोजित नहीं करेगी। अगले वर्ष से वह खुद को सिर्फ प्रवेश परीक्षाओं तक सीमित रखेगी। निश्चित रूप से यह एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

दरअसल, राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी में सुधार के लिए जो उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी, उसने अपनी रपट सरकार को सौंप दी है। इसके बाद ही सरकार ने बड़ा कदम उठाया। अब न केवल राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी के पुनर्गठन के रास्ते खुलेंगे, बल्कि इसकी कार्यशैली भी बदलेगी। इसका लाभ अंततः परीक्षार्थियों को ही मिलेगा। इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि नए कदम से एजंसी की परीक्षा व्यवस्था पुख्ता होगी, जिसे लेकर संसद से लेकर सड़क तक सवाल उठते रहे हैं। चूंकि बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो संभव है तकनीकी आधारित परीक्षा आयोजित करने की दिशा में भी बड़े कदम उठाए जाएं। फिलहाल उम्मीद की जा सकती है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी अपने गठन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पारदर्शिता और शुचिता कायम करने के दिशा में कदम बढ़ाएगी।

मशीन से भावनात्मक जुड़ाव के खतरे

एआइ तकनीक क्रांतिकारी है। इसकी बदौलत बहुत कुछ सरल होने लगा है। घंटों के काम चुटकी बजाते होने लगे हैं, लेकिन क्या एआइ के साथ भावनात्मक जुड़ाव और उसे वास्तविक संबंध समझने वाले लोगों को जागरूक करना जरूरी नहीं है?

अमरपाल सिंह वर्मा

हाल में अमेरिका के फ्लोरिडा में एक किशोर ने खुदकुशी कर ली। कहा गया कि वह कृत्रिम मेधा (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआइ) के 'मोह' में डूबा था। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बच्चे की मां का कहना है कि एआइ ने उनके बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाया। उन्होंने एआइ कंपनी के खिलाफ आरलैंडो की संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया है। इसमें मां ने दावा किया है कि एआइ ने उनके बेटे को 'यौन केंद्रित और यथार्थवादी बातचीत' का अनुभव कराया, जिसके परिणामस्वरूप उसे चैटबाट से गहरा लगाव हो गया।

इस घटना से मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी (एमआइटी) के एक मनोवैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता शेरी तुर्कले की पांच महीने पहले दी गई चेतावनी याद आई। उन्होंने कहा था कि इंसानों को एआइ के साथ लगाव से बचना चाहिए। तुर्कले ने इंसान और 'एआइ चैटबाट' के बीच भावनात्मक संबंध पर अपने शोध में कहा था कि एआइ सिर्फ दिखावा करता है और वह आपकी परवाह नहीं करता। तुर्कले ने यह चेतावनी कई कारणों से दी थी, जो एआइ के साथ गहरे भावनात्मक संबंध स्थापित करने से उत्पन्न हो सकती है। अब चौदह वर्ष के एक लड़के के आत्महत्या कर लेने की घटना काफी कुछ सोचने पर मजबूर करती है।

एआइ को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। जहां एआइ के लाभ गिनाए जा रहे हैं, वहीं अंदेशा जताया जा रहा है कि यह लोगों को बेरोजगार कर देगा। इसी के साथ-साथ यह आशंका भी उठ रही है कि एआइ लोगों को भ्रम जाल में फंसा रहा है। इससे बचने के उपाय किए जाने चाहिए। वहां खुदकुशी करने वाले बच्चे की मां के दावे पर गौर किया जाना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि कंपनी ने अपने चैटबाट को एक वास्तविक व्यक्ति, एक लाइसेंस प्राप्त मनोचिकित्सक और एक वयस्क प्रेमी या प्रेमिका के रूप में डिजाइन किया। बच्चे ने चैटबाट के साथ एक मजबूत भावनात्मक संबंध बना लिए। मुकदमे में मां ने दावा किया है कि उसका बेटा चैटबाट से 'प्यार' करता था और उसके साथ यौन क्रिया-कलाप संबंधी संवाद करता था। बच्चे ने कई बार चैटबाट को अपने आत्मघाती विचारों से भी अवगत कराया।

इस घटना ने उन आशंकाओं को बल प्रदान किया है, जो एआइ के बारे में व्यक्त की जा रही हैं। संजीदा लोग इस घटना से चिंतित हैं और उनमें इस पर व्यापक विमर्श चल रहा है। यह संवेदनशील मुद्दा है। कई बार अकेलेपन या भावनात्मक जरूरतों के कारण लोग एआइ को एक साथी की तरह देखना शुरू कर देते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि 'एआइ चैटबाट' स्वाभाविक और सहायक बातचीत करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे लोग उनके साथ सहज महसूस कर सकते हैं। हालांकि, यह एकतरफा और गैर-मानवीय संबंध होता है, क्योंकि एआइ भावनाओं को महसूस नहीं कर सकता।

विश्व में इस विषय पर शोध हो रहा है, नैतिक बहस भी चल रही है कि इस तरह के संबंध लोगों की मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं। मगर सवाल उठता है कि इस स्थिति के लिए लोग दोषी हैं या एआइ तकनीक?

यकीनन, एआइ तकनीक क्रांतिकारी है। इसकी बदौलत बहुत कुछ सरल होने लगा है। घंटों के काम चुटकी बजाते होने लगे हैं, लेकिन क्या एआइ के साथ भावनात्मक जुड़ाव और उसे वास्तविक संबंध समझने वाले लोगों को जागरूक करना जरूरी नहीं है? कई लोगों का अपनी भावनात्मक जरूरतों के कारण तकनीक के साथ असामान्य रूप से जुड़ जाना संभव है। अगर उनका मानसिक स्वास्थ्य कमजोर हो, तो एआइ को वास्तविक साथी समझने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। जानकारों का कहना है कि कुछ लोग एआइ को ऐसे तरीकों से इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए यह डिजाइन नहीं किया गया है। यह गलतफहमी या अत्यधिक निर्भरता कई जटिलताओं को जन्म दे सकती है। वर्तमान में लोग व्यस्त हो गए हैं और अलग-थलग पड़े हुए हैं। सोशल मीडिया के कारण लोग पहले ही स्वयं को वास्तविक रिश्तों की तुलना में आभासी दुनिया में अधिक आरामदायक महसूस कर रहे हैं। ऐसे में इंसान-सा व्यवहार करने वाला एआइ लोगों को और अलग-थलग कर देगा। लिहाजा, इस खतरे से आंखें मूंद लेने की समझदारी नहीं कहा जा सकता है।

> **कई बार अकेलेपन या भावनात्मक जरूरतों के कारण लोग एआइ को एक साथी की तरह देखना शुरू कर देते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि 'एआइ चैटबाट' स्वाभाविक और सहायक बातचीत करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे लोग उनके साथ सहज महसूस कर सकते हैं। हालांकि, यह एकतरफा और गैर-मानवीय संबंध होता है, क्योंकि एआइ भावनाओं को महसूस नहीं कर सकता। विश्व में इस विषय पर शोध हो रहा है, नैतिक बहस भी चल रही है कि इस तरह के संबंध लोगों की मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं। मगर सवाल उठता है कि इस स्थिति के लिए लोग दोषी हैं या एआइ तकनीक?**

वर्तमान में अकेलापन बढ़ने से लोगों का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। विश्व में एक बड़ी आबादी अकेलेपन का शिकार हो चुकी है। इसकी वजह से बहुत से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम सामने आए हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) भी अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरे के रूप में वर्गीकृत कर चुका है। वर्ष 2022 में जारी एक अन्य अध्ययन रपट के अनुसार भारतीय युवाओं में अकेलेपन की बढ़ती समस्या चिंताजनक है। पैंतालीस वर्ष की उम्र के करीब 20.5 फीसद वयस्क अकेलेपन के शिकार हैं, जिससे उनमें विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। अकेलेपन के शिकार लोग अपनी व्यथा सुनाने के लिए एआइ की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि एआइ से उन्हें किसी इंसान से बात करने जैसा ही अहसास होता है। यही कारण है कि उनका आभासी दुनिया से जुड़ाव बढ़ रहा है, लेकिन वास्तविक दुनिया से वे दूर होते जा रहे हैं।

मानसिक बीमारियां पहले ही विश्व भर में बड़ी समस्या बनी हुई हैं। एआइ के कारण भविष्य में लोगों का मानसिक स्वास्थ्य और अधिक प्रभावित होने का अंदेशा है। मगर सवाल है कि इस खतरे से निपटा कैसे जाए? अब जरूरी है कि विशेष रूप से अभियान चला कर एआइ से जुड़े खतरों के बारे में लोगों को आगाह किया जाए। जब तक सचेत नहीं किया जाएगा, लोग एआइ का समझदारी से उपयोग करना जरूरी नहीं समझेंगे। इसके साथ-साथ एआइ निर्माताओं के लिए तकनीक के उपयोग की सीमाएं स्पष्ट करना भी अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। निर्माताओं के लिए यह जरूरी हो कि वे एआइ को इस तरह डिजाइन करें, जिससे उससे जुड़ने वाले लोग भावनात्मक रूप से अस्वस्थ स्थिति में पहुंचने से बच सकें।

भावनात्मक समस्याओं का हल तकनीक में नहीं, बल्कि इंसानी रिश्तों और मदद में है, लोगों को यह बात समझानी होगी। सरकारों को ऐसे संवदेनशील मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए और एआइ के उपयोग के लिए नीति बना कर दिशा-निर्देश तैयार करना चाहिए। इसके लिए अभी समय है, क्योंकि फिलहाल, एक बड़े वर्ग की एआइ तक अब भी पहुंच नहीं बन पाई है। मगर अब तो हर हाथ में स्मार्ट फोन है, इसलिए वह दिन दूर नहीं, जब प्रत्येक व्यक्ति एआइ का इस्तेमाल करने लगेगा। जब तक ऐसा हो, उससे पहले लोगों को जिम्मेदारी से तकनीक का इस्तेमाल करना सिखाना ही होगा। लोगों को बताना होगा कि एआइ एक मशीन है और इंसानों को उससे वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वे अब तक मशीनों के साथ करते आ रहे हैं।

लोक से विमुख लोग

गिरीश पंकज

हमारा भारतीय समाज लोकानुरागी रहा है। लोक उसकी आत्मा का हिस्सा रहा। लोक के आलोक में ही उसका जीवन दीप्त होता था। लेकिन धीरे-धीरे शहरीकरण ने लोक को हाशिये पर धकेल दिया है। इसका दुष्परिणाम समाज भोग रहा है। हम सब जानते हैं कि लोक का भोजन अमृत रहा है, क्योंकि उसमें शुद्धता की गारंटी हुआ करती थी। आज भी बहुत हद तक वहां शुद्धता बची हुई है। जबकि अनुभव यही बताता है कि शहरी भोजन अब जहर बनता जा रहा। सांसों में घुलता विषैला धुआं और खानपान में मिलावट शहरी जीवन का दुष्परिणाम हो गया है। लोक में रहने वाला समाज सहज रूप से शुद्ध प्रकृति के साथ रहता है।

चतुर्दिक पसरी हरियाली और नदी-तालाब की समृद्धि, तन-मन दोनों को स्वस्थ बनाए रखती है। इधर कभी प्रकृति के संग रहने वाला नागर समाज अब धीरे-धीरे प्रकृति का दुश्मन होता जा रहा है। जबकि सभी जीव प्रकृति के साथ मजे से रहते हैं। तथाकथित विकास के नाम पर मनुष्य पेड़ काट रहा है। वह एक तरह से 'कालिदास' बना हुआ है। जिस डाल पर बैठा है, उसे ही काटे जा रहा। लोग नदी को प्रणाम तो करते हैं, पर तुरंत प्रदूषित भी करने लगते हैं। कुछ तो इतने चेतना-शून्य हो जाते हैं कि उनके कारखाने का दूषित जल सीधे जीवनदायिनी नदी में समाता रहता है। तंत्र भी इसकी अनदेखी करता है।

मनुष्य सुंदर विशाल पहाड़ों को खोद रहा है। उसके दुष्परिणाम भी भोग रहा है। फिर भी वह सबक ग्रहण नहीं करता। पहले कहावत थी कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की ओर भागता है। अब गीदड़ की जगह मनुष्य शब्द का प्रयोग करना चाहिए। धीरे-धीरे अपने ही गांव से मनुष्य का मोह भंग हो रहा है। गांव में गाय पालने वाला व्यक्ति शहर आकर कुत्ते पालने लगता है। यह अजीब-सा बदलाव है। गांव का आदमी शहर की ओर भाग रहा है और यहां कुचल कर मर रहा है, बीमार पड़ रहा है। गांव में रहते हुए जिस व्यक्ति के फेफड़े दुरुस्त थे, शहर में आकर वही फेफड़ा प्रदूषण का केंद्र बन गया है। पूरा शरीर बीमारियों का घर बनता जा रहा है।

दुनिया मेरे आगे

> **गनीमत है कि अभी भी गांव की बची-खुची आबादी शहरी व्यामोह में नहीं फंसी। आज भी सुदूर गांवों या वनप्रांतर में कुछ ऐसे लोग या समूह निवास कर रहे हैं, जो शहरी जीवन से कोई संपर्क ही नहीं रखना चाहते। वे सब अपनी दुनिया में मगन हैं, यानी प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं।**

गनीमत है कि अभी भी गांव की बची-खुची आबादी शहरी व्यामोह में नहीं फंसी। आज भी सुदूर गांवों या वनप्रांतर में कुछ ऐसे लोग या समूह निवास कर रहे हैं, जो शहरी जीवन से कोई संपर्क ही नहीं रखना चाहते। वे सब अपनी दुनिया में मगन हैं, यानी प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे गांव से गंवईपन गायब होता जा रहा है, उसी तरह साहित्य से भी लोक-विमर्श धीरे-धीरे गायब होता जा रहा है। उसकी जगह महानगरीय जीवन और उसके संक्रमण केंद्र में आते जा रहे हैं। कहानी, कविताओं में, उपन्यासों में गांव की सोंधी खुशबू गायब है। अब जो नया साहित्य रचा जा रहा है, उसमें नग्नता की खुली चकालत है। नैतिकता अब चलन से बाहर मान ली गई है और आधुनिक होने की परिभाषा अलग मान ली गई है, जिसमें नैतिकता की जगह नहीं है। यह अजीब किस्म की उलटबांसी है। कुछ लोगों को लगता है कि यह देश 1947 में अस्तित्व में आया। उसका हजारों साल पुरानी परंपराओं से कोई वास्ता नहीं।

जैसे-जैसे हम लोक विमर्श या लोक जीवन से दूर होते जा रहे हैं, लोक ही क्या, अपने अतीत से ही हमारा विश्वास उठता जा रहा है। समाज में आत्महीनता या पतन आ रहा है और यह साहित्य में भी स्वाभाविक रूप से आ रहा है। हम प्रेमचंद की कहानियां पढ़ते हैं, तो उसमें लोक-विमर्श दिखाई देता है। परंपरा के प्रति लगाव भी नजर आता है। उनकी 'पूर्व संस्कार' जैसी कहानी की कहीं चर्चा नहीं होती। वेद व्यास जी का लोकप्रिय कथन है, 'प्रत्यक्षदर्शी लोकानाम सर्वदर्शी भवेन्नरः'। लोक जीवन को प्रत्यक्ष रूप से देखे बगैर हम मानव जीवन को ठीक से नहीं समझ सकते। इसलिए हमारे विमर्श के केंद्र में लोक-दर्शन होना चाहिए। लेकिन भारतीय समाज धीरे-धीरे इतना आधुनिक होता जा रहा है कि उसे लोक की बात करना पिछड़ापन लगने लगा है। लोक-संस्कृति, लोक-कला, लोक-वाद्य, लोक की वेशभूषा, लोक-पर्व, लोक के उत्पाद- इन सबसे जैसे मोह भंग होता गया है। अब तथाकथित 'ब्रांडेड' वस्तुओं की ओर भागने का दौर है। बोतलबंद पानी पी सकते हैं, लेकिन तांबे या मिट्टी के घड़े में रखा हुआ पानी पीने से परहेज किया जाता है। धोती-कुर्ते वाला व्यक्ति हमें दूसरे लोक से आया हुआ प्राणी लगता है। साड़ी में लिपटी हुई स्त्री हमें पिछड़ी हुई प्रतीत होती है। गाय-भैंस को उपेक्षित करने वाला व्यक्ति जब विदेशी नस्ल का कोई कुत्ता पालता है, तो उसे लोग 'एनिमल लवर' या 'पशु-प्रेमी' कहने लगते हैं। यह तथाकथित परिवर्तन उत्थान है या सामाजिक पराभव, इस पर अब बात करना बेमानी है। लोग अपनी सुंदर परंपराओं, संस्कृतियों और कुछ बेहतर शाश्वत मूल्यों से दूर होते चले जा रहे हैं। ऐसा लगता है, यह लोक विमुखता अब बढ़ती ही जाएगी।

बेटियों से भेदभाव

इक्कीसवीं सदी में भी हमारे देश के बहुत से लोगों की मानसिकता नहीं बदली है। रूढ़िवादी विचारधाराओं और धर्म के ठेकेदार आज भी लड़कियों के प्रति संकीर्ण सोच रखते हैं। एक सामाजिक बुराई बाल विवाह भी है। हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। यह अभियान कितना रंग लाएगा, यह कितनी बेटियों के लिए वरदान साबित होगा, आने वाला समय ही बताएगा। यह अभियान तभी कामयाब होगा, जब समाज भी इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। हिमाचल सरकार ने तो लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल कर दी है। यह एक दुरगामी पहल है। कम उम्र में शादी लड़कियों की सेहत की दुश्मन भी है। कुछ लोग संकीर्ण विचारों के कारण इन्हें बोझ समझते हुए, जल्द से जल्द इनकी शादी करने की योजना बनाने लगते हैं। चाहे उनकी लड़की अपने सपने को साकार करने की कोशिश क्यों न कर रही हो। जब किसी घर में लड़के की शादी होती है, तब दहेज की और जब लड़की पैदा होती है, तो नकारात्मक बातें होने लगती हैं। हमें बेटियों से भेदभाव की मानसिकता त्यागनी होगी

- राजेश कुमार चौहान, जलंधर

बच्चों का भविष्य

केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री जयंत चौधरी द्वारा लोकसभा में साझा की गई जानकारी से पता चलता है कि देशभर में 11.7 लाख से अधिक बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। इनमें से सबसे अधिक 7.84 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश से हैं। यह आंकड़ा शिक्षा के सार्वभौमिक अधिकार को लेकर गंभीर सवाल उठाता है। सरकारी योजनाओं के बावजूद शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना मुश्किल हो रहा है। इसके पीछे आर्थिक समस्याएं, शहरी-ग्रामीण भेदभाव और शिक्षा की गुणवत्ता में असमानता प्रमुख कारण हैं। सरकार ने ऐसे बच्चों की पहचान करने के लिए 'प्रबंध' पोर्टल शुरू किया, लेकिन दोबारा शिक्षा व्यवस्था में उन्हें शामिल करने की प्रक्रिया धीमी है। अगर यह स्थिति नहीं सुधरी, तो यह देश की सामाजिक और आर्थिक समृद्धि के लिए खतरे की घंटी होगी। ये बच्चे ही आगे चल कर देश को प्रगति के पथ पर ले जाएंगे। ऐसे में आज लाखों बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तो यह गंभीर बात है।

- आरके जैन 'अरिजीत', बड़वानी

सेहत की फिक्र

संयुक्त परिवार का विघटन और अब दंपतियों के कामकाजी होने से डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों का बाजार बढ़ता जा रहा है। आम लोग भी इस बात को महसूस करते हैं कि यह स्वास्थ्य के लिए कितना नुकसानदेह है, लेकिन दिखावा और रुचिकर स्वाद तथा आसानी से उपलब्धता की वजह से लोग इसका सेवन कर रहे हैं। वे जाने-अनजाने अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही कर रहे हैं। डिब्बाबंद भोजन मोटापा बढ़ाने के साथ कई जानलेवा बीमारियों को न्योता देता है, जो प्रारंभिक दौर में पहचान में नहीं आती है। मगर कुछ समय के बाद यही बीमारियां हमारे जीवन के लिए नासूर बन जाती हैं। सरकार को कानून बना कर सभी पैकेटबंद खाद्य पर वसा, नमक और चीनी आदि की मात्रा का विवरण उपलब्ध कराना चाहिए ताकि खरीदने से पहले लोग यह जान सकें कि खाद्य सामग्री में कौन सी चीज किस अनुपात में मिलाई गई है। डिब्बाबंद खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर सरकार को निगरानी रखनी चाहिए।

- हिमांशु शेखर, गया

भिक्षावृत्ति पर अंकुश

इंदौर के भिखुकों की कमाई देख कर कोई भी हैरत में पड़ जाए। भीख मांगने वाले वास्तव में भिखारी नहीं रहते। इसमें कई गिरोह सक्रिय हो गए हैं। इनका पर्दाफाश होने के बाद शासन ने इस पर अंकुश लगाने के आदेश जारी किए हैं। एक जनवरी 2025 से भीख देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भिखारियों से मुक्त शहर बनाने के लिए यह पहल सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय की योजना का हिस्सा है। इससे शहर की छवि सुधरेगी, भिक्षावृत्ति की आड़ में हो रहे अपराध और शोषण को भी रोका जा सकेगा। भीख मांगने वाले लोगों को बेहतर जीवन जीने के लिए अन्य कार्यों में लगाया जाएगा। शासन का यह प्रशंसनीय कदम है। उज्जैन में भी भिखुकों की संख्या बढ़ गई है। देश के कोने-कोने से लोग यहां आते हैं, पर वे भिखुकों से परेशान हो जाते हैं। भिक्षा किसी भी समाज के लिए अभिशाप है।

- अरविंद जैन, उज्जैन

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

www.readwhere.com

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स | नई दिल्ली, गुरुवार, 19 दिसंबर 2024

अमल का सवाल

नैशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) अब केवल कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम कराएगी। माना जा रहा है कि एजेंसी का वर्कलोड कम होने से वह ज्यादा फोकस्ड होकर काम कर पाएगी। यह कदम NTA की साख को बचाने और इस साल हुए पेपर लीक कांड की वजह से इमेज पर लगे धब्बे को मिटाने के लिए जरूरी भी था।

ज्यादा बोझ | इस साल NEET विवाद के बाद सरकार ने जो समिति गठित की थी, उसकी सिफारिश है कि क्षमता बढ़ाने के बाद ही एजेंसी को बाकी परीक्षाओं का आयोजन करना चाहिए। इस संस्था की स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली परीक्षाओं में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और एक समान प्रणाली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी। यह विचार अपने आप में ठीक है कि किसी प्रतियोगी परीक्षा में देशभर के स्टूडेंट्स को एक जैसा मौका मिलना चाहिए। हालांकि इस पर अमल में बहुत सारी गड़बड़ियां पाई गईं।

NTA: वर्कलोड कम होगा

NEET पर निर्णय | NEET पेपर लीक को लेकर देश में जिस तरह का हंगामा हुआ था और कई राज्यों में विवाद खड़े हुए, उसे NTA का सबसे लो पॉइंट कह सकते हैं। इसने स्टूडेंट्स के विश्वास को हिलाकर रख दिया। यही वजह है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खासतौर पर NEET का जिक्र करते हुए कहा कि इसे किस मोड में करवाना चाहिए, इस पर बातचीत चल रही है।

सिफारिशें अहम | ISRO के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित समिति ने साफ-सुथरी परीक्षा के लिए कई और सुझाव दिए हैं। परीक्षा केंद्र चुनने के लिए डेटा एनालिटिक्स का प्रयोग, पेपर लीक जैसी घटनाओं से बचने के लिए हाइब्रिड मॉडल जिसमें कंप्यूटर के साथ पेन-पेपर का भी इस्तेमाल हो और डिजी यात्रा की तर्ज पर डिजी एग्जाम जैसे उपाय नैशनल टेस्टिंग एजेंसी के काम को और बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं।

सबसे बढ़कर छात्र | नैशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 2024 में 29 परीक्षाएं आयोजित कीं, जिनमें 85.7 लाख स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड थे। हालांकि 2023 के मुकाबले यह आंकड़ा काफी कम है। तब एजेंसी ने 66 परीक्षाएं संभाली थीं और उनमें 1.33 करोड़ स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इससे साफ है कि NTA पर कितनी अहम जिम्मेदारी है। परिणाम तो बाद की बात है, पहले यह देखना जरूरी है कि परीक्षा कराई कैसे जाती है। इस नुक्ते पर आकर बच्चों की महीनों की मेहनत, भविष्य के सपने और उम्मीदें- सब कुछ NTA पर टिके होते हैं। इसमें दो राय नहीं कि ये सिफारिशें पहली नजर में उपयुक्त लग रही हैं, लेकिन इनकी असल परीक्षा व्यवहार में ही होनी है। देखना होगा कि इन सिफारिशों पर कितना सुसंगत अमल हो पाता है।

साड्डी दिल्ली

गूंज रहे हैं चर्च

विवेक शुक्ला

दिल्ली जंक्शन से बहुत दूर नहीं है फतेहपुरी में सेंट स्टीफेंस चर्च। 1862 में बने सेंट स्टीफेंस चर्च में आजकल क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर हैं। इस चर्च को दिल्ली ब्रदरहुड सोसाइटी ने बनवाया था। सेंट स्टीफेंस चर्च का मूल डिजाइन बरकरार है। चर्च के अंदर एक पत्थर पर सेंट स्टीफेंस कॉलेज के मशहूर प्रिंसिपल प्रो. सुशील कुमार रुद्र का नाम अंकित है। गांधी जी 1915 में जब पहली बार दिल्ली आए, तो वह कश्मीरी गेट स्थित प्रो. रुद्र के आवास पर रुके थे। दिल्ली-6 के ईसाई परिवार क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर और अन्य अवसरों के दौरान इधर ही आते हैं। बेशक, इसे कश्मीरी गेट के सेंट जेम्स चर्च के बाद बनाया गया। उधर, शाहदरा के जवाला नगर में बैपटिस्ट चर्च की स्थापना 1861 में हुई। हालांकि, इसके निर्माण के समय शाहदरा दिल्ली में नहीं, बल्कि मेरठ जिले में था। 1911 में दिल्ली के भारत की नई राजधानी घोषित किए जाने के बाद ही शाहदरा का दिल्ली में विलय हुआ था। बैपटिस्ट चर्च का निर्माण बैपटिस्ट मिशनरी सोसाइटी ने किया था। इस चर्च के आसपास ज्यादा ईसाई नहीं रहते। राजधानी के पुराने प्रोटेस्टेंट ईसाई परिवार सेंट जेम्स चर्च, सेंट स्टीफेंस चर्च और बैपटिस्ट चर्च में आते हैं। प्रोटेस्टेंट ईसाई राष्ट्रपति भवन के पास कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेंपशन में भी पहुंचते हैं क्रिसमस के मौके पर।

गोल डाक खाना से सटे सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल को हेनरी मेड ने डिजाइन किया था। वह 1939 से 1947 तक भारत सरकार के मुख्य वास्तुकार के रूप में कार्य कर रहे थे। इस बीच, दिल्ली छावनी में सेंट मार्टिन चर्च का भी डिजाइन उत्कृष्ट है। इसका निर्माण 1929 में हुआ। इसके डिजाइनर आर्थर गॉर्डन शूस्मिथ थे। सेंट मार्टिन चर्च का डिजाइन इंडो-ब्रिटिश वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। शूस्मिथ ने ही मंदिर मार्ग पर सेंट थॉमस चर्च को भी डिजाइन किया। ब्रदर जॉर्ज सोलोमन, जिन्होंने कई वर्षों तक सेंट मार्टिन चर्च में पादरी के रूप में सेवा की, कहते हैं, 'सेंट मार्टिन चर्च को ब्रिटिश सरकार ने अपने ईसाई सैनिकों और छावनी के निवासियों के लिए बनाया था। जाहिर है, ओरोंजों के भारत छोड़ने के बाद यहां सब आने लगे।' दिल्ली-NCR में काफी संख्या में पूर्वोत्तर राज्यों के ईसाई रहते हैं। ये आमतौर पर सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल ही जाना पसंद करते हैं। दिल्ली की नन्नी सी एंग्लो-इंडियन बिरादरी सेंट जेम्स चर्च में ही क्रिसमस पर मौजूद रहती है। इसका निर्माण 1836 में एंग्लो इंडियन सिपाही जेम्स स्किनर ने करवाया था। एक दौर में भारत में ब्रिटिश वायसराय प्रार्थना करने के लिए सेंट जेम्स चर्च में ही आते थे। इसके परिसर में प्रवेश करते ही लगता है मानो आप किसी शांत टापू में पहुंच गए हों।

एकदा

भरोसा हो तो ऐसा

सुभूति बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में थे और लंबे समय से अपने गुरु की शिक्षाओं का प्रचार करना चाहते थे। एक सुबह जेतवन में उन्होंने इसके लिए बुद्ध से अनुमति मांगी। बुद्ध ने कहा। 'शिक्षक बनना आसान नहीं है। भले ही तुम सुंदर शब्द बोल रहे हो, बहुत से लोग तुम्हारी आलोचना और निंदा करेंगे।' सुभूति बोले, 'हे शास्ता, आपके आशीर्वाद से मुझे यकीन है कि इसका मुझ पर कोई असर नहीं होगा। क्या मुझे तथागत की अनुमति है?' बुद्ध कुछ मिनटों तक चुप रहे, फिर पूछा, 'क्या होगा अगर तुम किसी गांव में पढ़ाने जाओ, और लोग तुम्हारी बात न सुनें?' 'प्रभु, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। कम से कम वे मुझ पर आरोप नहीं लगा रहे हैं।'

Subrata Char

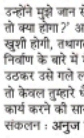

'अगर वे आरोप लगाने लगें तो?' 'मैं फिर भी मुस्कुराऊंगा। मैं खुद को याद दिलाऊंगा कि उन्होंने मेरी पिटाई तो नहीं की।' 'अगर वे पिटाई कर दें तो?' 'मैं तथागत की कृपा से फिर भी ठीक रहूंगा। कम से कम उन्होंने मुझे चाकू तो नहीं मारा?' 'अगर वे चाकू मार देते हैं तो सुभूति?' 'मैं यह सोचकर खुश हो जाऊंगा कि उन्होंने मुझे जान से नहीं मारा है।' 'और अगर वे तुम्हें मार देते हैं तो क्या होगा?' अब आंखों में आंसू लेकर सुभूति बोले, 'मुझे बहुत खुशी होगी, तथागत। आपके संदेश को फैलाते हुए मरने से बेहतर निर्वाण के बारे में मैं सोच नहीं सकता।' 'सुभूति,' बुद्ध ने आसन से उठकर उसे गले लगाते हुए कहा, 'तुम शिक्षक बनने के योग्य हो। मैं तो केवल तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा था। तुम्हारे अंदर एक महान कार्य करने की सारी क्षमता मौजूद है।'

संकलन : अनुज मौर्य

ट्रंप और मोदी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सब्सिडी देने के हिमायती हैं ताकि नौकरियों के मौक़े बढ़ें

रोजगार बढ़ाने का यह क्या तरीका हुआ

स्वामीनाथन एस अंकलेसरिया अय्यर

अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में एक बात कॉमन है। दोनों ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को सब्सिडी देने, उनमें निवेश करने के हिमायती हैं। वे मानते हैं कि इससे रोजगार के मौके बढ़ेंगे और उनके देश बनेंगे ग्रेट।

MAGA का ख्वाब | अमेरिकी लोग शिकायत करते हैं कि उनके देश से करोड़ों नौकरियां का चीन को निर्यात कर दिया गया है। यानी कई चीजें अमेरिका में बननी बंद हो गई हैं, उनका आयात चीन से किया जा रहा है। ट्रंप वे रोजगार वापस लाना चाहते हैं ताकि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (MAGA) का उनका ख्वाब पूरा हो सके।

क्यों घटे रोजगार | माफ कीजिएगा, यह उलटे बांस बरेली है। बिल क्लिंटन के राष्ट्रपति रहने के दौरान उनके आर्थिक सलाहकारों में शामिल रॉबर्ट लरिस का यही कहना है। वह बताते हैं कि कई ऐतिहासिक बदलावों की वजह से विकसित देशों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार घटे हैं।

औद्योगिक क्रांति से पहले | 18वीं सदी तक दुनिया में 80% लोग खेती से जुड़े थे। तब अलग-अलग देशों के लोगों के बीच आय में असमानता भी कम थी। इसके बाद औद्योगिक क्रांति का दौर आया, जिससे प्रॉडक्टिविटी और इनकम में बढ़ोतरी हुई। अमेरिका में 1810 में 81% लोग खेती पर आश्रित थे जबकि 3% को मैन्युफैक्चरिंग और 16% को सर्विसेज सेक्टर में रोजगार मिला हुआ था।

ट्रंप फेल होंगे | 1950 तक खेती पर आश्रित लोगों की संख्या घटकर 12% रह गई। मैन्युफैक्चरिंग में यह बढ़कर 24% और सर्विसेज में 64% हो गई। 2020 तक तीनों क्षेत्रों का रोजगार में योगदान क्रमशः 1.8%, 8%, और 91% हो गया। जब कोई देश अमीर होता है तो वहां यही ट्रेंड दिखता है। यह 'इकॉनमिक लॉ' है, जिसे बदलना ट्रंप के लिए भी मुमकिन नहीं।

मशीनों का प्रभाव | मशीनों का प्रयोग बढ़ने से रोजगार में कमी आती है। अमेरिका में सिर्फ 1.8% आबादी खेती करती है। इससे इतनी पैदावार होती है कि अपनी जरूरत पूरी करने के बाद वह बड़े पैमानों पर कृषि उत्पादों का निर्यात भी करता है।

मैन्युफैक्चरिंग पर जोर

- मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ट्रंप का ख्वाब
- मोदी करते हैं आत्मनिर्भर भारत की बात
- भारत में छुट्टियां ज्यादा, इनमें हो कटौती

कैसे हुआ बदलाव | शुरुआत में, उत्पादकता बढ़ने से कृषि उत्पादों के दाम गिरे और उससे दिहाड़ी में कमी आई। ऐसे में लोग खेती से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ओर शिफ्ट हुए। ऐसी कंपनियों का साइज बढ़ा तो वे कम लागत पर उत्पादन करने में सक्षम हुईं। इससे डिमांड को बढ़ावा मिला, लिहाजा प्रॉडक्शन बढ़ा और संबंधित रोजगार भी। लेकिन जैसे-जैसे देश अमीर हुए, सर्विसेज की तुलना में मैटीरियल गुड्स की मांग धीमी रफ्तार से बढ़ी।

ग्रोथ धीमी होगी | ट्रंप जब पिछली बार राष्ट्रपति बने थे, तब उन्होंने आयात शुल्क लगाया ताकि अमेरिका में स्टील और एल्युमीनियम क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिले। उनका तर्क था कि ये 'स्ट्रैटेजिक' इंडस्ट्रीज हैं। उनके बाद बाइडन राष्ट्रपति बने तो उन्होंने 'स्ट्रैटेजिक' का दायरा बढ़ाकर इसमें सोलर पैनल, बैटरी, विंडमिल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को शामिल कर लिया। दूसरे टर्म में ट्रंप इस लिस्ट में और चीजें जोड़ सकते हैं।

एपल की कामयाबी | भारत में आज 43% आबादी खेती पर आश्रित है। यानी उससे इंडस्ट्री और फिर सर्विसेज में लोगों के शिफ्ट होने में लंबा वक्त लगेगा। सच यह भी है कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के पहले 10 वर्षों में रोजगार में वैसी बढ़ोतरी नहीं हुई, जिसका वादा किया गया था। सरकार की प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव स्कीम की इकलौती कामयाबी आईफोन बनाने वाली कंपनी एपल रही है, जिससे 1.5 लाख प्रत्यक्ष रोजगार पैदा किए हैं। लेकिन भारत जैसे देश में जहां हर साल 1.2 करोड़ लोग रोजगार बाजार से जुड़ते हैं, यह काफी कम है।

छुट्टियां हैं ज्यादा | कई सरकारी योजनाओं के बावजूद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में करोड़ों नए रोजगार क्यों नहीं पैदा किए जा सके? अर्थशास्त्रियों के मुताबिक, इसके लिए श्रम कानून दोषी हैं, जो मजदूरों को निकालना मुश्किल बनाते हैं, लेकिन यह छोटी वजह है। इससे बड़ी वजह है छुट्टियां। भारत में छुट्टियां बहुत ज्यादा होती हैं। कुछ वर्कर्स साल में 200 दिनों से भी कम काम करते हैं। इससे भारतीय वर्कर्स दूसरे देशों के वर्कर्स की तुलना में महंगे हो जाते हैं। लिहाजा भारतीय कंपनियां कैजुअल वर्कर्स को हायर करती हैं। ऐसे में अच्छे रोजगार नहीं पैदा होते।

ट्रेड यूनियन बाधा | छुट्टियों को साल में घटाकर 50 दिन करना एक शुरुआती कदम हो सकता है, लेकिन BJP और कांग्रेस दोनों के पास ट्रेड यूनियन हैं, जो छुट्टियों में कटौती का विरोध करेंगी। साफ है कि भारत में रोजगार बढ़ाने के लिए जो जरूरी रिफॉर्म्स हैं, वे राजनीतिक तौर पर संभव नहीं।

प्रदूषण पर चीन से क्या सीख सकता है भारत

अमित भट्टाचार्य

यह एक भयावह सपने जैसा था। समूचा शहर जहरीली धुंध के साए में था। जो भी बाहर निकलता, उसकी आंखें जलने लगतीं। कई लोग इतना खांस रहे थे कि हांफना तक मुश्किल हो गया था। सांस से जुड़ी बीमारियां हर किसी को जकड़ रही थीं। प्रशासन ने स्कूल बंद कर दिए, बड़ी गाड़ियां भी। मीडिया इसे वायुप्रलय कहने लगा। आपको यह सब आज के दिल्ली-मुंबई जैसा लग रहा होगा। लेकिन यह तस्वीर 2013 की शुरुआती सर्दियों के पेइचिंग की है।

दिल्ली से मुंबई | दिल्ली ने नवंबर के मध्य में इस सीजन का सबसे खराब AQI दर्ज किया। अगले कुछ दिनों में यह बढ़कर 494 तक पहुंच गया, जो राष्ट्रीय राजधानी में अब तक का दूसरा सबसे खराब AQI था। अधिकारियों ने स्टेज-4 GRAP लागू किया। लखनऊ में स्मॉग का जहरीलापन एक साथ 12 सिगरेट पीने के बराबर था तो मुंबई का हाल भी इससे ज्यादा अलग नहीं रहा। रविवार को मुंबई के वर्ली में AQI 225 दर्ज किया गया, नरीमन पॉइंट और अन्य जगहों पर जहरीली धुंध छाई रही।

धुंध में शहर | कई वर्षों से खासकर सर्दियां आते ही भारतीय राजधानी ही नहीं, लखनऊ, मुंबई, भोपाल और पटना जैसी कई मेट्रो सिटीज को भी गंभीर वायु प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। यह संकट 2013 के आसपास के पेइचिंग की स्थिति से मिलता-जुलता है, जब चीनी राजधानी दुनिया में प्रदूषण की राजधानी के रूप में जानी जाती थी। पेइचिंग की जहरीली हवा चीनी नेताओं के लिए अंतरराष्ट्रीय शर्मिंदगी का कारण बन रही थी। मार्च 2013 में, चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री ली केक्यांग ने नेशनल पीपल्स कांग्रेस की वार्षिक बैठक में वादा किया कि वे 'नीले आसमान की रक्षा के लिए मजबूती से लड़ेंगे'। 2013 में पेइचिंग में औसत PM 2.5 101.5 था। 2023 तक यह घटकर 38.9 रह गया।

पेइचिंग और दिल्ली | चीन से हम काफी सीख सकते हैं। चीन और भारत के बीच भूगोल, मौसम और विकास के लिहाज से कई समानताएं हैं। दिल्ली और पेइचिंग को ही देख लें। दोनों शहर पहाड़ी क्षेत्रों के पास हैं, जो प्रदूषकों को आसानी से फैलने से रोकते हैं। नतीजतन, सर्दियों के मौसम में शांत हवाएं, नमी और बारिश की कमी प्रदूषण को बड़े पैमाने पर बढ़ा देती है। दिल्ली के मामले में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और एनसीआर के कस्बों से प्रदूषण आता है, जबकि पेइचिंग पर हेबेई और तियानजिन प्रांतों का प्रभाव पड़ता है।

कॉमन रूम

बदलता लक्ष्य | 2013 में जब पेइचिंग में प्रदूषण चरम सीमा पर पहुंच गया, तो वहां के मेयर ने 2014 में चार साल में PM2.5 की मात्रा को एक तिहाई तक कम करने का वादा किया। लेकिन 2016 के अंत में वह अपने लक्ष्य को पूरा न कर पाने की वजह से हटा दिए गए। वहीं भारत ने 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नीति की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य 2017 के स्तरों के मुकाबले पांच वर्षों में 121 शहरों में पार्टिकुलेट मैटर को 20-30% तक कम करना था। 2023 के अंत में क्लाइमेट ट्रेंड्स और रेस्पायर लिविंग साइंसेज ने पाया कि 46 शहरों में केवल आठ शहरों ने PM10 का लक्ष्य पूरा किया, जबकि 22 शहरों में प्रदूषण स्तर वास्तव में बढ़ गया। इसके बाद नीति का लक्ष्य 2026 तक के लिए बदल दिया गया।

प्रदूषण युद्ध | पेइचिंग ने PM2.5 की निगरानी के लिए पूरे शहर में 1,000 से अधिक सेंसर लगाए। नई सड़कों के निर्माण की गति धीमी की और पार्किंग सुविधाओं पर पाबंदियां लगाईं। सार्वजनिक परिवहन और पैदल चलने की सुविधाएं बढ़ाईं। 2017 में पेइचिंग ने यूरो VI के कड़े वाहन मानक लागू किए। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया गया। 2017 में लगभग 5,600 पर्यावरण निरीक्षक तैनात किए गए।

60 फीसदी कम | इन प्रयासों से बड़े परिणाम देखने को मिले। 2023 तक PM2.5 लेवल 60% तक कम हो गया। शिकागो विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में इतनी बड़ी कमी हासिल करने में दशकों लग गए, जबकि चीन ने इसे कुछ वर्षों में कर दिखाया। 2013 से 2020 के बीच, वैश्विक वायु प्रदूषण में कमी में 75% योगदान चीन का था। क्या हम ऐसा ही कुछ भारत में नहीं कर सकते?

औरंगज़ेब को छकाने वाला बंजारा

बंजारा शब्द सुनते ही स्वच्छंदता और आजादी का अनुभव होता है। लेकिन, बंजारा शब्द किसी बेफिक्री को ध्यान में रखते हुए नहीं बना। यह बना है वणजारा शब्द से। वणजारा यानी व्यापारी। बाबा लक्खी शाह बंजारा भी एक व्यापारी ही थे। बहुत लोग उन्हें लाखा बंजारा कहते हैं। व्यापारी होने के अलावा भी वह बहुत कुछ थे- सिविल कॉन्ट्रैक्टर, ट्रासपोर्टर और समाजसेवक। लाखो लोगो को अकेले चलाने वाले। उनके परिवार ने दिल्ली मे चार गांव बसाए थे। इनमे से एक आज देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान भी है यानी रायसीना। बाकी तीन गाव थे- नरेला, बारहखभा और मालवा।

सबसे बड़े व्यापारी | लाखा बंजारा का जन्म हुआ था चार जुलाई 1580 को। 18वीं सदी के मशहूर शायर नजीर अकबराबादी की एक रचना है, 'बंजारानामा'। इसमे उन्होने लक्खी शाह के बारे मे लिखा है। कहा जाता है कि लाखा उस वक्त मध्य एशिया के सबसे बड़े व्यापारी थे। वह कई टन नमक लेकर टांडा के रूप में चलते। टांडा मतलब एक पूरा गांव, जो एक साथ चल पड़ा हो। इनमे करीब चार लाख लोग और 10 लाख बैल शामिल थे। टांडा की रक्षा के लिए एक लंबी चौड़ी सशस्त्र सेना भी थी। सागर से 70 किलोमीटर दूर बीना खिमलासा रोड पर आज भी बंजारो का एक गांव है, जिसे टांडा के नाम से जाना जाता है।

लाल किले के ठेकेदार | लाखा बंजारा का कफिला जिस रास्ते पर जाता, वह अपनी सुविधा के लिए कुएं, बावड़ियों और सरायों का निर्माण कराते। इसका फायदा बाकी लोगों को भी मिलता। उनकी बनवाई कई इमारतें तो मिसाल हैं। 1639 में जब दिल्ली में लाल किले का निर्माण हो रहा था, तब उसमें शामिल ठेकेदारों में लक्खी शाह मुख्य थे। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती बिलासपुर जिले में स्थित खालसा राजधानी लौहगढ़ का किला और 55 कुएं उन्हीं की देखरेख में बने। हरियाणा के बालसोला में मालागढ़ रोड पर पांच एकड़ का तालाब और नाहन की गढ़ी भी लक्खी बंजारा की देन हैं। यही नहीं, दिल्ली, लखनऊ, सहारनपुर, देहरादून और दरभंगा में आलीशान बगीचे, बिहार में लक्खी सराय- ये सब उनके ही बनवाए हुए हैं।

हैरतअंगेज कारनामे | लक्खी शाह द्वारा सागर का किला बनवाए जाने का जिक्र भी मिलता है। सागर में एक शानदार झील है। माना जाता है कि यह झील 16वीं सदी में बनी। लाखा बंजारा ने ऐसे कई काम किए, जिनके बारे में सुनकर आज हैरत हो सकती है, लेकिन मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना के साथ उन्होंने जो किया, उसकी तो दूसरी मिसाल मिलना मुश्किल है।

रुई से जीत | 11 नवंबर 1675 को औरंगजेब के आदेश पर सिखों के नौवें गुरु, गुरु तेग बहादुर को शहीद कर दिया गया। जगह थी दिल्ली का चांदनी चौक। औरंगजेब ने पाप किया था, लेकिन उसके खिलाफ आवाज कौन उठाता? तभी लाखा बैलगाड़ियों का काफिला लेकर मुगल सेना के सामने से निकले। सैकड़ों बैलगाड़ियां और उन पर सवार हजारों लोग। उन लोगों में शामिल सिख लड़ाके। काफिला बड़ा और हवा में रुई उड़ने लगी। मुगल सेना का ध्यान थोड़ी देर के लिए भटका। बस, इतना काफी था लाखा बंजारा के लिए। उन्होंने पूरे सम्मान के साथ गुरु तेग बहादुर का पार्थिव शरीर उठा लिया और काफिले के बीच गुम हो गए। तब उनकी उम्र थी 95 साल। सात जून 1680 को मालचा पैलेस में लक्खी शाह बंजारा का निधन हो गया।

टाइम मशीन

चुनौतियों से संबल

प्रणव प्रियदर्शी

आयुर्विज्ञान उद्योग को वैश्विक तौर पर क्लाउड सॉफ्टवेयर और डेटा एनालिटिक्स मुहैया कराने वाली कंपनी एक्स्ट्रियो (Axtria) में सीनियर मैनेजर (बिजनेस इनसाइट्स) की अहम भूमिका निभा रहीं मीनाक्षी चंद्रशेखरन को हेल्थकेयर सेक्टर में AI की संभावनाएं चकित करती हैं। जब वह पहली बार इस सेक्टर में AI से जुड़े एक प्रॉजेक्ट पर काम कर रही टीम का हिस्सा बनी थीं, तभी उन्हें एहसास हो गया था कि इन दोनों का मेल दुनिया भर में लोगों की जिंदगी बदल सकता है। जैसे-जैसे उनकी टीम चिकित्सा से जुड़े अलग-अलग पहलुओं पर AI के संभावित प्रभावों पर काम करती गई, उनका विश्वास मजबूत होता गया। वह कहती हैं, जरा कल्पना कीजिए उस भविष्य की, जब AI के सहारे रीयल टाइम डेटा के आधार पर कहीं ज्यादा कुशलता और तत्परता से लोगों की बीमारी का पता लगाकर उनका बेहतरीन इलाज करना संभव होगा। इसी भविष्य को जल्द से जल्द वर्तमान में बदलने की प्रेरणा आज भी करियर में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी हुई है। टेक इंडस्ट्री में करियर बनाने की ख्वाहिश रखने वाली लड़कियों को वह यही सीख देती हैं कि जिज्ञासा को कभी मरने न दें। यह करियर की दिशा बताने वाला ऐसा कंपास है, जो हमेशा उनका मार्गदर्शन करता रहेगा। इसी चीज ने उन्हें अनजान राहों पर आगे बढ़ने का संबल दिया। उस यात्रा में ईंधन बने वे मेंटॉर्स जो ज्ञान की उनकी भूख देखकर खुश होते और उसे बढ़ाते रहे। इसीलिए उनकी अगली सलाह यह है कि अकेले चलने के बजाय अपने जैसे दूसरे लोगों की तलाश करें, उनका साथ दें, उन्हें साथ रखें। ऐसे लोगों का नेटवर्क तैयार करें जिनका आपकी क्षमता पर यकीन हो और जो आपका मार्गदर्शन करने में खुशी महसूस करते हो। आखिरी बात यह कि चुनौतियों को कठिनाई के तौर पर कभी न देखें। ये ऐसे अवसर हैं जो आपके भीतर की उन क्षमताओं को सामने लाते हैं जिनके बारे में आपको भी पता नहीं। इसलिए चुनौतियों को सेलिब्रेट करें।

आधी दुनिया

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ स्वागत योग्य कदम

संपादकीय 'तालमेल के संकेत' (18 दिसंबर) पढ़ा। श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके का भारत को अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए चुनना, दोनों देशों के संबंधों में एक सकारात्मक मोड़ का प्रतीक है। यह आकलन कि श्रीलंका की भूमि भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि, चीन के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर यह देखना होगा कि हंबनटोटा पोर्ट जैसे संवेदनशील मुद्दों पर श्रीलंका अपनी प्रतिबद्धता को कैसे बनाए रखता है। हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग और सुरक्षा पर दोनों देशों की सहमति एक स्वागत योग्य कदम है।

श्याम सिंह राठौर, लक्ष्मी नगर

■ चुनाव पर बहस

18 दिसंबर को संपादकीय पेज पर प्रकाशित लेख 'क्या वन नेशन, वन इलेक्शन जरूरी है' पढ़ा। देश में एक चुनाव को लेकर लोकसभा में कई पार्टियों की आपत्ति भी सामने आई। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि BJP देश में तानाशाही लाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने वन नेशन, वन इलेक्शन बिल का विरोध किया। TMC ने कहा कि यह बिल वास्तव में एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा पूर्ति के लिए लाया जा रहा है। वन नेशन, वन इलेक्शन की परंपरा देश की आजादी के पश्चात 1967 तक चली। मेरा मानना है कि एक देश, एक चुनाव देशहित में है।

कांतिलाल मांडोत, ईमेल से

■ गेहूं के साथ घुन

संपादकीय पृष्ठ पर 18 दिसंबर को प्रकाशित लेख 'क्या औरतें कानून का दुरुपयोग करती हैं' पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है कि हमारे देश में दहेज विरोधी कानून का दुरुपयोग होता है। लेकिन जिस तरह हमारे देश में महिलाओं के प्रति हिंसा का आलम है, अगर ऐसे कानूनों को नरम कर दिया जाए तो दरिंदों के हौसले और बुलंद होंगे। बहरहाल, सभी कानूनों का दुरुपयोग नहीं करते, लेकिन यह कहावत तो है ही कि एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, और गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है।

राजेश कुमार चौहान, ईमेल से

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

कनाडा के जस्टिन ट्रूडो पर इस्तीफे का दबाव- एक खबर

- बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होय?

शेफाली गुप्ता

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
hindi.speakingtree.in

जब हम वादे निभाते हैं तो उतने ही मज़बूत होते हैं

अमित वर्मा

वचन केवल शब्दों का आदान-प्रदान नहीं, बल्कि आत्मा का अनुबंध है। यह हमारे भीतर बसी दिव्य चेतना को उभारने का एक साधन है। जब हम कोई वादा करते हैं- चाहे वह विवाह-मंडप में की गई प्रतिज्ञा हो, मित्रों से किया सहायता का आश्वासन हो या खुद से तय किया गया कोई संकल्प- हम अपनी आत्मा को एक मार्गदर्शक सिद्धांत सौंप रहे होते हैं। वचन हमारी आंतरिक इच्छाशक्ति, नैतिक संकल्प और आध्यात्मिक चेतना को क्रियान्वित करने का माध्यम बनते हैं।

समस्या यह नहीं कि वचन देना कठिन है। सच तो यह है कि वचन देना बहुत सरल है। कठिनाई है तो उस वचन को निभाने में, उन शब्दों को कर्म में ढालने में। जब हम वचन देते समय आश्वस्त होते हैं, तब मन में उम्मीदों का प्रकाश-स्तंभ जगमगाता है। लेकिन असल में उस वचन को पूरा करने का समय आने पर मन के भीतर एक विरोधाभास जन्म लेता है, हृदय एक दिशा में खिंचता है, तो मस्तिष्क दूसरी ओर। भावनाएं तर्क को हराने लगती हैं। यही आंतरिक द्वंद्व हमारी आध्यात्मिक परीक्षा है। यह वही क्षण है जब हमें यह समझना चाहिए कि वचन निभाना आत्म-उत्थान का साधन है।

जब हम अपने वादे पर अडिग रहते हैं, तो हम दिव्य ऊर्जा से सिंक्रोनाइज करते हैं। ऐसा करने से हमें अनुभव होता है कि हमारा अस्तित्व व्यक्तिगत मर्यादाओं से परे अनंत चेतना से जुड़ा हुआ है। वचन निभाना तब एक कर्मकांड नहीं, बल्कि साधना का मार्ग बन जाता है। यह साधना हमें अहंकार से मुक्त करती है, क्योंकि अपना वादा पूरा करने के लिए हमें त्याग करना पड़ता है- समय का त्याग, श्रम का त्याग, कभी-कभी भावनाओं का त्याग। यह त्याग मन की सीमाओं को तोड़कर हमें व्यापक आत्मबोध की ओर ले जाता है।

जो वचन निभाते हैं, जीवन की कठिनाइयां फिर उन्हें डरा नहीं पातीं, क्योंकि उन्होंने अपने आपको आत्म-अनुशासन के माध्यम से निखारा होता है। जब हम अपने वचनों से नहीं डिगते, तो हमारा आत्मसम्मान प्रबल होता जाता है। हम जानते हैं कि चाहे हालात कैसे भी हों, हम सत्य के साथ दृढ़ता से खड़े रहने में सक्षम हैं।

ऐसे में हमारे संबंध भी नए अर्थ पाते हैं। जिन लोगों से हमने वादे किए हैं, उनका हम पर विश्वास गहरा होता जाता है। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हमारा खुद पर विश्वास बढ़ता है। हर पूरा किया गया वादा हमारे भीतरी आकाश में एक नया तारा बनकर जगमगाता है। हम इस प्रकाश में अपने जीवन की राह साफ-साफ देख पाते हैं। यह प्रकाश हमें यह दिखाता है कि हम केवल मानव शरीर नहीं, बल्कि दिव्य चेतना के अंश हैं, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपनी अंतर्निहित ज्योति को प्रज्वलित करने आए हैं।

वादा निभाना आत्मानुशासन, त्याग, विश्वास और आत्मिक विकास का मार्ग है। जब हम वादे को केवल बोझ या दायित्व न मानकर एक आध्यात्मिक साधना समझते हैं, तो हमारे भीतर का अहंकार गलकर परमार्थ की अनुभूति में बद

2024

56 जगहों पर छोटे-बड़े युद्ध हो रहे हैं फिलहाल विश्व में

65% बढ़ गया 3 साल में संकटग्रस्त क्षेत्रों का हिस्सा

30% बढ़ोतरी हुई जंग में जान गंवाने वालों की संख्या में

ये 5 सबसे अशांत देश

रैंक	देश	GPI स्कोर
1	यमन	3.397
2	सूडान	3.327
3	दक्षिण सूडान	3.324
4	अफगानिस्तान	3.294
5	यूक्रेन	3.28

क्या है GPI स्कोर

देश की शांति का पैमाना है। इसे 1 से 5 के स्केल पर नापते हैं। एक यानी सबसे ज्यादा शांति और 5 यानी सबसे कम शांति।

क्या कहता है ग्लोबल पीस इंडेक्स

2008 में ग्लोबल पीस इंडेक्स की शुरुआत के बाद से शांति के मामले में देशों का औसत स्कोर 4.5% कम हुआ है।

स्रोत: इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की रिपोर्ट

युद्ध के कारण बढ़ी गरीबी और मौतें

पलायन 9.5 करोड़ से अधिक लोग अब या तो शरणार्थी हैं या अपने देश से जा चुके हैं।

मौतें एक साल में हिंसक घटनाओं में मरने वालों की संख्या 37% बढ़ी है।

गरीबी हिंसा के कारण ग्लोबल इकॉनमी को करीब 1612 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

बदल रहा है ट्रेंड

बेनतीजा युद्धों में बढ़ोतरी: 21वीं सदी में युद्ध का ट्रेंड बदल गया है। आज ज्यादातर जंग बेनतीजा ही रहते हैं।

गृह युद्ध का दौर: आज ज्यादातर देश इसी में उलझे हैं। मसलन, अफगानिस्तान, श्रीलंका और कई अन्य देश।

तकनीक का दखल: आज युद्ध में ड्रोन और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ रहा है।

भारत

4 साल से बढ़ रहा शांति का स्तर

पिछले तीन वर्षों में दुनिया के संकटग्रस्त क्षेत्रों का हिस्सा 65% बढ़ गया है, जो भारत के कुल आकार का लगभग दोगुना है। वहीं दूसरी ओर भारत ने शांति का स्तर पिछले एक साल में 16% बढ़ा है।

92 देश इस समय युद्ध में... वर्ल्ड वॉर-II के बाद इतनी जंग कभी नहीं लड़ी गई, जितनी आज

2024 रहा वॉर-ईयर, कब आएगी शांति

'टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है। फ़तह का जश्न हो कि हार का सोग, ज़िंदगी मय्यतों पे रोती है।' मशहूर शायर साहिर लुधियानवी की ये पंक्तियां आज दुनिया भर में जारी युद्ध पर सटीक बैठती हैं। 2024 में जारी जंग पर एक नज़र। संदीप भूषण की रिपोर्ट...

File Photo

रूस और यूक्रेन

इस साल यूक्रेन को रूस पर मिली बढ़त

20 फरवरी 2022 को शुरू हुए रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को करीब-करीब तीन साल होने वाले हैं। यूक्रेन ने अपने कब्जे वाले 54% क्षेत्र को फिर से हासिल कर लिया है। अब भी देश के 18% हिस्से पर रूस का कब्जा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला करने की योजना बना रहा है। दूसरी तरफ, यूक्रेन अब जंग के मैदान में सैनिकों से ज्यादा ड्रोन की मदद ले रहा है।

असर युद्ध जारी

इंटरस्टेट वॉर

फिलहाल	2025 में
जंग जारी, हालात खराब	सीज फायर की उम्मीद

नए साल में सीज फायर की उम्मीद बढ़ी: दोनों देशों के बीच जंग रुकने की भविष्यवाणी कर पना अभी मुश्किल है। डॉनल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच जंग रुकवाने का ऐलान किया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि उनके दखल से दोनों देशों के बीच युद्ध पर विराम लगेगा।

इस्राइल और फलस्तीन

जवाबी हमले से ढीले पड़े हमास के तेवर

हमास ने 7 अक्टूबर, 2023 को इस्राइल पर बड़ा हमला किया। जवाब में इस्राइली सेना ने भी गाजा पट्टी पर हवाई और जमीनी हमले शुरू कर दिए। हिज्बुल्लाह, यमन के हूती विद्रोहियों, सीरिया, इराक और ईरान के एकजुट आने के बाद भी वे इस्राइल को नहीं झुका पाए और 2024 के अंत तक हमास के तेवर ढीले पड़ गए। अब वह जंग रोकने की गुहार लगा रहा है। गाजा के करीब 20 लाख लोग युद्ध के कारण बेघर हो चुके हैं।

असर युद्ध जारी

इंटरस्टेट वॉर

फिलहाल	2025 में
जंग जारी, हालात खराब	समझौते की उम्मीद

इस्राइल पर हमले बंद करेगा हमास? हमास के एक नेता ने कहा है कि गाजा में युद्ध विराम के लिए बातचीत फिर से शुरू हो गई है। युद्ध को समाप्त करने के लिए जल्द समझौते की उम्मीद है। यानी, 2025 में मिडिल-ईस्ट में एक बड़े युद्ध पर विराम लग सकता है।

सीरिया

असद को छोड़ना पड़ा देश, विद्रोहियों का कब्जा

विद्रोहियों ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असाद के शासन को समाप्त कर दिया। 30 नवंबर को अलेप्पो पर कब्जा करने के साथ विद्रोहियों ने एक भीषण युद्ध का ऐलान किया, जिसमें 8 दिसंबर को उन्हें बड़ी सफलता मिली। असद को रूस में शरण लेनी पड़ी। इस उथल-पुथल ने सीरिया में असाद परिवार के 50 साल से अधिक पुराने शासन और 2011 से चल रहे सीरियाई गृहयुद्ध को करीब-करीब समाप्त कर दिया।

असर नहीं सुधरे हालात

सिविल वॉर

फिलहाल	2025 में
सिविल वार समाप्त, हालात ठीक नहीं	विद्रोही गुटों में झगड़े का खतरा

2025 में कहीं फिर न एक्टिव हो जाए ISIS: अब देश पर विद्रोही गुट का कब्जा है। हालांकि, देश में हालात ठीक नहीं हैं। गोलीबारी और लूटपाट जारी है। सीरिया के अलग-अलग हिस्सों पर अलग-अलग गुटों का कब्जा है। देश के एक हिस्से पर ISIS का भी दबदबा है। इसके भी एक्टिव होने की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में 2025 में भी हालात पूरी तरह सुधरने के आसार नजर नहीं आते।

नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया

क्या लोकतंत्र पर खतरा?

नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच तनाव वर्ल्ड वॉर II के समय से ही जारी है। 50 के दशक में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के हिस्से पर हमला भी किया और यह वॉर करीब 3 साल तक चला। दोनों के बीच कोई स्थाई समझौता तो नहीं हुआ, लेकिन तब से स्टेटस-को कायम है। उधर, साउथ कोरिया में मार्शल लॉ के बीच लोकतंत्र पर सवाल उठने लगे हैं। नॉर्थ कोरिया इसका फायदा उठा सकता है।

असर स्टेटस को

इंटरस्टेट वॉर

फिलहाल	2025 में
छिटपुट हमले	न्यूक्लियर वॉर?

जंग की बढ़ी आशंका: जानकार साउथ कोरिया के हालात को दुश्मन की चाल मान रहे हैं, ताकि उसे कमजोर किया जा सके।

चीन और ताइवान

युद्ध की आशंका बरकरार

चीन ने 2024 में ताइवान के पास बड़े पैमाने पर नेवी और एयरफोर्स की गतिविधियां बढ़ा दी हैं। बीते कुछ समय से वह लगातार हमलावर दिखा है और ताइवान पर बलपूर्वक कब्जे की बात भी कह चुका है। ऐसे में दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो इसमें अमेरिका का कूदना स्वाभाविक है। अभी तक कोई औपचारिक हमला दोनों देशों के बीच नहीं हुआ है, लेकिन इससे इनकार नहीं कि दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है।

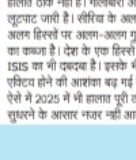

असर स्टेटस को

इंटरस्टेट वॉर

फिलहाल	2025 में
हालात स्थिर	सुपर पावर के बीच जंग?

प्रशांत क्षेत्र के अशांत होने का खतरा: इस क्षेत्र में लगभग सभी देशों का इंट्रेस्ट शामिल है। युद्ध हुआ तो क्षेत्र में हालात बिगड़ जाएंगे।

भारत और चीन

...एक कदम आगे बढ़े

भारत और चीन के बीच बिगड़े हालात 2024 में बेहतर हुए हैं। दोनों देशों द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 2020 से पहले की स्थिति को फिर से बहाल करने पर सहमत होना उनके संबंधों में सुधार की दिशा में एक अहम कदम है। 2017 में शुरू हुए डोकलाम विवाद और 2020 में गलवान की घटना के बाद से बड़े तनाव के बीच दोनों देशों ने सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी थी। दोनों देशों के बीच अब गश्त बहाली और अन्य फैसलों से इस इलाके में शांति स्थापित होने की संभावना बढ़ी है।

असर सुधार हो रहे

सीमा विवाद

फिलहाल	2025 में
रिश्तों में हो रहे सुधार	रिश्ते बेहतर होने के संकेत

नए साल में नई चुनौती: चीन के साथ भारत की मुश्किलें केवल सीमा तक सीमित नहीं हैं। नए साल में हमें साउथ एशिया में चीन के व्यवहार को लेकर भी सतर्क रहने की जरूरत है।

दक्षिण चीन सागर

वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर पॉइंट

दक्षिण चीन सागर में चीन का शुरू से ही विवतनाम के साथ विवाद रहा है, लेकिन व्यापार का बड़ा रूट और इस इलाके में तेल-गैस के भंडार होने की खबरों के बाद इसमें दुनिया के कई देश शामिल हो गए हैं। चीन इस क्षेत्र के सबसे बड़े लगभग 90% हिस्से पर अपना दावेदार करता है। वहीं, QUAD ग्रुप (भारत-अमेरिका-जापान और ऑस्ट्रेलिया) इस एरिया में चीन के बढ़ते दबदबे को लेकर चिंता जताते रहे हैं। इससे साफ होता है कि क्षेत्र में तनाव जारी है। एक्सपर्ट कहते हैं कि इस क्षेत्र में युद्ध जैसे हालात बने तो, पूरी दुनिया को नुकसान होगा।

असर तनाव जारी

ट्रेड रूट डिस्प्यूट

फिलहाल	2025 में
स्टेटस को बरकरार	क्षेत्र में विवाद बढ़ने की आशंका

2025 में बढ़ सकता है विवाद: चीन इस क्षेत्र में किसी दूसरे का दखल बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ऐसे में 2025 में इस क्षेत्र में विवाद और बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं।

भारत और पाकिस्तान

...इस जंग की कोई सुबह नहीं?

असर स्टेटस को

सीमा विवाद

फिलहाल	2025 में
हालात स्थिर, आतंकी हमले जारी	रिश्ते सुधरने की उम्मीद नहीं

भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते 1947 में आजादी के बाद से ही तनावपूर्ण रहे हैं। आतंकवाद, बॉर्डर पर झड़प और राजनीतिक मतभेदों ने दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित किया है। 2024 में दोनों देशों के रिश्ते में कोई गरमाहट नहीं दिखी है। सीमा पर भी हालात सामान्य हैं, लेकिन पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ नरमी बरतकर इस साल भी भारत को चोट पहुंचाने की अपनी कोशिश जारी रखे हुए है।

आतंकियों पर ऐक्शन से सुधर सकते हैं रिश्ते: एक ही उपाय है कि पाकिस्तान आतंकियों पर ऐक्शन ले, जो रिश्तों में सुधार के लिए भारत की प्रमुख मांग है।

आर्मीनिया और अजरबैजान

वॉर से टूटी दोनों देशों की कमर

असर स्टेटस को

इंटरस्टेट वॉर

फिलहाल	2025 में
दोनों देशों के बीच हालात सुधर रहे	दोनों में समझौते की उम्मीद

विवादित नागोर्नो-कराबख (Nagorno-Karabakh) क्षेत्र को लेकर आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच हिंसक जंग ने दोनों को नुकसान पहुंचाया है। दोनों के बीच रुक-रुक कर हमले और मौत की खबरें आती रही हैं। इस क्षेत्रीय विवाद और जातीय संघर्ष ने नागोर्नो-कराबाख क्षेत्र के आर्थिक-सामाजिक और राजनीतिक विकास को भी खासा प्रभावित किया है।

नया साल, नई शुरुआत की उम्मीद: एक्सपर्ट कहते हैं कि पुराना तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन 2025 में दोनों के बीच संबंध सुधरने के हालात बन रहे हैं।

2025 में ये पांच फैसले तय करेंगे भविष्य की दिशा

इस साल भी ये मुद्दे चर्चा में रहे, राजनीतिक पार्टियों ने जनता को लुभाने के लिए इनका खूब इस्तेमाल किया

2024 समाप्त होने को है। आने वाले नए साल में हम कुछ बड़े फैसलों का इंतजार करेंगे, जिनका व्यापक असर देश की राजनीति और इसके आसपास पर पड़ने वाला है। इसके परिणाम सालों तक दिखेंगे। 2025 में होने वाले ऐसे ही 5 बड़े फैसलों पर नरेन्द्र नाथ की रिपोर्ट...

1- जनगणना

साल 2025 का आगाज एक बहुप्रतीक्षित फैसले से हो सकता है और वह है देश में जनगणना। जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड और अन्य कारणों से इसे टलना पड़ा। देश में नई आर्थिक और सामाजिक नीतियों का निर्धारण करने के लिए जनगणना बेहद अहम है। यह जनगणना इसलिए भी मील का पत्थर साबित होगी क्योंकि इससे यह तय होगा कि जातियों की गणना होगी या नहीं। विपक्ष इस मुद्दे पर अड़ा हुआ है, जबकि सरकार इसपर स्पष्ट रुख अपनाने से बच रही है। इसके अलावा, जनगणना को एनआरसी और अन्य मुद्दों से भी अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ा जा रहा है। किसी भी सूरत में, देश में अगली जनगणना का असर कई सालों तक दिखेगा।

2- परिसीमन

साल 2025 में देश में लोकसभा के लिए नए सिरे से परिसीमन प्रक्रिया शुरू होनी है। परिसीमन के बाद लोकसभा में चुने जाने वाले सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन, इसका दूसरा पहलू भी है। इससे बड़ा विवाद भी पैदा हो सकता है। परिसीमन से पहले ही उत्तर बनाम दक्षिण भारत का विवाद शुरू हो चुका है। दक्षिण भारतीय राज्यों को परिसीमन में नुकसान होने की आशंका है और वे इसके लिए कानूनी और सियासी आंदोलन की रूपरेखा अभी से बनाने लगे हैं। ऐसे में परिसीमन और इसके इर्द-गिर्द होने वाली घटनाएं 2025 की सबसे अहम खबर हो सकती हैं।

3- एक देश एक चुनाव

अगले साल 'एक देश, एक चुनाव' को लेकर भी बड़ा फैसला हो सकता है। इसी साल के अंत में केंद्र सरकार ने इससे जुड़े बिल का ड्राफ्ट तैयार कर उसे संसद के सामने पेश किया। अब अगले साल इसपर देशव्यापी मंथन के बाद इसे कानूनी रूप दिया जा सकता है। अगर 'एक देश, एक चुनाव' कानून के रूप में लागू हो गया, तो इसका बड़ा असर आने वाले सालों में देखा जा सकता है। पूरे देश की सियासत में इस कानून के प्रभाव से बदलाव की संभावना है।

4- वक्फ पर नया कानून

अगले साल वक्फ बोर्ड को लेकर संसद में नया कानून पास हो सकता है। हालांकि, केंद्र सरकार ने इस साल इससे जुड़े बिल को पास कराने की कोशिश की थी, लेकिन विपक्ष और सहयोगी दलों के दबाव के बाद इसे जेपीसी के पास भेज दिया गया। अब एनडीए सरकार किसी भी सूरत में साल की शुरुआत में कानून में बदलाव को मंजूरी देना चाहती है। अगर यह कानून पास हुआ, तो इसके व्यापक प्रभाव होंगे और पूरे देश में इसका असर देखा जा सकता है। वक्फ की संपत्ति को लेकर कई मसले सामने आ सकते हैं, जिसका असर राजनीति पर भी पड़ेगा।

5- फ्रीबीज का विस्तार

पिछले दो-तीन सालों में देश में मुफ्त की कल्याणकारी योजनाओं (फ्रीबीज) का आक्रामक रूप से विस्तार देखा गया है। मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में चुनावी लाभ मिलने के बाद अब आने वाले वर्ष (2025) को इन योजनाओं के लिए मेरा का ब्रेक साल मान जा रहा है। क्या अब ऐसी योजनाएं हर राज्य में लागू होंगी? क्या केंद्र सरकार भी इन योजनाओं के दबाव में आएगी? क्या इसका असर देश के वित्तीय हालात पर पड़ेगा? क्या चुनावी में जीत की गारंटी ऐसी योजनाओं से मिलने वाली है? इन सभी सवालों का जवाब 2025 में मिलेगा। जो भी फैसला होगा, वह देश की आर्थिक नीति को तय करेगा।

हिंदी में गगन गिल और इंग्लिश में किरे को साहित्य अकादमी पुरस्कार

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

हिंदी के लिए गगन गिल की कविता पुस्तक 'मैं जब तक आई बहार' और इंग्लिश के लिए इंस्टॉन किरे के उपन्यास 'स्पॉटेड नाइट्स' को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। बुधवार को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई। साहित्य अकादमी के सचिव के. श्रीनिवासराव ने बताया कि पुरस्कार 21 भाषाओं के लिए घोषित किए गए हैं, जिनमें आठ कविता संग्रह, तीन उपन्यास, दो कहानी संग्रह, तीन निबंध, तीन साहित्यिक आलोचना, एक नाटक और एक शोध की पुस्तकें शामिल हैं। बांग्ला, डोगरी और उर्दू में पुरस्कारों की घोषणा बाद में की जाएगी। 8 मार्च 2025 को दिल्ली में एक समारोह में पुरस्कार दिए जाएंगे।

गगन गिल

21 भारतीय भाषाओं की निर्णायक समितियों की अनुशंसा पर पुरस्कारों के लिए किताबें चुनी गई हैं। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक की अध्यक्षता में आयोजित अकादमी के कार्यकारी मंडल की बैठक में बुधवार को इन्हें अनुमोदित किया गया। कविता संग्रह के लिए समीर रावी (असमिया), द्रिलीप झावेरी (गुजराती), गगन गिल (हिंदी), के. जयकुमार (मलयालम), हाओबम सत्यबती देवी (मणिपुरी), फॉल कौर (पंजाबी), मुकुट मणिराज (राजस्थानी), दीपक कुमार शर्मा (संस्कृत) की किताबों को चुना गया है। अरन राजा (बोडो), इंस्टॉन किरे (अंग्रेजी), सोहान कॉल (कश्मीरी) को अपने उपन्यास के लिए यह पुरस्कार मिलेगा। कहानी संग्रह के लिए सुब्ब बगल (नेपाली), हूंदराज बलवाणी (सिंधी) और निबंध के लिए मुकेश थली (कोंकणी), महेन्द्र मलेगिया (मैथिली), बैष्णव चरण खामरा (ओड़िआ) की पुस्तकें चुनी गई हैं। साहित्यिक आलोचना के लिए के.जी. नारायण (कन्नड), सुधीर माधव कौशिक ने कहा कि कुमुदा ने नारी उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण काम किए हैं। अजीत कौर ने कहा कि यह उनके लिए बहुत खुशी का अवसर है और वे बेहद सम्मानित महसूस कर रही हैं। अजीत लेखिका, पत्रकार, अर्थशास्त्री, सांस्कृतिक प्रचारक, सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। 16 नवंबर 1934 में लाहौर में जन्मी अजीत कौर विभाजन के बाद से दिल्ली बस गईं।

अजीत कौर

पंजाबी लेखिका अजीत कौर को सर्वोच्च सम्मान

शिरा, नई दिल्ली : साहित्य अकादमी ने बुधवार को प्रतिष्ठित पंजाबी लेखिका अजीत कौर को अपने सर्वोच्च सम्मान 'महत्तर सदस्यता' से सम्मानित किया। सम्मान स्वरूप दिया जाने वाला ताम्र फलक और अंगवस्त्र साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक ने दिया और अकादमी की उपाध्यक्ष कुमुदा शर्मा ने स्वागत किया। अकादमी के सचिव के. श्रीनिवासराव ने प्रशस्ति पत्र पढ़ा। रसाल (मराठी), गगन गिल (हिंदी), के. जयकुमार (मलयालम), हाओबम सत्यबती देवी (मणिपुरी), फॉल कौर (पंजाबी), मुकुट मणिराज (राजस्थानी), दीपक कुमार शर्मा (संस्कृत) को किताबों को चुना गया है। अरन राजा (बोडो), इंस्टॉन किरे (अंग्रेजी), सोहान कॉल (कश्मीरी) को अपने उपन्यास के लिए यह पुरस्कार मिलेगा। कहानी संग्रह के लिए सुब्ब बगल (नेपाली), हूंदराज बलवाणी (सिंधी) और निबंध के लिए मुकेश थली (कोंकणी), महेन्द्र मलेगिया (मैथिली), बैष्णव चरण खामरा (ओड़िआ) की पुस्तकें चुनी गई हैं। साहित्यिक आलोचना के लिए के.जी. नारायण (कन्नड), सुधीर रसाल (मराठी), पेनुगोंडा लक्ष्मीनारायण (तेलुगु) और नाटक में महेश्वर सेरोन (संतोली) और शोध में ए. आर. केंकटाचलपति (तमिल) को किताब को साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार पिछले पांच साल यानी, 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2022 के दौरान पहली बार प्रकाशित पुस्तकों पर दिए गए हैं। इसके अलावा साहित्य अकादमी ने फैसला लिया है कि 2025 से इस पुरस्कार के लिए लेखक खुद आवेदन दे सकेंगे। साहित्य अकादमी के सचिव ने बताया कि रचनाकार या उनकी ओर से प्रकाशक या उनका कोई भी परिचित आवेदन कर सकेगा।

भारत-श्रीलंका संबंध

सामयिक आश्वासन

श्रीलंका ने नई दिल्ली को आश्वस्त किया है कि वह अपनी धरती का प्रयोग भारतीय सुरक्षा को खतरा पैदा करने के लिए नहीं करेगा। यह निश्चित रूप से भारत सरकार के लिए बहुत अच्छी खबर है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा है कि उनका देश किसी को उनके क्षेत्र का प्रयोग भारतीय सुरक्षा को खतरा पैदा करने के लिए नहीं करने देगा। यह आश्वासन ऐसे समय आया है जब चीन आक्रामक रूप से भारत को निशाना बनाने के लिए 'मिशन इंडियन ओसेन' चला रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ नई दिल्ली में वार्ता के बाद एक संयुक्त बयान में कोलंबो की स्थिति स्पष्ट की है। यह आश्वासन भारत-श्रीलंका संबंधों में महत्वपूर्ण घटना की तरह देखा जा रहा है क्योंकि चीन श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह का प्रयोग नौसैनिक निगरानी और जासूसी जहाजों को खड़ा करने के लिए कर रहा है जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज युवान वांग 5 भी शामिल है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति नई दिल्ली के लिए चिन्ता का विषय है। हंबनटोटा बंदरगाह अब चीन को 99 साल के पट्टे पर दिया गया है क्योंकि श्रीलंका चीन का कर्ज नहीं अदा कर पा रहा था और यह चीनी नौसैनिक कार्रवाइयों का केन्द्र बन गया है। पिछले दो साल में बीजिंग ने वहां कई बार 25,000 टन क्षमता वाले उपग्रह व मिसाइल ट्रैकिंग जहाज युवान वांग 5 को कई बार खड़ा किया। उत्कृष्ट ट्रैकिंग व संचार व्यवस्थाओं से लैस यह जहाज संभवत: इस क्षेत्र की उपग्रह व मिसाइल गतिविधियों पर नजर रखता है और भारत के लिए रणनीतिक चुनौती पैदा करता है।

2022 में भारतीय सरोकारों को देखते हुए श्रीलंका ने थोड़े समय के लिए युवान वांग 5 की तैनाती रोक दी थी, पर अंतत: उसे 'आवश्यक आपूर्ति' के बहाने खड़े होने की अनुमति मिल गई। इसके बाद से चीनी निगरानी जहाजों ने नियमित रूप से हिंद महासागर में गश्त की है जिससे इस क्षेत्र में बीजिंग के रणनीतिक इरादों के बारे में भारत में संदेह पैदा होता है। भारत और श्रीलंका के बीच हुआ समझौता यह सुनिश्चित करने के लिए है कि श्रीलंका के समुद्र समेत उसके क्षेत्र का प्रयोग किसी प्रकार भारत की सुरक्षा या क्षेत्रीय शांति को खतरा पैदा करने के लिए नहीं होगा। यह नई दिल्ली के लिए स्वागत योग्य राहत है जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र में स्थायित्व बनाए रखने को महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता माना गया है। यह निश्चित रूप से रातोंरात नहीं हुआ है। भारत ने 2022 के आर्थिक संकट के दौरान श्रीलंका का लगातार समर्थन किया है जिससे दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत हुए हैं। राष्ट्रपति दिसानायके ने भारत की सामयिक सहायता के लिए धन्यवाद दिया है जिसने सर्वाधिक चुनौती वाले एक समय में श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। जहां तक चीन का संबंध है, यह श्रीलंका का प्रयोग पूरी तरह भारत को घेरने तथा हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए कर रहा है। श्रीलंका में चीन का प्रभाव खासकर कोलंबो द्वारा हंबनटोटा बंदरगाह परियोजना के लिए 1.7 बिलियन डालर का कर्ज न अदा करने के बाद बढ़ा है। भारत ने लगातार श्रीलंका में चीनी निवेशों और गतिविधियों के रणनीतिक प्रभावों पर चिन्ता प्रकट की है। इस पृष्ठभूमि में श्रीलंका के राष्ट्रपति का आश्वासन श्रीलंका के इस इरादे का संकेत देता है कि वह क्षेत्रीय स्थायित्व सुनिश्चित करते हुए दोनों क्षेत्रीय शक्तियों के बीच संबंधों में संतुलन रखना चाहता है। इस समझौते से यह तथ्य भी रेखांकित होता है कि कोलंबो भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थायित्व को महत्व देते हुए आने वाले वर्षों में भारत-श्रीलंका के बीच संबंधों को ज्यादा मजबूत रणनीतिक स्वरूप देना चाहता है।

कीटनाशकों से विषाक्त होती मिट्टी

पंजाब में खेती एक भयानक यथार्थ का सामना कर रही है। उसकी जीवनरेखा, यानी मृदा खतरनाक जहरीले कीटनाशकों से अत्यधिक उच्च स्तर तक प्रदूषित हो गई है।

ए एस मित्तल
(लेखक, उद्योग क्षेत्र से जुड़े हैं)

समय आ गया है कि पंजाब अपने कृषि क्षेत्र के कटु यथार्थ का सामना करे जो एक भयानक विभीषिका बन गया है। भटिंडा, मानसा और लुधियाना जिलों में खेतों की मिट्टी के 60 प्रतिशत नमूनों में जहरीले कीटनाशकों के अंश बड़ी मात्रा में पाए गए हैं। इनमें घातक रसायन इंडोसल्फान व कार्बोफ्यूरान शामिल हैं और इनका स्तर किसी प्रकार सुरक्षित नहीं कहा जा सकता है। यह केवल चेतावनी न होकर पूरी तरह से सामने आया गंभीर संकट तथा टिक-टिक करता टाइम बम है।

कीटनाशकों और उर्वरकों के इस गैरजिम्मेदार प्रयोग से पंजाब के खेत बंजर हो रहे हैं। 5 दिसंबर को 'विश्व मृदा दिवस' पर हमें तेजी से विघटित होती कृषि व्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है, जबकि दुनिया 'मृदा की देखभाल: उपाय, निगरानी एवं प्रबंधन' की बात कर रही है। ऐसे में पंजाब में पागलपन खतरनाक स्तर तक पहुंच रहा है। एक समय उर्वर भूमि तेजी से बंजर जमीन में बदल रही है और यह तबाह होता जा रहा है। जहरीले रसायन केवल मृदा में ही नहीं रहते हैं, बल्कि वे हमारी खाद्य श्रृंखला में शामिल हो जाते हैं तथा खाने के हर कौर के साथ धीरे-धीरे हमारे भीतर जहर भरते हैं। यह प्रक्रिया यहीं नहीं थमती है, बल्कि जहरीले रसायनों के अवशेष हमारे डीएनए में प्रवेश कर जाते हैं और इस प्रकार हमारे बच्चों तथा उनके भी बच्चों के लिए जेनेटिक परिवर्तन की जहरीली श्रृंखला पीछे छोड़ते हैं। ऐसे में हम ऐसे भविष्य का सामना कर रहे हैं जहां स्वास्थ्य पर खतरों और जेनेटिक विघटन की आशंका मौजूद है।

यह भयानक विभीषिका अनेक पीढ़ियों तक जा सकती है। हम न केवल वर्तमान पीढ़ी का स्वास्थ्य नष्ट कर रहे हैं, बल्कि हम अपने बच्चों को भी अपनी मूर्खता और लालच के कारण बरबादी की ओर धकेल रहे हैं। भावी पीढ़ियों का भविष्य ही संकट में पड़ गया है और हमारी निष्क्रियता के हर क्षण के साथ अपरिवर्तनीय जेनेटिक परिवर्तनों का खतरा मंडरा रहा है। समय आ गया है कि हम जागें, यथार्थ से मुंह चुराना बंद करें तथा संकट का सीधे-सीधे सामना करें। ऐसा न होने पर भावी पीढ़ियों का जीवन भी संकट में पड़ जाएगा। भारत ने कीटनाशकों पर नियामक ढांचे की स्थापना 1968 में की थी, पर यह दयनीय रूप से पुरानी पड़ गई है और आधुनिक चुनौतियों का सामना करने में पूर्णत: विफल है जिससे कृषि-रसायनों के खतरनाक दुरुपयोग का खतरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि, इस ढांचे में संशोधन के प्रयास 2008 से जारी हैं, पर किसानों, उपभोक्ताओं और पर्यावरण की सुरक्षा में काफी कमियां हैं। 1968 के कीटनाशक कानून तथा 1971 के कीटनाशक नियमों में समग्र परिवर्तनों की आवश्यकता है ताकि वे कीटनाशकों के दुरुपयोग से पैदा बहुआयामी संकटों का सामना कर सकें।

कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2020-पीएनबी को पुराने पड़ चुके कानूनों का स्थान लेने के लिए लाया गया था, पर इसमें महत्वपूर्ण सरोकारों को संबोधित किया जाना चाहिए। इस विधेयक में कीटनाशक पंजीकरण व लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को रेखांकित किया गया है, पर इसमें इनके खतरनाक प्रभाव से किसानों को भी समुचित सुरक्षा दी जानी चाहिए। 'पेस्टीसाइड एक्शन नेटवर्क'-पैन इंटरनेशनल के आंकड़ों से निराशाजनक तस्वीर सामने आती है। दुनिया भर में कीटनाशक विषाक्तता की दुर्घटनाओं से हर साल लगभग 11,000 लोगों की मौत होती है जिसमें अकेले भारत में खतरनाक रूप से 6,000 लोग हताहत होते हैं। इन आंकड़ों से स्वाभाविक रूप से कीटनाशक प्रयोग व्यवहारों और सुरक्षा उपायों में व्यापक कमियां उजागर होती हैं। अक्सर किसानों तथा ग्रामीण समाज को रसायनों के प्रयोग का खामियाजा भुगतना पड़ता है। यह खासकर गहन कृषि वाले क्षेत्रों, जैसे पंजाब में बहुत गंभीर है। धान और गेंहूं की खेती में कीटनाशक प्रयोग की दर खतरनाक रूप से बहुत ऊंची है। इसमें औसतन 77 किलो प्रति हेक्टर कीटनाशक प्रयोग होता है, जबकि राष्ट्रीय औसत 62 किलो प्रति हेक्टर है। कीटनाशक उपभोग में भारत में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद पंजाब का तीसरा स्थान है। केन्द्रीय स्वायल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट-सीएसएसआरआई के एक अध्ययन से पता चला है कि भारत में 6.74 मिलियन हेक्टर जमीन लवणीयता की शिकार है और कृषि-रसायनों के प्रयोग से स्थिति और खराब होती है।

लगातार कीटनाशकों के प्रयोग से 'माइक्रोबियल बायोमास' घट कर 30-50 प्रतिशत रह जाता है जिससे मृदा की उर्वरता प्रभावित होती है तथा जमीन फसलों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने में विफल हो जाती है। ऐसे में आधुनिक कृषि के लिए कीटनाशकों पर कठोर नियंत्रण जरूरी है जिसमें कीटनाशक, फफूंदनाशक या खरपतवार नाशक शामिल हैं।

उनकी विषाक्त प्रकृति के कारण उनके पूरे जीवनचक्र पर ही कठोर नजर रखना बहुत जरूरी हो जाता है जिसमें उत्पादन से लेकर प्रयोग तक शामिल हैं। वर्तमान नियामक ढांचे में सामने आ रहे विधविज्ञान आंकड़ों के आधार पर पंजीकृत कीटनाशकों की समय-समय पर समीक्षा में अक्षमता दिखती है। इस लापरवाही के कारण आम जनता के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा पैदा होता है। यह खासकर ऐसे देश में और गंभीर हो जाता है जहां कीटनाशकों का ठीक से प्रयोग न करना बहुत व्यापक हो गया है। पिछले तीन दशकों में कीटनाशकों के बेलगाम प्रयोग पर नियंत्रण का प्रयास नहीं हुआ है। इनका प्रयोग बढ़ने का कारण अक्सर आक्रामक मार्केटिंग तथा अधिक फसल पैदा करने के लिए कीटनाशकों के अधिकाधिक प्रयोग की रणनीति है।

वर्तमान समय में प्रशिक्षण प्रयास तेज करने की जरूरत है। 1994-95 से 2020-21 के बीच कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के प्लांट प्रोटेक्शन विभाग ने समन्वित कीटनाशक प्रबंधन-आईपीएम में केवल 585,000 किसानों को प्रशिक्षण दिया। यह 150 मिलियन से अधिक किसानों वाले देश में बहुत कम है। कीटनाशक प्रबंधन के अंतरराष्ट्रीय कोड के अनुसार सरकारों तथा उद्योगों को किसानों तथा खुदरा विक्रेताओं को समग्र प्रशिक्षण एवं सूचनाओं से लैस करना चाहिए। इन संस्तुतियों का प्रभावी क्रियान्वयन होना चाहिए। अक्सर किसानों के संपर्क का एकमात्र साधन खुदरा विक्रेता होते हैं जो भ्रामक या आधी-अधूरी सूचनायें देते हैं। डेटा का उपयुक्त संग्रह न करना भी भारत में नियामक व्यवस्था के लिए समस्यायें खड़ी करता है।

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो-एनसीआरबी दस्तावेजों के अनुसार कीटनाशकों के कारण होने वाली मौतें तभी पंजीकृत होती हैं जब उनको मेडिको-लीगल मामलों के रूप में दर्ज किया जाए। इससे कीटनाशकों के गैर-संस्थागत हानिकारक प्रयोग तथा भयानक स्वास्थ्य दुष्प्रभावों के असंख्य मामले दर्ज नहीं हो पाते हैं। इसके कारण नीति निर्माण तथा जवाबदेही में बाधा पैदा होती है। भारत के कीटनाशक नियमन व्यवस्था में समुचित शिकायत निवारण व्यवस्था की कमी सामने आती है। किसानों तथा खेतिहर मजदूरों को कीटनाशकों के दुष्प्रभावों के मामले में न्याय व मुआवजा प्राप्त करने में भरी खर्च करना पड़ता है तथा इसकी प्रक्रिया बहुत जटिल है।

इसके अलावा राज्य सरकारें खतरनाक कीटनाशकों पर केवल अस्थाई प्रतिबंध लगा सकती हैं जिसकी अवधि केवल 60 दिन होती है। इससे बहुत बड़ा समुदाय इसके जोखिमों का शिकार बनता रहता है। खेतिहर मजदूरों को कीटनाशकों के दुरुपयोग का ज्यादा जोखिम उठाना पड़ता है, जबकि उनको स्वास्थ्य जोखिम से निपटने के लिए सुरक्षा उपकरणों को खासकर गरम और नम माहौल वाले कृषि क्षेत्रों में जरूरी है। हालांकि, उपभोक्ता संरक्षण कानून सिद्धान्त रूप से किसानों पर भी लागू होता है, पर कीटनाशक निर्माताओं द्वारा भ्रामक लेबिलों या अधोमानक उत्पादों के प्रयोग के खिलाफ कानूनी लड़ाई आसान नहीं है।

ऐसे में भारत को एक किसान-केन्द्रित कानूनी ढांचा तैयार करना चाहिए जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो क्योंकि यही कृषि को सुरक्षित और टिकाऊ बनाने का एकमात्र रास्ता है। सरकार को खतरनाक कीटनाशकों पर तत्काल प्रतिंध लगा कर किसानों के स्वास्थ्य तथा उपभोक्ताओं की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक लागू करने चाहिए।

प्रगति के पथ पर भारतीय अर्थव्यवस्था

> लगातार मुद्रास्फीति, बैंकिंग क्षेत्र में मंदी और पर्यावरण संबंधी चिंताओं जैसी चुनौतियां बाधाएं खड़ी करती रहती हैं।

कजलीन कौर
(लेखिका, सह प्रोफेसर हैं)

भारत ने खुद को जी20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर लिया है, जिसकी अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 6.5 प्रतिशत-7 प्रतिशत है। यह उल्लेखनीय प्रक्षेपवक्र वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की आर्थिक लचीलापन और अपार क्षमता को रेखांकित करता है। वर्ष 2024 भारत के आर्थिक परिदृश्य की एक ज्वलंत तस्वीर प्रस्तुत करता है, जिसमें उल्लेखनीय उपलब्धियां और उभरती चुनौतियाँ शामिल हैं।

प्रगति के सबसे महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक रोजगार में पर्याप्त सुधार है। बेरोजगारी दर 2017 में 6 प्रतिशत से घटकर 2024 में प्रभावशाली 3.2 प्रतिशत हो गई है, जो सभी क्षेत्रों में मजबूत रोजगार सृजन को दर्शाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में भी नाटकीय उछाल आया है, जो 2024-25 की पहली छमाही में सालाना आधार पर 45 प्रतिशत बढ़कर 29.79 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसमें सेवाओं, दूरसंचार और फार्मास्यूटिकल्स में प्रमुख प्रवाह शामिल है। इस गति को आगे बढ़ाते हुए, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 704.89 बिलियन डॉलर हो गया, जो अकेले इस वर्ष 87.6 बिलियन डॉलर की वृद्धि से प्रेरित है। इस वृद्धि में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में 10.468 बिलियन डॉलर की वृद्धि और सर्वाच्च भंडार में 2 बिलियन डॉलर की वृद्धि शामिल है, जो अब 65.7 बिलियन डॉलर हो गया है।

भारत का फिनटेक क्षेत्र वैश्विक मंच पर चमकना जारी रखता है, जो यूएसए और यूके के बाद तीसरी सबसे बड़ी फिनटेक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थान पाता है। देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार भी है, जिसका बाजार पूंजीकरण 4.33 ट्रिलियन डॉलर है, जो हांगकांग से आगे है। डिजिटल भुगतान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर

एकीकृत भुगतान इंटरफ्रेस के साथ हासिल किया गया, जिसके कारण 2024 में लेनदेन मूल्य 200 ट्रिलियन रुपये तक पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष यह 139 ट्रिलियन रुपये था। भारत ने वैश्विक मंच पर भी अपनी ऋ क्षमता का प्रदर्शन किया, फ्रांस के साथ डिजिटल भुगतान समझौते के हिस्से के रूप में पेरिस के एफिल टॉवर में इस प्रणाली की शुरुआत की। वस्तु एवं सेवा कर (जस्त्र) राजस्व संग्रह भी अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया, जो 2.10 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया - जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.4 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि है। यह वृद्धि घरेलू लेनदेन में 13.4 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि और आयात में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि से प्रेरित थी, जो भारत के कर बुनियादी ढांचे की ताकत को दर्शाता है। इन आशाजनक आंकड़ों के बीच, कुछ चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति लगातार उच्च बनी हुई है, जो 5 प्रतिशत से अधिक है। बैंकिंग क्षेत्र में मंदी देखी गई है, नवंबर 2024 में ऋण वृद्धि पिछले वर्ष के 20.6 प्रतिशत से घटकर 11 प्रतिशत रह गई। जमा वृद्धि में भी कमी आई है, बैंकों ने अप्रैल और नवंबर के बीच 13.8 लाख करोड़ रुपये जमा किए हैं, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 16.1 लाख करोड़ रुपये जमा हुए थे। जवाब में, भारतीय रिजर्व बैंक ने नकदी प्रवाह में सुधार और ऋण वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए दिसंबर में नकद आरक्षित अनुपात को 50 आधार अंकों से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया। गुणात्मक संकेतक मिश्रित तस्वीर पेश करते हैं। यूएनडीपी लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 14 पायदान ऊपर चढ़ा, जो लैंगिक अंतर को पाटने में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है।

इसने वैश्विक नवाचार सूचकांक में भी अपनी स्थिति में सुधार किया, जो उद्यमशीलता गतिविधि, जीवंत स्टार्टअप और सफल सार्वजनिक-निजी भागीदारी द्वारा संचालित 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 40वें से 39वें स्थान पर पहुंच गया। मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 ने भारत को 193 देशों में 134वें स्थान पर रखा, जो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और सकल राष्ट्रीय आय में वृद्धि को दर्शाता है। हालाँकि, हैप्पीनेस इंडेक्स में कोई प्रगति नहीं देखी गई, जहाँ भारत 126वें स्थान पर बना हुआ है, जिसका मुख्य कारण वृद्ध नागरिकों में असंतोष, कथित भेदभाव और खराब स्वास्थ्य मीट्रिक हैं। इसके अलावा, भारत पर्यावरण प्रदर्शन में संघर्ष कर रहा है, 180 देशों में से 176वें स्थान पर है। वायु गुणवत्ता, जैव विविधता हानि और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन जैसी चुनौतियों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

जैसे-जैसे भारत इन जटिलताओं से निपट रहा है, यह महत्वपूर्ण बदलावों से भी गुजर रहा है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है, और भारत ऋ नेतृत्व में बदलाव देख रहा है, जिसमें संजय मल्होत्रा शक्तिकांत दास के कार्यकाल के बाद 26वें गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। जबकि वित्त वर्ष 2024-25 का अंतिम मूल्यांकन अभी भी लंबित है, भारत की विकास कहानी एक उज्जवल भविष्य के लिए आशावाद और 'विकसित भारत 2047' के दृष्टिकोण के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है।

आप की बात

अंत भला तो सब भला

महाराष्ट्र में भाजपा नीत 'महायुति' को असाधारण जनादेश मिला। भाजपा नीत महायुति को विधानसभा चुनावों में भारी विजय मिली और वह 288 सदस्यों वाले सदन में 230 सीटें जीतने में सफल रही। शिंदे की शिवसेना तथा अजीत पवार की रांकापा ने भी बेहतर प्रदर्शन किया। शिवसेना को 57 और रांकापा को 41 सीटों पर विजय मिली। इस परिणाम से कांग्रेस नीत 'महाविकास अघाड़ी'-एमवीए को भारी निराशा मिली। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का राज्य विधानसभा में प्रदर्शन अब तक का एक सबसे खराब प्रदर्शन रहा और वह केवल 16 सीटें जीत सकी। शरद पवार के नेतृत्व वाली रांकापा को केवल 10 सीटें मिलीं, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को केवल 20 सीटों पर सफलता मिली। लेकिन इस सफलता के बावजूद चुनाव पश्चात परिदृश्य उथलपुथल से भरा दिख रहा है। कहा जाता है कि महायुति के दो गठबंधन सहयोगियों के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर काफी टकराव रहा। वैसे भी भाजपा के महाराष्ट्र में सर्वोच्च नेता के रूप में फडनवीस के व्यापक रूप से मुख्यमंत्री पद पर आने की आशा थी। शिवसेना ने गठबंधन की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद अपने पास रखने के इच्छुक थे। लेकिन कई दिन चली वार्ताओं के बाद वे अंतत: फडनवीस को अपना स्थान देने के लिए तैयार हो गए।

- **सुचिता शांडिल्य**, आगरा

मानसिक स्वास्थ्य का महत्व

जिस तरह हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, उसी तरह हमारे मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। घर में एक खुशहाल, सहायक और समझदार माहौल बनाने में माता-पिता की अहम भूमिका होती है। चिंता, डर और अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आम हैं, और ये बदमाशी, पारिवारिक संघर्ष, स्कूल या जीवन में बदलाव, शैक्षणिक तनाव या यहां तक कि कठोर दंड के कारण उत्पन्न हो सकती हैं। ये चुनौतियां बच्चों को अलग-थलग, क्रोधित या अपनी पढ़ाई पर ध्यान न देने का एहसास करा सकती हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि परामर्शदाताओं, चिकित्सकों या माता-पिता या शिक्षकों जैसे विश्वसनीय वयस्कों से मदद लेना ताकत का संकेत है, कमजोरी का नहीं। आज, पांच में से एक व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहा है। थेरेपी जैसे पेशेवर समर्थन भावनात्मक भलाई में काफी सुधार कर सकते हैं। योग, खेल और ध्यान जैसी गतिविधियां भी मन को शांत करने और तनाव को कम करने के लिए प्रभावी हैं। इसके अतिरिक्त, माइंडफुलनेस का अभ्यास करना - वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना, बच्चों को अधिक शांतिपूर्ण और केंद्रित महसूस करने में मदद कर सकता है। अच्छी आदतें, जैसे पर्याप्त नींद लेना, स्वस्थ भोजन खाना और हाइड्रेटेड रहना, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों का समर्थन करती हैं।

- **सुनील वार्ष्णेय**, कानपुर

बांग्लादेश पर लगाम लगे

भारत के लिए बांग्लादेश सीमा सुरक्षा तथा क्षेत्रीय स्थायित्व बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण साझीदार है। दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध हैं जिससे लंबे समय तक गतिरोध संकट का कारण बन सकता है। लेकिन वर्तमान समय में परस्पर विश्वास लगभग समाप्त हो गया है। भारत ने बार-बार बांग्लादेश से अनुरोध किया है कि वह अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी हिंसा से निपटे। दूसरी ओर बांग्लादेश के अधिकारियों का कहना है कि भारतीय मीडिया का एक हिस्सा जानबूझ कर गलत सूचनायें फैलाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छे संबंध रहे हैं, ऐसे में दोनों देशों को तत्काल तनाव घटाने के प्रयास करने चाहिए। हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी से पैदा तनाव तत्काल दूर करने के प्रयास होने चाहिए। उनको जल्दी से जल्दी रिहा करने के साथ ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यक अधिकारों के उल्लंघन पर उठ रहे सवालों को संबोधित करना होगा। भारत की जनता बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर स्वाभाविक प्रतिक्रिया करती है, ऐसे में बांग्लादेश को अपने देश में कट्टरपंथियों पर कठोरता से लगाम लगानी चाहिए। भारत के सामने बांग्लादेश की हैसियत कुछ नहीं है अत: भारत लगाम कसने में सक्षम है।

- **सीमांत कक्कड़**, लखनऊ

कांग्रेस करे पुनर्विचार

हालिया चुनाव परिणाम दलगत विकास में खोए अवसरों का खुलासा भी करते हैं। यदि कांग्रेस ने अतीत की गलतियों से बेहतर सबक सीखे होते और आवश्यक परिवर्तन किए होते तो उसका प्रदर्शन बेहतर हो सकता था। कांग्रेस ने चुनाव-पश्चात स्थितियों पर वैसे विश्लेषण नहीं किए जैसे पचमढ़ी या शिमला सम्मेलनों में किए गए थे। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस विपक्ष के नेता राहुल गांधी तथा उनके द्वारा चयनित सहयोगियों के नियंत्रण में है। हालांकि, राहुल गांधी ने हालिया विधानसभा चुनावों में कड़ी मेहनत की तथा व्यापक अभियान चलाया, पर पार्टी बेहतर नतीजे नहीं दिखा सकी। इन परिणामों से संकेत मिलता है कि उन्होंने अभी हालिया हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम से कोई सबक नहीं सीखा है और वे प्रदेशों में दूसरों को अनदेखा कर केवल एक नेता पर अत्यधिक निर्भर हैं। जनता से संबंध विच्छेद इस बात का स्पष्ट संकेत है कि पार्टी को अपनी रणनीति पर पुन: विचार करना होगा, और अल्पसंख्यकवाद की राजनीति से बाज आना होगा।

- **अजय महावर**, सीतापुर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

1.5 प्रतिवर्ष बढ़ जाएगी भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर, यदि देश में सभी सूचना एक साथ कर जाएं, एक देश-एक चुनाव के लिए बनाई गई कोविन्द समिति की रिपोर्ट के अनुसार।

ब्र. वेदाप्रकाश
असिस्टेंट प्रोफेसर, किरोड़ीमल कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

आजकल

एक साथ चुनाव से समर्थ बनेगा देश

'एक देश-एक चुनाव' की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए केंद्र सरकार ने इससे संबंधित संविधान (129वां) संशोधन विधेयक और इससे जुड़ा एक अन्य विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत कर दिया है। वस्तुतः विकसित भारत के लिए परिवर्तन और नई व्यवस्थाएं आवश्यक हैं। जिस प्रकार भिन्न-भिन्न प्रकार की ढांचागत व्यवस्थाओं का आधुनिकीकरण प्रगति का आधार बनता है, उसी प्रकार 'एक देश-एक चुनाव' भारतवर्ष की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को नया जीवन देने वाला सिद्ध होगा

'एक देश-एक चुनाव' भारत के लोकतंत्र, अर्थतंत्र, समाजतंत्र एवं विकासतंत्र को मजबूती प्रदान करने में सक्षम हो सकता है। फाइल

हमारे देश में ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम आदि स्थानीय निकाय, फिर विधानसभा चुनाव और इसी श्रृंखला में लोकसभा चुनावों की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। देश के कई प्रदेश तो पिछले कई महीने से लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव की प्रक्रिया में ही हैं, ऐसे में क्या वहां जन कल्याण और विकास कार्य सुचारु रूप से हो पाएंगे? वस्तुतः चुनाव की पूरी प्रक्रिया में भिन्न-भिन्न प्रकार के संसाधनों और लोगों की भारी आवश्यकता पड़ती है। 'एक देश-एक चुनाव' की संकल्पना यही है कि ये सभी चुनाव एक साथ अर्थात एक निश्चित समय खंभा में संपन्न हों। एक देश, एक चुनाव विधेयक को मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद मूर्त रूप देने के लिए केंद्र सरकार ने इससे संबंधित संविधान संशोधन विधेयक 129 और इससे जुड़े एक अन्य विधेयक को लोकसभा में पेश कर दिया है। विधेयक को विपक्ष के 198 मतों की तुलना में 269 सदस्यों का समर्थन मिला। प्रस्तुत विधेयक में तीन केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव भी लोकसभा चुनावों के साथ करवाने का प्रविधान है। प्रस्तुत विधेयक से संबद्ध प्रक्रिया अभी जारी है।

संसाधनों की बचत : इस विधेयक के मूल में सरकार का तर्क है कि देश में एक साथ चुनाव कराने से समय, धन और संसाधनों की बचत होगी। साथ ही अलग-अलग चुनावों के चलते बार-बार आदर्श आचार संहिता के कारण होने वाली बाधाओं को भी रोका जा सकेगा। आदर्श आचार संहिता चुनाव अवधि के दौरान विकास कार्यों को भी रोक देती है। इसके विपरीत विपक्ष ने इस प्रस्ताव को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बताया है। क्या विपक्ष का यह विरोध और आरोप तार्किक है? कोविन्द समिति ने 'एक देश-एक चुनाव' की संभावनाएं तलाशने के लिए दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, बेल्जियम आदि सात देशों की चुनाव प्रक्रिया का अध्ययन किया है। साथ ही देश के छोटे बड़े 47 दलों ने समिति के सामने अपनी राय रखी, जिसमें 32 दलों ने इसका समर्थन किया और केवल 15 ने विरोध जताया है।

तथ्य यह भी है कि आजादी के बाद वर्ष 1951-52 से 1967 के बीच लोकसभा के साथ ही राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ होते रहे हैं। अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा आदि अनेक विकसित देशों में भी विभिन्न चुनाव एक साथ ही होते हैं। क्या ऐसे में हर दिन चुनाव की प्रक्रिया विकसित भारत की राह में बाधक नहीं है? इन सबके बीच एक नगरिक के रूप में हमें यह समझने की आवश्यकता है कि समय-समय पर होने वाले चुनावों में भारी खर्च हो रहा है।

एक देश, एक चुनाव पर बनी कोविन्द समिति की रिपोर्ट बताती है कि सभी चुनाव एक साथ होने पर भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) ग्रोथ अगले वर्ष 1.5 प्रतिशत बढ़ जाएगी। आंकड़े यह भी बताते हैं कि सभी चुनाव एक साथ होने से जीडीपी के लिए नेशनल ग्रस फिक्स्ड कैपिटल फारमेशन निवेश का अनुपात करीब 0.5 प्रतिशत बढ़ जाएगा। इसी प्रकार एक साथ चुनाव होने से महंगाई में भी गिरावट आने का अनुमान है। एक देश एक चुनाव के लागू होने से चुनाव प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलेगा और देश के आर्थिक विकास में भी यह मददगार साबित होगा। चुनाव किसी भी स्तर पर हो, उसकी प्रक्रिया लंबी और जटिल होती है, जिसमें लाखों शिक्षक और अन्य कर्मचारी, पुलिस बल एवं सेना के जवान लगते हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक चुनाव में ये कर्मचारी अनेक कार्य दिवस अपने मूल काम से अलग रहते हैं। क्या इसका प्रभाव पढ़ाई, कार्यालयों के कामकाज एवं सुरक्षा व्यवस्था पर नहीं पड़ता है? कई शिक्षकों की ड्यूटी स्कूल से अधिक मतदाता सूची बनाने, मतदान हेतु प्रशिक्षण एवं चुनाव संपन्न करवाने आदि में लगाई जाती है। क्या यह सरकारी खजाने पर भारी बोझ नहीं है?

मतदान के प्रति नीरसता : एक जानकारी के अनुसार, विगत लोकसभा चुनाव में अकेले दिल्ली में लगभग 30 हजार कर्मचारी लगाए गए। इनमें से 20 हजार शिक्षक थे। बार-बार चुनाव की प्रक्रिया मतदाताओं में भी मतदान के प्रति नीरसता लाती है। विगत लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रयास करने के बाद भी मतदान लगभग 60-65 प्रतिशत ही रहा है। यह भी सत्य है कि छोटा-बड़ा प्रत्येक चुनाव अब धनबल, बाहुबल और हिंसा का शिकार होता जा रहा है। चुनाव की प्रक्रिया शुरू होते ही जाति, संप्रदाय एवं क्षेत्रीयता के आधार पर झगड़े आरंभ हो जाते हैं और कई बार तो हत्या एवं दंगों का रूप भी ले लेते हैं। आपराधिक प्रवृत्ति और उससे जुड़े लोग सक्रिय हो जाते हैं, जिससे सामान्य लोगों का जीवन तनाव और संकट में पड़ जाता है। विगत लोकसभा चुनाव इसका प्रमाण हैं।

यह भी सत्य है कि आज भारत को विकसित होने के लिए विकास की गति तेज करनी होगी। विकास योजनाएं बनाने एवं उन्हें क्रियान्वित करने में भी भारी पैसे की आवश्यकता है। फिर जैसे ही स्थानीय, राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व परिवर्तन होता है तो वे योजनाएं रोक दी जाती हैं। विश्व बैंक का कहना है कि विकसित देश बनने के लिए भारत के पास बहुत कम समय है और इस दौरान उसे कई बड़े सुधार करने होंगे। वहीं समूचा विपक्ष लंबे समय से केवल विरोध, भ्रम और भय फैलाने की राह पर है। ऐसे में संसद में चर्चा न करके हंगामे व बहिष्कार में लगे रहना जनकल्याण और विकास के कार्यों को रोकना है। 'एक देश-एक चुनाव' विधेयक अभी संसद में है, उसमें कुछ कमियां हो सकती हैं। विपक्ष का यह दायित्व है कि वह सभी पक्षों पर संसद में विचार करके राष्ट्रहित में इस कार्य में सहयोग करे।

प्रशासनिक बाधाओं को पार करने की चुनौती

मोनिका चौहान
स्वतंत्र टिप्पणीकार

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में पहचाने जाने वाला भारतीय लोकतंत्र चुनावी प्रक्रिया के मामले में अद्वितीय है। यह प्रक्रिया देश के नागरिकों को अपनी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को व्यक्त करने का अवसर देती है। स्वतंत्रता के बाद से ही चुनाव प्रणाली ने भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि समय के साथ इस प्रक्रिया में अनेक चुनौतियां और कमियां भी सामने आई हैं।

वस्तुतः भारत में हर वर्ष किसी न किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय निकाय में चुनाव होते रहते हैं। यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है, लेकिन बार-बार के चुनावों से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। चुनावों के दौरान लागू होने वाली आदर्श आचार संहिता के कारण विकास योजनाओं और नीतिगत निर्णयों पर रोक लग जाती है। इससे न केवल शासन-प्रशासन का नियमित कामकाज बाधित होता है, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति पर भी असर पड़ता है। सुरक्षा बलों की व्यापक तैनाती और चुनावी प्रबंधन के लिए मानव संसाधन का अत्यधिक उपयोग भी होता है। यह सिलसिला लगभग हर वर्ष चलता रहता है, जिससे देश का प्रशासनिक ढांचा और संसाधन लगातार दबाव में रहते हैं। इसके अतिरिक्त, बार-बार के चुनावी माहौल के कारण देश में एक राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है, जिससे दीर्घकालिक नीतियों और योजनाओं के कार्यान्वयन में बाधा आती है। 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' की अवधारणा का उद्देश्य लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनावों को एक साथ आयोजित करना है। इससे न केवल संसाधनों की बचत होगी, बल्कि प्रशासनिक और राजनीतिक स्थिरता भी सुनिश्चित होगी।

'एक राष्ट्र-एक चुनाव' से आर्थिक बचत होने के साथ ही बार-बार चुनाव होने के कारण प्रशासनिक कामकाज में आने वाली रुकावटें समाप्त होंगी। चुनावों के दौरान सुरक्षा बलों की व्यापक तैनाती को आवश्यकता होती है। एक साथ चुनाव कराने से यह प्रक्रिया अधिक संगठित होगी। बार-बार के चुनावी माहौल से उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता कम होगी और देश शासन एवं विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेगा। नगरिकों को बार-बार मतदान प्रक्रिया में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे उनकी भागीदारी अधिक प्रभावी हो सकेगी।

'एक राष्ट्र-एक चुनाव' को लागू करना जितना फायदेमंद प्रतीत होता है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए कई संवैधानिक और प्रशासनिक बाधाओं को पार करना होगा। विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए संविधान में कम से कम पांच संशोधन करने होंगे। भारत की संघीय संरचना में केंद्र एवं राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी। इतने बड़े पैमाने पर एक साथ चुनाव कराने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करना आवश्यक होगा।

इन चुनौतियों को दूर करने के लिए व्यापक संवाद, योजना और राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' की अवधारणा केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र को नई दिशा देने की ऐतिहासिक पहल है। इस विचार का इतिहास बताता है कि यह व्यवस्था एक समय में सफलतापूर्वक लागू थी। इसके फिर से लागू होने से लोकतंत्र और विकास दोनों को बल मिलेगा। यदि यह योजना सफल होती है, तो यह भारतीय लोकतंत्र को एक नई ऊंचाई तक ले जाने वाला परिवर्तन साबित होगी। यह समय है कि सभी नागरिक, राजनीतिक दल और संस्थाएं इस पहल का समर्थन करें और इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए एक मील का पत्थर बनाएं।

खरी-खरी

मान लो वह गुलाबी गेंद नहीं, ईवीएम है

क्षमा जैन

गुलाबी के फेर में पड़ गए ये लोग। न न, हनीट्रैप टाइप नहीं हुआ कुछ। गुलाबी से मतलब है गुलाबी गेंद। यों तो विश्व चैंपियन है टीम अपनी। परंतु स्टेडियम में पहुंचती ही परिणाम का अंदाजा हो जाता है दर्शकों को। कमेंटेटर आंखों देखा हाल सुनाते हैं, पिच पर घास दिखाई दे रही है, मेहमान टीम मुश्किल में आ सकती है। ऐसे में मेहमानों के लिए कठिनाइयां पैदा करना मुझे अच्छा नहीं लगता। हमारी संस्कृति के हिसाब से एकदम गलत है यह।

लेकिन उनसे कौन कहे। वैसे मुझे कभी समझ नहीं आया कि पिच पर घास का किसी टीम के मुश्किलों से क्या संबंध? अच्छी खासी टीम है। बस इस बार हुआ यह है कि गेंद का रंग गुलाबी कर दिया गया है। रंग बदलने से गेंद की मारक क्षमता बदलती होगी, ऐसा कभी सोच सकता था कोई? पर उनका दिमाग देखिए।

आखिर गेंद का रंग गुलाबी ही क्यों भाई? जरूर स्पेक्ट्रम में गुलाबी की तरंग दैर्ध्य ऐसी होती होगी कि इस उपमहाद्वीप के इंसानों की आंखें चकरा जाती होंगी। या फिर गुलाबी रंग वाले पदार्थ में ऐसा कैमिकल होता होगा जो हमारे बल्लों से छिटका देता होग गेंद को। जो भी हो, पर ऐसे तो हारते ही रहना पड़ेगा हमें। कुछ तो करना पड़ेगा। मैं टीम वालों को संदेश देना चाहूंगा कि उन्हें हमारे नेताओं से प्रेरणा लेने की जरूरत है।

मान लो आप नेता हो, गेंद ईवीएम है और जो मैच हार गए हैं, वह चुनाव है। लीजिए हो गई रणनीति तैयार। हारते ही बयान जारी करें कि हमें यह परिणाम स्वीकार नहीं। अगला भाई का लाल हो तो लाल गेंद से फिर से करा के देख ले मैच।

क्या कहा, यदि लाल से भी हार गए तो? आप राजनीति नहीं जानते यार। खिलाड़ी हो न। अरे भाई अगला कौन सा मान रहा है आपकी बात। आप सच्चमुच बहुत कच्चे हो। जीत गए तो मस्त जश्न मनाना। कोई पिछले मैच में हाय-तौबा करने की याद दिलाए तो सुनना ही नहीं। कान आपके हैं। ऐसे स्वयं ही लाजिक निकालेंगे तो कैसे काम चलेगा? एक बार मानकर तो देखिए स्वयं को नेता। सारी झिझक मिट जाएगी।

पोस्ट

दिल्ली पुलिस तो अमित शाह के मंत्रालय के अधीन ही है। उनके लिए कितना मुश्किल होगा उन तीन-चार लोगों पर कार्रवाई करना, जिन्होंने उनके वीडियो की विलप काट कर अपनी सुविधा से उसे चलाया। असल में जब तक इन लोगों के अंदर डर पैदा नहीं होगा कि ये कुछ भी झूठ बोलकर बच जाएंगे, तब तक यह नौटंकी देश में चलती रहेगी। विक्रांत@vikrantkumar

दिल्ली में यमुना तट पर गांधी की समाधि बनी। फिर नेहरू की। ये सब 50-50 एकड़ की हैं, पर बाबा साहब की समाधि को दिल्ली में जगह नहीं मिली। परिनिर्वाण के बाद उनके शव को मुंबई ले जाया गया। दिल्ली में संजय गांधी तक की समाधि बनी, जबकि वह तो मामूली सांसद ही थे। दिलीप मंडल@Profdilipmandal

इतिहास कैसे तोड़-मरोड़ा जाता है, यह 16 दिसंबर को मनाए गए विजय दिवस से पता चलता है। कांग्रेसदेव की अंतरिम सरकार 1971 की जीत में भारत के योगदान को झुठला रही है। यह तो हाल का इतिहास है। जरा सोचिए, जो घटना घटित होते पूरी दुनिया ने देखी, उसे ही सिरे से नकारा जा रहा है, तो फिर हमारे एक हजार साल के इतिहास को कैसे तहस-नहस किया गया होगा। अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

जागरण जनमत कल का परिणाम

एक साथ चुनाव वाले विधेयक को जेपीसी में भेजने से उस पर सहमति बन सकती है?

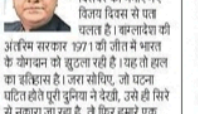

आज का सवाल
क्या रविवेकन अर्पिन को कुछ समय और खेलना चाहिए था?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

सभल मे हनुमान जी वर्षों से थे कैद,
मोर्मन की करतूत सब रही आजतक वैध।
रही आजतक वैध चलाओ अपनी मर्जी,
रोशन ही घरवार कनेवशन लेकर फर्जी।
नेता की शह पाय छेड़ते रहते दंगल,
किंतु रहा है जाग आजतक फिर से सभल!
- ओमप्रकाश तिवारी

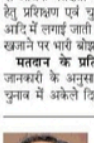

संजय मिश्र
स्थानीय संपादक, नवदुनिया, भोपाल

मध्य प्रदेश डायरी

साइबर धोखाधड़ी से निपटने की कवायद

यह छिपा तथ्य नहीं है कि कैशलेस इकोनामी की ओर तेजी से बढ़ रहे देश को साइबर अपराधियों से बड़ी चुनौती मिल रही है। मध्य प्रदेश भी ऐसा राज्य है, जहां शायद ही कोई दिन हो जब साइबर अपराधी किसी को निशाना न बना रहे हों। हर व्यक्ति के पास पहुंच चुके फोन और इंटरनेट का फायदा साइबर ठगों ने इस कदर उठाया है कि पारंपरिक अपराधों से निपटने के लिए प्रशिक्षित पुलिस जमीनी मोर्चाबंदी बिखर-सी गई है। लोग इस डर के बीच जी रहे हैं कि पता नहीं मोबाइल फोन पर कब, कौन-सी काल या संदेश उनके लिए आफत बनकर आ जाए और उनकी गाढ़ी कमाई लुट जाए। यह हैरान करने वाली सूचना है कि पिछले 11 महीनों में ही प्रदेश में साइबर ठगी की साढ़े पांच लाख से अधिक शिकायतें सामने आई हैं। इनमें 400 करोड़ रुपये की ठगी का ब्रोरा दर्ज है। अकेले राजधानी भोपाल में साइबर ठगी की करीब छह हजार शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। ये वे शिकायतें हैं, जिन्हें पुलिस के संज्ञान में लाया गया, लेकिन इनकी संख्या और अधिक भी हो सकती है। अनेक ऐसे लोग भी हैं जो ठगी तो गए, लेकिन लोकलाज के कारण अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास तक नहीं पहुंचे। दरअसल, छिपाए गए ऐसे मामले साइबर अपराधियों द्वारा अख्तीलन बेहिचाके काल के जरिये फंसाने के अधिक हैं।

इसमें कोई दो राय नहीं कि कानून की कमजोरियां एवं पुलिस की कमजोर जांच-पड़ताल का लाभ उठाकर साइबर अपराधी बचे रहते हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि साइबर अपराध के खतरों को लेकर प्रदेश सरकार ने इधर गंभीरता दिखाई है। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव इस मुद्दे पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें करके रोकथाम के उपायों पर चर्चा कर चुके हैं। इन बैठकों में साइबर अपराधियों से निपटने के तौर-तरीकों में बदलाव की बात भी हो चुकी है। मुख्यमंत्री के जोर देने का नतीजा यह है कि साइबर अपराधियों के खिलाफ अपने अभियान के तरीके बदले जा रहे हैं। पुलिस ने नए सूचना प्रौद्योगिकी नियम का सहारा लेकर उन दूर संचार और वित्तीय कंपनियों पर भी नकेल कसने की शुरुआत की है, जहां से उपभोक्ता का डाटा लीक होता है। इसे एक अच्छी शुरुआत मान जा रहा है। भोपाल के पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्रा बताते हैं कि साइबर ठगी के मामले में अगर यह बात सामने आई कि किसी कंपनी के लीक डाटा से उपभोक्ता की जानकारी साइबर ठग तक पहुंची है तो उस कंपनी को भी आरोपित बनाया जाएगा। यह डाटा सुरक्षा के प्रति लापरवाह कंपनियों के लिए भी बड़ा सबक होगा।

भोपाल में साइबर हेल्प डेस्क का शुभारंभ करते पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्रा। फाइल

इसके साथ ही पुलिस ने साइबर अपराध से लड़ने के अपने बुनियादी ढांचे में भी सुधार की कवायद तेज की है। अभी तक पूरे मध्य प्रदेश में एक साइबर थाना हुआ करता था। साइबर अपराध की जांच का जिम्मा राजधानी भोपाल में बनाए गए इस अकेले थाने की पुलिस पर था। अब इसमें बदलाव किया गया है। भोपाल के 37 थानों में एक दिसंबर से ही साइबर हेल्प डेस्क शुरू कर दी गई है। इस डेस्क पर तैनात पुलिसकर्मियों को साइबर अपराधों से निपटने का शार्ट टर्म प्रशिक्षण दिया गया है। पुलिस की इस विंग में फिलहाल 400 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। प्रत्येक थाने में इस डेस्क से संबद्ध पुलिस अधिकारी पांच लाख रुपये तक की ठगी के मामलों की जांच करेंगे। इससे बड़ी रकम अथवा जटिल मामले साइबर क्राइम सेल में भेजे जाएंगे। भोपाल में हुई इस शुरुआत के बाद प्रदेश भर के सभी थानों में ऐसा ही साइबर हेल्पडेस्क बनाने की तैयारी की जा रही है। प्रत्येक जिले में एक साइबर थाना बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

पुलिस ने उन वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों से भी तालमेल बढ़ाना शुरू किया है, जहां से इन ठगों को रुपये निकालने में मदद मिल जाती है। भोपाल में पिछले दिनों बैंकरों के साथ पुलिस ने एक बैठक की। इसमें साइबर ठगों के सहयोगियों द्वारा फर्जी दस्तावेजों से खाते खोल लेने के मुद्दे पर सख्त संदेश दिया गया। इसी तरह संदिग्ध खातों की पहचान करने में भी बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से मदद मांगी गई। विशेषज्ञों का मानना है कि बैंकों ने अगर कड़ाई की तो ठगों को बैंक खाता उपलब्ध कराने वाले लोग नहीं मिलेंगे। ऐसे में ठगों का नेटवर्क टूट जाएगा। पुलिस के इस रुख का नतीजा भी सामने आ रहा है। भोपाल पुलिस ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के महोबा से एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जो साइबर ठगों को सिम उपलब्ध कराने का नेटवर्क चला रहा था। मुंबई से एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसके खाते में ठगी की रकम भेजी गई थी। हिजिटल अरेस्ट के एक मामले में इंदौर पुलिस ने कन्नौज के मदरसा संचालक बाप-बेटे को गिरफ्तार किया। उनके खाते में 46 लाख रुपये भेजे गए थे। भोपाल में ऐसे गिरोह को भी पकड़ा गया है, जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ठगों को बैंक खाते उपलब्ध करा रहा था।

यह भी सच है कि साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस की सख्ती और कार्रवाई का रुख जरूर बदला है, लेकिन इसको ठगर लंबी हो सकती है। सरकार को इसके लिए संसाधनों की व्यवस्था करनी होगी, जो बड़ी चुनौती है। विधानसभा के मौजूदा सत्र में बुधवार को राज्य में साइबर अपराध बढ़ने का मामला उठाया गया। इस मुद्दे पर सरकार ने भरोसा दिया कि साइबर अपराधियों की नकेल कसने में वह कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

हिमाचल प्रदेश डायरी

घेरने-घिरने में घिरतीं प्राथमिकताएं

नवनीत शर्मा
राज्य संपादक, हिमाचल प्रदेश

वर्ष के 365 दिन चौंह के पेड़ों की सांय-सांय अकेले सुनने वाला, धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा सदन बुधवार से चहल-पहल देख रहा है। आखिर चार दिवसीय शीतकालीन सत्र का पहला दिन था। किसी समय जम्मू-कश्मीर के दरबार मूव की प्रतीति देती इस परंपरा का उद्देश्य यह अनुभव कराना रहा है कि कांगड़ा, चंबा और निचला हिमाचल प्रदेश भी सरकार और विपक्ष की हदयस्थली में वास करता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री का कांगड़ा शीतकालीन प्रवास भी परंपरा थी, जो अब क्षीण हो रही है। जो हो, राजनीतिक रूप से ही सही, कहने को कांगड़ा हर सरकार के हदय में वास करता है, क्योंकि 68 सदस्यीं वाली विधानसभा में यहां से सर्वाधिक 15 विधायक हैं। यह और बात है कि शिमला मंत्रिमंडल में भी शीर्ष पर है।

बहरहाल, चार दिनों के सत्र में मुख्यमंत्री दो ही दिन विधानसभा में रहेंगे, बाकी का दायित्व उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री संभालेंगे। इससे पूर्व प्रदेश में काफी कुछ हुआ है। सरकार ने दो वर्ष पूरे किए। कुछ और गारंटियों को लागू करते हुए नई योजनाएं आरंभ की। विपक्ष ने टायलेट टैक्स, समोसा की जांच, निगम की बसों में प्रेशर कुकर का टिकट काटने के विषय उठाने के साथ यह आरोप भी लगाया कि मुख्यमंत्री की कुपवी यात्रा के दौरान रात्रि भोज में जंगली मुर्गा परोसा गया। बहुत बवाल कटा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वह तो मुर्गा खाते नहीं, दूसरा, मुर्गा जंगली नहीं, देसी था। जाहिर है, पोल्ट्री फार्म वाला अंग्रेजी और घर में पाला जाने वाला देसी। बाद में बताया गया कि जैसे चित्र प्रसारित किए गए, उस प्रजाति के मुर्गे उस क्षेत्र में होते ही नहीं, नतीजतन यह दुष्प्रचार गरदाना गयादस क्षेत्र के लोगों की भावनाएं आहत हुईं और परिणामस्वरूप कुछ पत्रकारों पर बुधवार को ही प्राथमिकी भी दर्ज हुई है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस प्रदेश पर 90 हजार करोड़ रुपये से अधिक ऋण हो, जहां केंद्रीय सहायता पर दो पक्ष सुनने को मिलते हैं। एक पक्ष भाजपा का दावा कि दिल खोल कर सहायता मिली है। दूसरा पक्ष कांग्रेस का दावा कि फूटी कौड़ी नहीं मिली, जो मिला वह अधिकार था। जिस प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के भवन के लिए आवश्यक राशि जमा न करवाई जा पा रही हो, जहां सरकारी अस्पताल की डाक्टर मरीज को यह कह कर एक निजी अस्पताल में भेजे कि यहां उपयुक्त सुविधाएं नहीं मिलेंगी, इसलिए मैं हो आपका आरेरेशन उस निजी अस्पताल में कर दूंगी और मरीज की मौत हो जाए, जहां हिमाचल की छाती पर शानन ऊर्जा परियोजना पंजाब का नश्तर बन कर गड़ा हो, पहाड़ भरभरा रहे हों, कृषि भूमि कम हो रही हो, संस्न वर्ग को बिजली-पानी पर छूट समाप्त की जा रही हो, उस प्रदेश में मुर्गे पर बिमर्श करना यह बताता है कि संकट केवल वित्तीय नहीं, सर्वपक्षीय और कई प्रकार का है। लेकिन एक सवाल उस अफसर से भी बनता है जिसने मुख्यमंत्री के रात के खाने का मैन्यु सार्वजनिक किया और किसी क्रम में जंगली मुर्गा भी लिखा। यही समोसे के साथ भी हुआ जब डीजीपी ने अपने कर कमलों से समोसा चौरी को सरकार विरोधी गतिविधि बताया था। बिलासपुर जनसभा में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ठीक कहा था कि समोसा सरकार का नहीं था, डीजीपी का था।

घेरने की रणनीति और प्रतिरोधी रणनीति में वास्तविक विषय कहां चले जाते हैं, उसकी कुछ झलक बुधवार को भी दिखी। प्रश्नकाल से पहले भाजपा ने नोटिस दिया कि वह प्रश्नकाल को स्थगित कर नियम 67 के अंतर्गत चर्चा चाहते हैं। बुधवार को ही भाजपा की जन आक्रोश रैली भी थी। व्यावहारिक परंपरा के अनुसार, नोटिस अस्वीकार होना था, मगर सत्तापक्ष ने क्लाईमैक्स को एंटी क्लाईमैक्स बनाते हुए अनुमति दे दी कि चर्चा कीजिए, सत्ता पक्ष हर उत्तर देगा। उसके बाद रैली में भाजपा का शीर्ष नेतृत्व ही जा पाया, पर वह मोड़ नहीं आया, जिसे बाकआउट कहा जाता है। प्रदेश में आरोपपत्र बनाना पुराना शगल है। दोनों ही दल इस कार्य में असीम सूख पाते हैं, पर वे आरोप गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। कई बार नाम आरोपपत्र होता है, कई बार चार्जशीट। इस बार सुक्खू सरकार के दो वर्ष होने पर ही 11 दिसंबर को कच्चा चिट्ठा नाम से 18 आरोप दागे गए। बुधवार को जब चर्चा हुई तो भाजपा ने भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोप लगाए, कांग्रेस सरकार ने कहा कि साक्ष्य दें। और इसी नूराकुश्ती में दिन समाप्त।

एक काम यह बहुत हुआ कि बुधवार को ही हमीरपुर जिले के भौटा स्थित राधा स्वामी चेरिटेबल अस्पताल का स्वामित्व उसकी सहयोगी संस्था के नाम करने की राह खोलने वाला विधेयक प्रस्तुत किया गया। अभी धारा 118 यानी गैर कृषक हिमाचल प्रदेश में भूमि नहीं ले सकता का प्रतिबंध है। अब हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा संशोधन विधेयक, 2024 इसलिए लाया गया है, ताकि राधा स्वामी चेरिटेबल अस्पताल सहयोगी संस्था के पास जाकर चलता रहे। अन्यथा यह बंद हो रहा था। धारा 118 की दीवारों को छोटा करता हुआ यह विधेयक राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाएगा। जानकार मानते हैं कि विषय राधा स्वामी से जुड़ा है, इसलिए कोई बाधा नहीं आएगी। इसके साथ ही ऐसी ही अन्य संस्थाओं के लिए भी स्वामित्व हस्तांतरित करने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। एक पंक्ति आश्वस्त करती है कि यदि उक्त संस्थाएं भूमि या ढांचे का उपयोग बदलेंगे तो सब सरकार में बिलीन हो जाएगा।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा भवन। फाइल

दैनिक जागरण
मूल समझे बिना समस्या का समाधान संभव नहीं

बात का बतंगड़

किसी के बयान के आधे-अधूरे हिस्से को अपने एजेंडे के हिसाब से प्रचारित करने की सस्ती राजनीति कैसे गुल खिलाती है, इसका प्रमाण है गत दिवस संसद में गृह मंत्री अमित शाह के डा. आंबेडकर को लेकर दिए गए बयान पर विपक्ष का हंगामा। इस हंगामे का आधार यह है कि गृह मंत्री ने यह कह कर आंबेडकरजी का अपमान कर दिया कि यदि आंबेडकर, आंबेडकर करने वाले इतना नाम भगवान का लेते तो सात जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। मुश्किल यह है कि हंगामा करने वाले यह स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर ऐसा कहने से आंबेडकरजी का अपमान कैसे हो गया? अपने आरोप को पुष्ट करने के लिए विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस नेता गृह मंत्री के बयान के एक हिस्से को तो प्रचारित कर रहे हैं, लेकिन उसके शेष हिस्से को सुनने के लिए तैयार नहीं, जिसमें उन्होंने कहा था कि डा. आंबेडकर का नाम लेने वालों ने किस तरह उनके विचारों के खिलाफ काम किया और उन्हें अपमानित करने में भी संकोच नहीं किया। लगता है कांग्रेस को यही चुभ गया और इसी कारण वह संसद के भीतर-बाहर इस मामले को तूल देने में जुट गई। इसे तूल देने के लिए उसके नेताओं की ओर से जैसे तर्क दिए जा रहे हैं, वे विचित्र ही नहीं, हास्यास्पद भी हैं। ये तर्क केवल राजनीतिक विमर्श का स्तर गिराने वाले ही नहीं, यह बताने वाले भी हैं कि नेतागण किस तरह तिल का ताड़ बनाने में माहिर हो गए हैं। बिढंबना यह है कि यह काम अब कुछ ज्यादा ही होने लगा है। इससे राजनीतिक बहस का स्तर गिर रहा है।

राजनीतिक बहस का स्तर इतना छिछला नहीं होना चाहिए कि किसी के लिए अभिधा, लक्षणा, व्यंजना में अपनी बात कहना या फिर मुहावरों का प्रयोग करना दूभर हो जाए। यह अच्छा हुआ कि गृह मंत्री ने अपने बयान पर कोई सफाई देने के बजाय दो टूक यह कहना पसंद किया कि उनके पूरे वक्तव्य को सुना जाए। वैसे यह तय है कि विपक्षी नेता ऐसा नहीं करने वाले, क्योंकि उन्हें यही साबित करना है कि आंबेडकरजी का अपमान हो गया और संविधान खतरे में आ गया। इसे मूर्खतापूर्ण राजनीति न कहा जाए तो क्या कहा जाए? इस पर हैरानी नहीं कि राहुल गांधी को फिर से यह नजर आने लगा कि मोदी सरकार संविधान बदलने जा रही है। कांग्रेस नेता गृह मंत्री के बयान को लेकर आसमान सिर पर उठाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन वे इस सच को नहीं छिपा सकते कि उनके शासनकाल में डा. आंबेडकर की किस तरह उपेक्षा और अनदेखी की गई। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि जहां नेहरू और इंदिरा गांधी को तो उनके जीवनकाल में ही भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया, वहीं आंबेडकरजी को यह सम्मान 1990 में मिल सका। क्या कांग्रेस बता सकेगी कि ऐसा क्यों हुआ?

कड़ा सबक

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के वृंदावन के डालमिया बाग और आगरा के माथुर फार्म हाउस में हरे पेड़ काटे जाने के मामले में सख्त रुख अपनाकर सीधा संदेश दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और यदि कोई दुस्साहस करेगा तो उसके खिलाफ दंड भी कड़े होंगे। वस्तुतः डालमिया बाग में रातोंरात 454 और माथुर फार्म हाउस में 17 हरे पेड़ कट डाले गए थे। लिहाजा, सुप्रीम कोर्ट ने इन पर क्रमशः 4.54 करोड़ और 17 लाख रुपये का जुर्माना तो लगाया ही है, 20 गुणा पौधे रोपने के साथ ही इसके लिए जमीन भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। हरे पेड़ों को काटने के संदर्भ में कोर्ट का यह फैसला बड़ा उदाहरण बनेगा, क्योंकि यह आदेश स्वयं को अति शक्तिशाली मानने वालों के खिलाफ कानून की सत्ता स्थापित करता है। कोर्ट ने अपना काम कर दिया है, लेकिन अब राज्य सरकार को उन अधिकारियों को चिह्नित करना चाहिए जो इतनी बड़ी संख्या में हरे पेड़ काटने के बाद भी आंखें मूंदे रहे। बिल्डरों और अधिकारियों के गठजोड़ से हरे पेड़ों की कटाई रोकने के लिए भी यह जरूरी है। बिना अनुमति हरे पेड़ काटना अपराध है और बात जब ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र की हो जिसकी परिधि में ताजमहल से 50 किमी का क्षेत्र आता है तो ऐसा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति जरूरी है। कानूनी प्रविधानों के बारे में जानकारी होने के बावजूद यदि कोई उसका उल्लंघन करता है तो इतनी ही कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि दूसरे उससे सबक लें। वृक्षों के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसलिए पेड़ों को बचाना हर नागरिक का कर्तव्य है। विकास के लिए सड़कें जरूरी हैं, लेकिन इस बात का भरपूर प्रयास हो कि कम से कम वृक्ष काटने पड़ें और उनकी प्रतिपूर्ति में दस गुणा पौधे लगाए जाएं।

> कानूनी प्रविधानों के बारे में जानकारी होने के बावजूद यदि कोई उसका उल्लंघन करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए

चीन पर भरोसा न करे भारत

श्रीराम चौलिया

जब तक चीन भारत के आगे बढ़ने में अड़चनें डालता रहेगा, तब तक उससे दोस्ती की अपेक्षा काल्पनिक ही बनी रहेगी

अरुंधती रागुप्ता

पांच वर्षों के अंतराल के बाद भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच उच्चस्तरीय वार्ता के बाद द्विपक्षीय संबंधों में नरमी के संकेत मिले। इस वार्ता में भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन की ओर से विदेश मंत्री वांग यी शामिल हुए। वार्ता की यह पहल पूर्वी लद्दाख और अक्साई चिन सीमा पर 2020 से चले आ रहे सैन्य टकराव को सुलझाने के पारस्पर आरंभ की गई है। उस समझौते के तहत चीन ने विवादित क्षेत्रों से अपनी सेना को पीछे हटाया है, जहां उसने भारतीय सेना को गश्त करने से रोका था। सैन्य निकासी के अलावा चीन ने आश्वासन दिया है कि दोनों पक्ष एक-दूसरे के 'मूल हितों और प्रमुख सरोकारों को समझते हुए और ईमानदारी एवं सद्भावना के साथ मतभेदों को सुलझाने के लिए तैयार हैं।' कूटनीतिक सरगर्मियों के मद्देनजर अहम सवाल यही है कि क्या चीन का भारत के प्रति बाकई कोई हृदय परिवर्तन हुआ है और अगर ऐसा हुआ है तो इसका कारण क्या है? बीते 12 वर्षों से चीन पर राज करते हुए तानाशाह राष्ट्रपति शी चिनफिंग की मंशा पर ध्यान दें तो यह असंभव है कि उन्होंने एशिया और विश्व में चीन के वर्चस्व और विस्तारवाद का सपना रातोंरात त्याग दिया है। 'प्रमुख देश कूटनीति' नामक उनकी अवधारणा के अनुसार चीन कभी भी अपने 'वैध अधिकारों और हितों' को नहीं छोड़ेगा और पड़ोसी देशों के साथ विवादों में अपनी शक्ति एवं श्रेष्ठता के बलबूते हावी रहेगा। भारत के अलावा एक दर्जन से अधिक देशों के साथ चीन के अनसुलझे क्षेत्रीय विवाद हैं और इन सभी के प्रति शी के शासन में चीन ने दबंग व्यवहार अपनाकर धौंस देना जारी रखा है। 'ग्रे जोन' और 'सलामी स्लाइसिंग' रणनीतियों का उपयोग करते हुए चीन ने पड़ोसियों पर सैन्य एवं आर्थिक दबाव डालकर यही चेष्टा की है कि कमजोर देशों पर चीन की इच्छा थोपी जाए। उनके अतिराष्ट्रवादी 'चीनी स्वप्न' का लक्ष्य एशिया में उस पुराने साम्राज्यवादी युग को पुनः स्थापित करना है, जहां चीन का कथित तौर पर प्रभुत्व था और पड़ोसियों को बीजिंग में सम्राट के सामने झुककर प्रणाम करना पड़ता था।

शी जैसे कट्टर निरंकुश नेता का इतने भव्य एवं महत्वाकांक्षी स्वप्न को भुला देना नामुमकिन है। चीन को केवल महाशक्ति बनाना ही नहीं, बल्कि अमेरिका को पछाड़कर विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित करने और चीनी मूल्यों पर आधारित नई विश्व व्यवस्था कायम करने जैसे लक्ष्यों को साधने के लिए वह कोई कोर-कसर नहीं छोड़ने वाले। हालांकि उनकी यह राह आसान नहीं। अमेरिका और उसके सहयोगी देश भी चीन की इस राह में कांटे बिछाने के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे। यह कोई संयोग नहीं है कि चीन ने भारत समेत जिन एशियाई देशों के साथ स्थलीय और समुद्री सीमाओं से जुड़े विवाद नहीं निपटाए, उनकी अमेरिका के साथ गलबहियां बढ़ी हैं। असल में चीन को संतुलित करने की दृष्टि से ही इन देशों का झुकाव अमेरिका की ओर बढ़ा है, जिससे चीन और चिढ़ता है। चीन यह चाहता है कि सीमाओं पर दबाव घटाने के बदले पड़ोसी देश अमेरिका से किनारा करें या अमेरिका के साथ मिलकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उसके लिए मुश्किलें पैदा न करें। इसका अर्थ है कि पड़ोसियों को अपनी विदेश नीति स्वतंत्रता और सामरिक स्वायत्तता को सीमित करना होगा और चीनी प्रभुत्व वाली क्षेत्रीय व्यवस्था को स्वीकार करना होगा। इस प्रकार की शर्त किसी भी स्वाभिमानी देश विशेषकर भारत जैसी उभरती महाशक्ति को कतई स्वीकार्य नहीं हो सकती।

अजीत डोभाल और वांग यी के बीच हालिया वार्ता विवादित 'सीमा प्रश्न' पर विशेष प्रतिनिधियों की 23वीं बैठक है और यह सिलसिला बिना किसी अंतिम सहमति के वर्ष 2003 से निरंतर जारी है। इसके अतिरिक्त, 'सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र' की 2012 से अब तक 32 बैठकें हो चुकी हैं। इनमें भाग लेने वाले भारतीय वार्ताकारों और राजनयिकों का मानना है कि चीन इस विवाद को हमेशा के लिए समाप्त करने का इच्छुक नहीं दिखता और वह भारत की ओर से प्रस्तुत किए गए मानचित्रों की बारीकियों में भी नहीं जाता। चीन लगातार थकाऊ वार्ताओं के माध्यम से संघर्ष को प्रबंधित करने का प्रयास करता है, परंतु अपने क्षेत्रीय दावों को नहीं छोड़ता।

वर्ष 2020 में गलवन घाटी में मुठभेड़ और उसके बाद करीब सठ हजार सैनिकों एवं भारी-भरकम हथियारों की तैनाती चीन को खासी महंगी पड़ी। भारतीय सेना ने जिस मुस्तैदी के साथ जवाबी कार्रवाई की और अतिरिक्त चीनी घुसपैठ के लिए सभी रास्ते बंद कर दिए, उसने शी की चिंताएं बढ़ा दी थीं। अमेरिका के साथ भारत की सामरिक साझेदारी भी बीते कुछ वर्षों के दौरान जिस प्रकार मजबूत होती गई, उसने भी चीन के माथे पर बल डालने का काम किया। ट्रंप की वापसी और उनके द्वारा छेड़े जाने वाले संभावित व्यापार युद्ध व सैन्य चुनौती भी शी की आशंका का कारण है। ऐसे में, भारत के प्रति नरम रवैये का प्रदर्शन कर शी चीन के लिए थोड़े समय के लिए सामरिक राहत की खोज में होंगे।

देपसांग और देमचोक से चीनी सेना की वापसी शी की नाकामी का परिचायक है, लेकिन यह ध्यान रहे कि उनके जैसे महत्वाकांक्षी तानाशाह आसानी से हार नहीं मानते। चीन भारत को झुकाने का इरादा तब तक मन में रखेगा, जब तक वह आश्वस्त न हो जाए कि भारत अमेरिका के संग मिलकर उसकी घेराबंदी करना नहीं छोड़ता। चूंकि अमेरिका की मित्रता भारत के उत्थान के लिए अनिवार्य है, इसलिए चीन के साथ भारत की अनबन और प्रतिस्पर्धा में कमी की अपेक्षा अवास्तविक है। भारत-चीन वार्ता के दौर सीमा पर उल्लंघित नियमों को बहाल करने में कमोबेश मददगार हो सकते हैं, लेकिन भू-राजनीतिक स्तर पर मैत्रीपूर्ण संबंध की संभावना दूर की कौड़ी है। जब तक चीन भारत के महाशक्ति बनने में अड़चनें डालता रहेगा, उससे दोस्ती की अपेक्षा काल्पनिक बनी रहेगी। भारत को अपनी सैन्य तैयारियों और क्षमताओं को उन्नत करते हुए चीन से सतर्क रहने की नीति पर ही चलना होगा।

(लेखक जिंदल स्कूल आफ इंटरनेशनल अफेयर्स में प्रोफेसर और डीन हैं)

response@jagran.com

संविधान को बचाने का दिखावा

जगमोहन सिंह राजपूत

इन दिनों जगह-जगह संविधान की प्रति लहराने का एकमात्र उद्देश्य देश का ध्यान भटकाना है

लोकसभा में संविधान की प्रति दिखाते राहुल। एएनआइ

आजकल संविधान हर तरफ चर्चा में है, लेकिन यह पहली बार दिख रहा है कि संविधान के नए संरक्षक उसे बचाने के लिए सबसे अधिक उत्सुक दिख रहे हैं। यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर वे किससे संविधान को बचा रहे हैं? अच्छी बात यह है कि इस सबके बीच देश संविधान पर घातक आघात किए जाने के उन दो वर्षों को पुनः याद कर रहा है, जो उसने 1975-77 के मध्य झेले थे। स्वाभाविक है कि उन लोगों को भी याद किया जा रहा है, जिन्होंने संविधान को उस समय बचाया था। देश में जेपी जैसे स्वतंत्रता संग्राम के तपे हुए नेता मौजूद थे, जिनकी निस्वार्थ अगुआई में जनता ने संविधान बचाया था। नीयत में खोट और अनुभवहीनता का जब सत्ता प्राप्ति के संदर्भ में समन्वय हो जाता है, तो हास्यास्पद स्थितियां निर्मित हो जाती हैं। भारत की राजनीति में इस समय यही स्थिति बन गई है। संविधान की मूल भावना अपनी संपूर्णता के साथ उसके आमुख में निहित थी। वह एक संपूर्ण प्रतिज्ञा है, जिसे निभाने के लिए हर नागरिक को प्रतिबद्ध होना चाहिए। वे लोग जो संवैधानिक पदों पर जनप्रतिनिधि बनकर पहुंचते हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे उसके अनुपालन का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करेंगे।

संविधान हर भारतवासी को एक बेहतर जीवन देने के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धता का वह दस्तावेज है, जो इंगित करता है कि व्यवस्था किस प्रकार आगे बढ़ेगी। यह सामान्य अपेक्षा है कि हर नागरिक अपना उत्तरदायित्व निर्बंहन पूरी निष्ठा के साथ लक्ष्य प्राप्ति के लिए अवश्य करे। 'लोक हिताय मम कर्तव्यम' संविधान में हर प्रकार से रचा बसा है। कौन उसे कितना आत्मसात कर पाता है, यह व्यक्ति की अपनी क्षमता पर ही नहीं, उसके जीवन मूल्यों पर भी निर्भर करता है। आप संविधान को जितनी बार पढ़ेंगे, आपकी समझ का दायरा उतना ही बढ़ता जाएगा। इसे के साथ संविधान निर्माताओं के प्रति सम्मान भी बढ़ता जाएगा। मैं उन लोगों में हूं, जिन्हें संविधान का आमुख 1955 के आसपास स्कूल में ही कंठस्थ करा दिया गया था। आपातकाल में इसे परिवर्तित किया गया और इसमें सोशलिस्ट और सेक्यूलर शब्द जोड़े गए। यह परिवर्तन दूरदर्शी संविधान निर्माताओं की समझ का अपमान था। यह परिवर्तन उस संसद ने किया, जिसका सारा विपक्ष जेल में यातनाएं झेल रहा था। उसका कार्यकाल तक संविधान के प्रविधानों को रौंदकर पांच साल से बढ़ाकर सात साल कर दिया गया था। कैसी बिडंबना है कि इस सबके लिए जिम्मेदार लोग आज संविधान के संरक्षक बनकर देश की जनता का समर्थन पाने की अभिलाषा कर रहे हैं।

भले ही सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आमुख परिवर्तन को बदलने की आवश्यकता न मानी हो, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि आमुख बदल जाएगा, ऐसी कल्पना तो शायद राजेंद्र प्रसाद या भीमराव आंबेडकर और संविधान सभा के अन्य सदस्यों ने भी कभी नहीं की होगी। सामान्य नागरिक के लिए यह समझ पाना कठिन है कि जो सर्वोच्च न्यायालय यह निर्णय देता है कि संसद भी संविधान के मूल आत्मा से छेड़छाड़ नहीं कर सकती, वह आमुख के मूल स्वरूप में हुई छेड़छाड़ को कैसे स्वीकार कर लेता है।

आंबेडकर और गांधीजी ने पश्चिम में शिक्षा ग्रहण की थी, लेकिन वे भारतीयों की उस श्रेणी में नहीं थे, जिन्हें पश्चिम की पढ़ाई ने अपने देश और संस्कृति से अलग कर दिया हो, जैसा अधिकांश विलायत में पढ़े लोगों के साथ हुआ। भारत, उसकी सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति, उसकी वैचारिक समृद्धता और मनुष्य मात्र की एकता में विश्वास की जितनी गहरी समझ इन मनीषियों ने गहन अध्ययन से प्राप्त की, वह अद्वितीय थी। क्या उनके साथ-साथ राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय आदि का आचरण और जीवन जीने की पद्धति यह स्पष्ट नहीं करती थी कि पंथनिरपेक्षता की निर्मल और व्यावहारिक समझ भारत में सदा उपस्थित थी? क्या यह भावना आमुख तथा संविधान के हर पृष्ठ पर स्पष्ट नहीं होती? संविधान सभा ने इन शब्दों के संबंध में चर्चा भी की थी और उन्हें न जोड़ने का निर्णय लिया था।

डा. आंबेडकर ने 25 नवंबर, 1949 के अपने ऐतिहासिक भाषण में यह कहा था कि संविधान कितना अच्छा होगा, यह आगे चलकर उसे चलाने वालों पर निर्भर करेगा। 1975-77 में यह शब्दशः सत्य सिद्ध हुआ, जब पद पर बने रहने की लालसा ने संविधान के साथ ऐसा अत्याचार किया, जिसे इतिहास भूलेगा नहीं। इस समय संविधान बचाने का जो शोर सुनाई दे रहा है और जिसकी प्रति संसद से सेंधल तक लहराई जा रही है, वह देश का ध्यान भटकाने की कोशिश मात्र है। संविधान की प्रति हर जगह लहराने वाले लोग यदि एक बार यह कहते कि उनके हाथ में वह प्रति है, जिसमें आचार्य नंदलाल बोस द्वारा भारतीय संस्कृति को दर्शाते हुए सभी चित्र भी शामिल हैं, तो बात बनती। ये चित्र पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुरोध पर बनाए गए थे। संविधान का सम्मान तो तब होगा, जब यह प्रश्न उठाया जाए कि ये चित्र हटाए क्यों गए? संविधान के प्रति निष्ठा प्रकट करने के दिखावे के स्थान पर यह मांग उठाई जानी चाहिए कि भविष्य में संविधान की कोई प्रति बिना इन चित्रों के छापना दंडनीय अपराध होगा। आचार्य नंदलाल बोस ने बहुत मनोयोग से ये चित्र बनाए थे। उन्हें पुनः स्थापित कर उनके अपमान की भरपाई होनी चाहिए।

यह देखना दयनीय है कि सत्ता पाने के लिए व्याकुल लोगों की व्यग्रता अब उग्रता के रूप में प्रकट हो रही है। संसद के कार्य संचालन में जैसे व्यवधान डाले जा रहे हैं, वे न तो भारत के संविधान के प्रति कोई आदरभाव प्रकट करते हैं, न ही आंबेडकर के प्रति कोई श्रद्धा प्रकट करते हैं।

(लेखक प्रधानमंत्री स्मारक एवं ग्रंथालय में फेलो हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

विवेक

मनुष्य की स्वाभाविक विचार चेतना भौतिकतावादी होती है। वह जिस समाज में रहता है, उसके वातावरण का प्रभाव उस पर अवश्य ही पड़ता है। अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह जो संघर्ष करता है, उसका प्रभाव उसके मन-मस्तिष्क पर पड़ता ही है। इस भौतिक संसार में रहकर जीवन-जगत की स्वाभाविकता के कारण जो विचार और संकल्प मनुष्य बनाता है, पुरुषार्थ करने पर वह भौतिक वस्तुओं के रूप में इन्हें प्राप्त कर सकता है। यदि हम गहनता से विचार करें तो यह भौतिक उपलब्धियां मानव जीवन में स्थायी शांति प्रदान नहीं कर सकतीं। अविवेक के कारण हम इन्हें सुख मान लेते हैं और आनंद का साधन भी। वास्तव में आनंदमयी शांति की प्राप्ति के लिए विवेक का होना आवश्यक है। जीवन की यथार्थ दृष्टि विवेक से ही प्राप्त हो सकती है। कर्तव्य और अकर्तव्य का भेद विवेक से ही प्राप्त हो सकता है।

तुलसीदास जी कहते हैं कि विवेक सत्संग से प्राप्त होता है। गीता में वर्णन है कि किंकर्तव्यविमूढ़ महारथी अर्जुन अनिश्चय की स्थिति से बाहर निकालने के लिए अपने आराध्य भगवान श्रीकृष्ण से विवेक की प्रार्थना करते हैं। भगवान श्रीकृष्ण के उपदेश के बाद उनमें विवेक अर्थात यथार्थ ज्ञान जागृत हो जाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच उन्हें अनुकूल ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे भ्रम की स्थिति समाप्त हो जाती है।

वस्तुतः, विवेक की परिभाषा ही यह है कि मोह जनित भ्रम का नाश हो जाए और यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो। इसे ही हम ईश्वरीय बोध कह सकते हैं। यह बोध मनुष्य को मानसिक चिंताओं से मुक्त कर आनंदमय जीवन प्रदान करता है। जिस प्रकार तैरने की कला में माहिर व्यक्ति डूबती हुई नाव से कूद कर सरलता से तैरकर अपने प्राणों की रक्षा कर सकता है। ठीक इसी प्रकार विवेक से परिपूर्ण व्यक्ति इस दुखमय संसार रूपी सागर को विवेक की सहायता से तैरकर पार कर सकता है।

डा. प्रशांत अग्निहोत्री

स्पिन के महारथी के सुनहरे युग का अंत

नृपेंद्र अभिषेक नृप

स्पिन गेंदबाजी को नई ऊंचाई देने के साथ ही अश्विन ने भारतीय क्रिकेट के प्रशंसकों को कई यादगार पल भी दिए हैं

भारतीय क्रिकेट स्पिन गेंदबाजों का गढ़ रहा है। इस परंपरा ने हाल के वर्षों में हमें अनिल कुंबले, हरभजन सिंह और रविचंद्रन अश्विन जैसे खिलाड़ी दिए हैं। अश्विन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। क्रिकेट में अपने कौशल का परचम लहराते हुए उन्होंने भारत को इस मामले में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया।

अश्विन ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2010 में जिंबाब्वे के खिलाफ वनडे मैच से की थी। इसके बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी अपनी जगह बनाई और अपने पहले ही टेस्ट मैच में नौ विकेट लेकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। अश्विन का गेंदबाजी स्टाइल उन्हें सबसे अलग बनाता है। उनकी आफ स्पिन गेंदबाजी में विविधता, फ्लाइट और गति का अद्भुत संयोजन देखने को मिलता है। उनकी 'कैरम बाल' ने कई बल्लेबाजों को परेशान किया और उन्हें विश्व क्रिकेट में खास पहचान दिलाई। उनकी गेंदबाजी में गहराई और बल्लेबाजों को पढ़ने की क्षमता उनकी सफलता का मूल कारण रही है। कुंबले और हरभजन सिंह के संन्यास के बाद भारतीय टीम में एक ऐसे स्पिनर की जरूरत थी जो टेस्ट क्रिकेट में विकेट निकाल सके और कठिन परिस्थितियों में टीम का साथ दे सके। अश्विन ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। कुंबले की तरह अश्विन ने भी टेस्ट क्रिकेट में निरंतरता और दृढ़ता दिखाई। हरभजन की तरह आक्रामकता और बल्लेबाजों पर मानसिक दबाव बनाने की कला सीखी।

अश्विन का संन्यास भारतीय क्रिकेट के लिए एक युग के अंत जैसा है। हालांकि उन्होंने आइपीएल में खेलना जारी रखने का संकेत दिया है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनकी अनुपस्थिति की महसूस किया जाएगा। उनके संन्यास का फैसला कई कारणों से लिया गया हो सकता है, जिनमें उम्र, शारीरिक थकान और युवा खिलाड़ियों को मौका देने की भावना शामिल हो सकती है। अश्विन ने युवा खिलाड़ियों को प्रेरित किया है और स्पिन गेंदबाजी की नई परिभाषा गढ़ी है। उनकी सीख, तकनीक और रणनीतियां भारतीय क्रिकेट के लिए एक धरोहर हैं। उन्होंने टीम इंडिया को कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाला और कई मैच जिताए। उन्होंने दिखाया कि एक स्पिनर भी आलराउंडर बन सकता है। अश्विन के संन्यास के बाद भारतीय टीम को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल जैसे स्पिनर टीम में हैं, लेकिन अश्विन जैसी विविधता और अनुभव हासिल करने में समय लगेगा।

अश्विन का करियर भारतीय क्रिकेट के स्वर्णिम अध्यायों में दर्ज रहेगा। उनके संन्यास के बाद टीम में उनकी कमी जरूर महसूस होगी, लेकिन उनके द्वारा स्थापित मानदंड आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

पारदर्शिता आवश्यक

'ईवीएम पर बेजा सवाल उठाने के खतरे' शीर्षक से लिखे आलेख में राहुल वर्मा ने ईवीएम पर कुछ दलों के रवैये को लोकतंत्र के लिए हानिकारक बताया। वैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की हमारी छवि केवल ईवीएम पर सवाल उठाने से ही कमजोर नहीं हो रही। हमारे नेताओं की तुच्छ राजनीति से भी यह प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। भारत में चुनाव आयोग हर चुनाव से पहले ईवीएम की उचित और निष्पक्ष जांच कराता है, इसलिए ईवीएम में गड़बड़ी की जरा भी उम्मीद नहीं की जा सकती। इसके बावजूद किसी भी प्रकार के संदेह दूर किए ही जाने चाहिए। दुनिया के दूसरे कोनों में भी ईवीएम जैसी मशीनों को लेकर संदेह व्यक्त किए जाते हैं, उसे देखते हुए निर्वाचन आयोग को पूरे तथ्य सामने रखने चाहिए कि भारतीय ईवीएम कैसे सबसे अलग है और उसमें जरा भी हेरफेर की कोई गुंजाइश नहीं। इस दिशा में लेखक ने एप बनाने का जो सुझाव दिया वह सराहनीय है। जितनी पारदर्शिता बढ़ेगी, उससे उतना ही लाभ मिलेगा।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

रविचंद्रन अश्विन का संन्यास

दिग्गज स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। भारत के इस महान स्पिनर के संन्यास की घोषणा एक तरफ से चौंकाने वाला बड़ा फैसला भी रहा, क्योंकि वह भारत के लिए कई बार मुश्किल परिस्थितियों में दमदार प्रदर्शन कर चुके हैं। अश्विन बालिंग के साथ-साथ बैटिंग में भी कमाल दिख चुके हैं। वह भारत के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। उनके आगे केवल अनिल कुंबले हैं। इसके साथ ही अश्विन के नाम टेस्ट में 37 बार पांच विकेट लेने का रिकार्ड भी है, जो किसी भारतीय गेंदबाज द्वारा सबसे ज्यादा है। अश्विन ने इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लिए, इसके साथ ही अश्विन टेस्ट में सबसे ज्यादा प्लेयर आफ द सीरीज अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ी हैं। भारत के घरेलू मैदानों पर रविचंद्रन अश्विन की तूती बोलती थी। वह भारतीय स्पिन गेंदबाजी के आधार स्तंभ थे। भारत में उनके स्पिन गेंद का सामना करना विपक्षी टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती थी। भारत में कई बड़ी विजय के वह नायक रहे हैं। भारत अपनी जमीन पर इस दिग्गज स्पिनर की कमी को महसूस करेगा। एक बात का हमेशा क्रिकेट प्रेमियों को मलाल रहेगा कि कई महान खिलाड़ियों की तरह उन्हें भी विदाई मैच खेलने का अवसर नहीं मिला।

विजय किशोर तिवारी, नई दिल्ली

परीक्षा में पारदर्शिता

वर्ष 2024 की नीट की परीक्षा को लेकर नेशनल टेस्ट एजेंसी (एनटीए) विवादों के घेरे में आ गई थी। इस प्रकार से शिक्षा मंत्रालय द्वारा जांच कमेटी बैठाई गई और विभिन्न याचिकाएं विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय तथा देश की सबसे बड़ी अदालत उच्चतम न्यायालय में लगाई गईं। जिसके तहत इसरो के पूर्व अध्यक्ष डा. के. राधाकृष्णन के नेतृत्व में गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को अक्टूबर 2024 में सौंप दी थी। समिति ने एनटीए के कार्य पर विभिन्न तरह के सवाल भी खड़े किए थे। वर्ष 2024 में एनटीए ने विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन किया। इसी संस्था द्वारा विभिन्न पदों को भरने के लिए परीक्षाएं ली गईं थीं। विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालय में नियुक्तियों को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। एनटीए द्वारा ली गई नीट और जेईई की परीक्षा के साथ-साथ विभिन्न अन्य परीक्षाओं में विभिन्न तरह की खामियां पाई गईं। जांच समिति ने इस बात की सिफारिश की कि किसी भी तरह की भर्ती एनटीए द्वारा नहीं की जाएगी। समिति द्वारा सिफारिश की गई कि किसी भी निजी स्कूल में परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। यहां तक कि सभी परीक्षा केंद्र विश्वविद्यालय, कालेज, सरकारी स्कूलों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ही होंगे। प्रश्न पत्र लीक होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए कमेटी ने संस्तुति की है कि ऐसे मामलों पर सख्त करवाई हो तथा इसमें जिम्मेदारी भी तय की जाए।

मीना धानिया, सिरसपुर, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

दैनिक जागरण
मूल समझे बिना समस्या का समाधान संभव नहीं

बात का बतंगड़

किसी के बयान के आधे-अधूरे हिस्से को अपने एजेंडे के हिसाब से प्रचारित करने की सस्ती राजनीति कैसे गुल खिलाती है, इसका प्रमाण है गत दिवस संसद में गृह मंत्री अमित शाह के डा. आंबेडकर को लेकर दिए गए बयान पर विपक्ष का हंगामा। इस हंगामे का आधार यह है कि गृह मंत्री ने यह कह कर आंबेडकरजी का अपमान कर दिया कि यदि आंबेडकर, आंबेडकर करने वाले इतना नाम भगवान का लेते तो सात जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। मुश्किल यह है कि हंगामा करने वाले यह स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर ऐसा कहने से आंबेडकरजी का अपमान कैसे हो गया? अपने आरोप को पुष्ट करने के लिए विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस नेता गृह मंत्री के बयान के एक हिस्से को तो प्रचारित कर रहे हैं, लेकिन उसके शेष हिस्से को सुनने के लिए तैयार नहीं, जिसमें उन्होंने कहा था कि डा. आंबेडकर का नाम लेने वालों ने किस तरह उनके विचारों के खिलाफ काम किया और उन्हें अपमानित करने में भी संकोच नहीं किया। लगता है कांग्रेस को यही चुभ गया और इसी कारण वह संसद के भीतर-बाहर इस मामले को तूल देने में जुट गई। इसे तूल देने के लिए उसके नेताओं की ओर से जैसे तर्क दिए जा रहे हैं, वे विचित्र ही नहीं, हास्यास्पद भी हैं। ये तर्क केवल राजनीतिक क्विज़ की स्तर गिराने वाले ही नहीं, यह बताने वाले भी हैं कि नेतागण किस तरह तिल का ताड़ बनाने में माहिर हो गए हैं। विडंबना यह है कि यह काम अब कुछ ज्यादा ही होने लगा है। इससे राजनीतिक बहस का स्तर गिर रहा है।

राजनीतिक बहस का स्तर इतना छिछला नहीं होना चाहिए कि किसी के लिए अभिधा, लक्षणा, व्यंजना में अपनी बात कहना या फिर मुहावरों का प्रयोग करना दूभर हो जाए। यह अच्छा हुआ कि गृह मंत्री ने अपने बयान पर कोई सफाई देने के बजाय दो टूक यह कहना पसंद किया कि उनके पूरे वक्तव्य को सुना जाए। वैसे यह तय है कि विपक्षी नेता ऐसा नहीं करने वाले, क्योंकि उन्हें यही साबित करना है कि आंबेडकरजी का अपमान हो गया और संविधान खतरे में आ गया। इसे मूर्खतापूर्ण राजनीति न कहा जाए तो क्या कहा जाए? इस पर हैरानी नहीं कि राहुल गांधी को फिर से यह नजर आने लगा कि मोदी सरकार संविधान बदलने जा रही है। कांग्रेस नेता गृह मंत्री के बयान को लेकर आसमान सिर पर उठाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन वे इस सच को नहीं छिपा सकते कि उनके शासनकाल में डा. आंबेडकर की किस तरह उपेक्षा और अनदेखी की गई। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि जहां नेहरू और इंदिरा गांधी को तो उनके जीवनकाल में ही भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया, वहीं आंबेडकरजी को यह सम्मान 1990 में मिल सका। क्या कांग्रेस बता सकेगी कि ऐसा क्यों हुआ?

कड़ा सबक

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के कुंदाबा के डालमिया बाग और आगरा के माथुर फार्म हाउस में हरे पेड़ काटे जाने के मामले में सख्त रुख अपनाकर सीधा संदेश दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और यदि कोई दुस्साहस करेगा तो उसके खिलाफ दंड भी कड़े होंगे। वस्तुतः डालमिया बाग में रातोंरात 454 और माथुर फार्म हाउस में 17 हरे पेड़ काट डाले गए थे। लिहाजा, सुप्रीम कोर्ट ने इन पर क्रमशः 4.54 करोड़ और 17 लाख रुपये का जुर्माना तो लगाया ही है, 20 गुणा पौधे रोपने के साथ ही इसके लिए जमीन भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। हरे पेड़ों को काटने के संदर्भ में कोर्ट का यह फैसला बड़ा उदाहरण बनेगा, क्योंकि यह आदेश स्वयं को अति शक्तिशाली मानने वालों के खिलाफ कानून की सत्ता स्थापित करता है। कोर्ट ने अपना काम कर दिया है, लेकिन अब राज्य सरकार को उन अधिकारियों को चिह्नित करना चाहिए जो इतनी बड़ी संख्या में हरे पेड़ काटने के बाद भी आंखें मूंदे रहे। बिल्डरों और अधिकारियों के गठजोड़ से हरे पेड़ों की कटाई रोकने के लिए भी यह जरूरी है। बिना अनुमति हरे पेड़ काटना अपराध है और बात जब ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र की हो जिसकी परिधि में ताजमहल से 50 किमी का क्षेत्र आता है तो ऐसा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति जरूरी है। कानूनी प्रविधानों के बारे में जानकारी होने के बावजूद यदि कोई उसका उल्लंघन करता है तो इतनी ही कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि दूसरे उससे सबक लें। वृक्षों के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसलिए पेड़ों को बचाना हर नागरिक का कर्तव्य है। विकास के लिए सड़कें जरूरी हैं, लेकिन इस बात का भरपूर प्रयास हो कि कम से कम वृक्ष काटने पड़ें और उनकी प्रतिपूर्ति में दस गुणा पौधे लगाए जाएं।

> कानूनी प्रविधानों के बारे में जानकारी होने के बावजूद यदि कोई उसका उल्लंघन करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए

चीन पर भरोसा न करे भारत

श्रीराम चौलिया

जब तक चीन भारत के आगे बढ़ने में अड़चनें डालता रहेगा, तब तक उससे दोस्ती की अपेक्षा काल्पनिक ही बनी रहेगी

अवधेश राजपूत

पांच वर्षों के अंतराल के बाद भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच उच्चस्तरीय वार्ता के बाद द्विपक्षीय संबंधों में नरमी के संकेत मिले। इस वार्ता में भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन की ओर से विदेश मंत्री वांग यी शामिल हुए। वार्ता की यह पहल पूर्वी लद्दाख और अक्साई चिन सीमा पर 2020 से चले आ रहे सैन्य टकराव को सुलझाने के पश्चात आरंभ की गई है। उस समझौते के तहत चीन ने विवादित क्षेत्रों से अपनी सेना को पीछे हटाया है, जहां उसने भारतीय सेना को गश्त करने से रोका था। सैन्य निकासी के अलावा चीन ने आश्वासन दिया है कि दोनों पक्ष एक-दूसरे के 'मूल हितों और प्रमुख सरोकारों को समझते हुए और ईमानदारी एवं सद्भावना के साथ मतभेदों को सुलझाने के लिए तैयार हैं।' कूटनीतिक सरगर्मियों के मद्देनजर अहम सवाल यही है कि क्या चीन का भारत के प्रति बर्ताव कोई हृदय परिवर्तन हुआ है और अगर ऐसा हुआ है तो इसका कारण क्या है? बीते 12 वर्षों से चीन पर राज करते हुए तानाशाह राष्ट्रपति शी चिनफिंग की मंशा पर ध्यान दें तो यह असंभव है कि उन्होंने एशिया और विश्व में चीन के वर्चस्व और विस्तारवाद का सपना रातोंरात त्याग दिया है। 'प्रमुख देश कूटनीति' नामक उनकी अवधारणा के अनुसार चीन कभी भी अपने 'वैध अधिकारों और हितों' को नहीं छोड़ेगा और पड़ोसी देशों के साथ विवादों में अपनी शक्ति एवं श्रेष्ठता के बलबूते हावी रहेगा। भारत के अलावा एक दर्जन से अधिक देशों के साथ चीन के अनसुलझे क्षेत्रीय विवाद हैं और इन सभी के प्रति शी के शासन में चीन ने दबंग व्यवहार अपनाकर धौंस देना जारी रखा है। 'ग्रे जोन' और 'सलामी स्लाइसिंग' रणनीतियों का उपयोग करते हुए चीन ने पड़ोसियों पर सैन्य एवं आर्थिक दबाव डालकर यही चेष्टा की है कि कमजोर देशों पर चीन की इच्छा थोपी जाए। उनके अतिराष्ट्रवादी 'चीनी स्वप्न' का लक्ष्य एशिया में उस पुराने साम्राज्यवादी युग को पुनः स्थापित करना है, जहां चीन का कथित तौर पर प्रभुत्व था और पड़ोसियों को बीजिंग में सम्राट के सामने झुककर प्रणाम करना पड़ता था।

शी जैसे कट्टर निरंकुश नेता का इतने भव्य एवं महत्वाकांक्षी स्वप्न को भुला देना नामुमकिन है। चीन को केवल महाशक्ति बनना ही नहीं, बल्कि अमेरिका को पछाड़कर विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित करने और चीनी मूल्यों पर आधारित नई विश्व व्यवस्था कायम करने जैसे लक्ष्यों को साधने के लिए वह कोई कोर-कसर नहीं छोड़ने वाले। हालांकि उनकी यह राह आसान नहीं। अमेरिका और उसके सहयोगी देश भी चीन की इस राह में कांटे बिछाने के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे। यह कोई संयोग नहीं है कि चीन ने भारत समेत जिन एशियाई देशों के साथ स्थलीय और समुद्री सीमाओं से जुड़े विवाद नहीं निपटाए, उनकी अमेरिका के साथ गलबहियां बढ़ी हैं। असल में चीन को संतुलित करने की दृष्टि से ही इन देशों का झुकाव अमेरिका की ओर बढ़ा है, जिससे चीन और चिढ़ता है। चीन यह चाहता है कि सीमाओं पर दबाव घटाने के बदले पड़ोसी देश अमेरिका से किनारा करें या अमेरिका के साथ मिलकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उसके लिए मुश्किलें पैदा न करें। इसका अर्थ है कि पड़ोसियों को अपनी विदेश नीति स्वतंत्रता और सामरिक स्वायत्तता को सीमित करना होगा और चीनी प्रभुत्व वाली क्षेत्रीय व्यवस्था को स्वीकार करना होगा। इस प्रकार की शर्त किसी भी स्वाभिमानी देश विशेषकर भारत जैसी उभरती महाशक्ति को कतई स्वीकार्य नहीं हो सकती।

अजीत डोभाल और वांग यी के बीच हालिया वार्ता बिजादित 'सीमा प्रश्न' पर विशेष प्रतिनिधियों की 23वीं बैठक है और यह सिलसिला बिना किसी अंतिम सहमति के वर्ष 2003 से निरंतर जारी है। इसके अतिरिक्त, 'सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र' की 2012 से अब तक 32 बैठकें हो चुकी हैं। इनमें भाग लेने वाले भारतीय वार्ताकारों और राजनयिकों का मानना है कि चीन इस विवाद को हमेशा के लिए समाप्त करने का इच्छुक नहीं दिखता और वह भारत की ओर से प्रस्तुत किए गए मानचित्रों को बारीकियों में भी नहीं जाता। चीन लगातार थकाऊ वार्ताओं के माध्यम से संघर्ष को प्रबंधित करने का प्रयास करता है, परंतु अपने क्षेत्रीय दावों को नहीं छोड़ता।

वर्ष 2020 में गलवन घाटी में मुठभेड़ और उसके बाद करीब सात हजार सैनिकों एवं भारी-भरकम हथियारों की तैनाती चीन की खासी महंगी पड़ी। भारतीय सेना ने जिस मुस्तैदी के साथ जवाबी कार्रवाई की और अतिरिक्त चीनी घुसपैठ के लिए सभी रास्ते बंद कर दिए, उससे शी की चिंताएं बढ़ा दी थीं। अमेरिका के साथ भारत की सामरिक साझेदारी भी बीते कुछ वर्षों के दौरान जिस प्रकार मजबूत होती गई, उससे भी चीन के माथे पर बल डालने का काम किया। ट्रंप की वापसी और उनके द्वारा छेड़े जाने वाले संभावित व्यापार युद्ध व सैन्य चुनौती भी शी की आशंका का कारण है। ऐसे में, भारत के प्रति नरम रवैये का प्रदर्शन कर शी चीन के लिए थोड़े समय के लिए सामरिक राहत की खोज में होंगे।

देपसांग और देमचोक से चीनी सेना की वापसी शी की नाकामी का परिचायक है, लेकिन यह ध्यान रहे कि उनके जैसे महत्वाकांक्षी तानाशाह आसानी से हार नहीं मानते। चीन भारत को झुकाने का इरादा तब तक मन में रखेगा, जब तक वह आश्वस्त न हो जाए कि भारत अमेरिका के संग मिलकर उसकी घेराबंदी करना नहीं छोड़ता। चूंकि अमेरिका की मित्रता भारत के उत्थान के लिए अनिवार्य है, इसलिए चीन के साथ भारत की अनबन और प्रतिस्पर्धा में कमी की अपेक्षा अवास्तविक है। भारत-चीन वार्ता के दौर सीमा पर उलझित नियमों को बहाल करने में कमोबेश मददगार हो सकते हैं, लेकिन भू-राजनीतिक स्तर पर मैत्रीपूर्ण संबंध की संभावना दूर की कौड़ी है। जब तक चीन भारत के महाशक्ति बनने में अड़चनें डालता रहेगा, उससे दोस्ती की अपेक्षा काल्पनिक बनी रहेगी। भारत को अपनी सैन्य तैयारियों और क्षमताओं को उन्नत करते हुए चीन से सतर्क रहने की नीति पर ही चलना होगा।

(लेखक जिंदल स्कूल आफ इंटरनेशनल अफेयर्स में प्रोफेसर और डीन हैं)

response@jagran.com

संविधान को बचाने का दिखावा

जगमोहन सिंह राजपूत

इन दिनों जगह-जगह संविधान की प्रति लहराने का एकमात्र उद्देश्य देश का ध्यान भटकाना है

आजकल संविधान हर तरफ चर्चा में है, लेकिन यह पहली बार दिख रहा है कि संविधान के नए संरक्षक उसे बचाने के लिए सबसे अधिक उत्सुक दिख रहे हैं। यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर वे किससे संविधान को बचा रहे हैं? अच्छी बात यह है कि इस सबके बीच देश संविधान पर घातक आघात किए जाने के उन दो वर्षों को पुनः याद कर रहा है, जो उसने 1975-77 के मध्य झेले थे। स्वाभाविक है कि उन लोगों को भी याद किया जा रहा है, जिन्होंने संविधान को उस समय बचाया था। देश में जेपी जैसे स्वतंत्रता संग्राम के तपे हुए नेता मौजूद थे, जिनकी निःस्वार्थ अगुआई में जनता ने संविधान बचाया था। नीयत में खोट और अनुभवहीनता का जब सत्ता प्राप्ति के संदर्भ में समन्वय हो जाता है, तो हास्यास्पद स्थितियां निर्मित हो जाती हैं। भारत की राजनीति में इस समय यही स्थिति बन गई है। संविधान की मूल भावना अपनी संपूर्णता के साथ उसके आमुख में निहित थी। वह एक संपूर्ण प्रतिज्ञा है, जिसे निभाने के लिए हर नागरिक को प्रतिबद्ध होना चाहिए। वे लोग जो संवैधानिक पदों पर जनप्रतिनिधि बनकर पहुंचते हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे उसके अनुपालन का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करेंगे।

संविधान हर भारतवासी को एक बेहतर जीवन देने के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धता का वह दस्तावेज है, जो इंगित करता है कि व्यवस्था किस प्रकार आगे बढ़ेगी। यह सामान्य अपेक्षा है कि हर नागरिक अपने उत्तरदायित्व निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ लक्ष्य प्राप्ति के लिए अवश्य करे। 'लोक हिताय मम कर्तव्यम' संविधान में हर प्रकार से रचा बसा है। कौन उसे कितना आत्मसात कर पाता है, यह व्यक्ति की अपनी क्षमता पर ही नहीं, उसके जीवन मूल्यों पर भी निर्भर करता है। आप संविधान को जितनी बार पढ़ेंगे, आपकी समझ का दायरा उतना ही बढ़ता जाएगा। इसे के साथ संविधान निर्माताओं के प्रति सम्मान भी बढ़ता जाएगा। मैं उन लोगों में हूं, जिन्हें संविधान का आमुख 1955 के आसपास स्कूल में ही कंठस्थ करा दिया गया था। आपातकाल में इसे परिवर्तित किया गया और इसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द जोड़े गए। यह परिवर्तन दुरदर्शी संविधान निर्माताओं की समझ का अपमान था। यह परिवर्तन उस संसद ने किया, जिसका सारा विपक्ष जेल में यातनाएं झेल रहा था। उसका कार्यकाल तक संविधान के प्रविधानों को शैंटकर पांच साल से बढ़ाकर सात साल कर दिया गया था। कैसी विडंबना है कि इस सबके लिए जिम्मेदार लोग आज संविधान के संरक्षक बनकर देश की जनता का समर्थन पाने की अभिलाषा कर रहे हैं।

लोकसभा में संविधान की प्रति दिखाते राहुल। एएनआइ

भले ही सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आमुख परिवर्तन को बदलने की आवश्यकता न मानी हो, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि आमुख बदल जाएगा, ऐसी कल्पना तो शायद राजेंद्र प्रसाद या भीमराव आंबेडकर और संविधान सभा के अन्य सदस्यों ने भी कभी नहीं की होगी। सामान्य नागरिक के लिए यह समझ पाना कठिन है कि जो सर्वोच्च न्यायालय यह निर्णय देता है कि कमजोर लोग आज संविधान के संरक्षक बनकर देश की जनता का समर्थन पाने की अभिलाषा कर रहे हैं।

अंबेडकर और गांधीजी ने पश्चिम में शिक्षा ग्रहण की थी, लेकिन वे भारतीयों की उस श्रेणी में नहीं थे, जिन्हें पश्चिम की पढ़ाई ने अपने देश और संस्कृति से अलग कर दिया हो, जैसा अधिकांश विलायत में पढ़े लोगों के साथ हुआ। भारत, उसकी सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति, उसकी वैचारिक समृद्धता और मनुष्य मात्र की एकता में विश्वास की जितनी गहरी समझ इन मनीषियों ने गहन अध्ययन से प्राप्त की, वह अद्वितीय थी। क्या उनके साथ-साथ राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय आदि का आचरण और जीवन जीने की पद्धति यह स्पष्ट नहीं करती थी कि पंथनिरपेक्षता की निर्मल और व्यावहारिक समझ भारत में सदा उपस्थित थी? क्या यह भावना आमुख तथा संविधान के हर पृष्ठ पर स्पष्ट नहीं होती? संविधान सभा ने इन शब्दों के संबंध में चर्चा भी की थी और उन्हें न जोड़ने का निर्णय लिया था।

डा. आंबेडकर ने 25 नवंबर, 1949 के अपने ऐतिहासिक भाषण में यह कहा था कि संविधान कितना अच्छा होगा, यह आगे चलकर उसे चलाने वालों पर निर्भर करेगा। 1975-77 में यह शब्दशः सत्य सिद्ध हुआ, जब पद पर बने रहने की लालसा ने संविधान के साथ ऐसा अत्याचार किया, जिसे इतिहास भूलेगा नहीं। इस समय संविधान बचाने का जो शेर सुनाई दे रहा है और जिसकी प्रति संसद से संभल तक लहराई जा रही है, वह देश का ध्यान भटकाने की कोशिश मात्र है। संविधान की प्रति हर जगह लहराने वाले लोग यदि एक बार यह कहते कि उनके हाथ में वह प्रति है, जिसमें आचार्य नंदलाल बोस द्वारा भारतीय संस्कृति को दर्शाते हुए सभी चित्र भी शामिल हैं, तो बात बनती। ये चित्र पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुरोध पर बनाए गए थे। संविधान का सम्मान तो तब होगा, जब यह प्रश्न उठाया जाए कि ये चित्र हटाए क्यों गए? संविधान के प्रति निष्ठा प्रकट करने के दिखावे के स्थान पर यह मांग उठाई जानी चाहिए कि भविष्य में संविधान की कोई प्रति बिना इन चित्रों के छापना दंडनीय अपराध होगा। आचार्य नंदलाल बोस ने बहुत मनोयोग से ये चित्र बनाए थे। उन्हें पुनः स्थापित कर उनके अपमान की भरपाई होनी चाहिए।

यह देखना दयनीय है कि सत्ता पाने के लिए व्याकुल लोगों की व्यग्रता अब उग्रता के रूप में प्रकट हो रही है। संसद के कार्य संचालन में जैसे व्यवधान डाले जा रहे हैं, वे न तो भारत के संविधान के प्रति कोई आदरभाव प्रकट करते हैं, न ही अंबेडकर के प्रति कोई श्रद्धा प्रकट करते हैं।

(लेखक प्रधानमंत्री स्मारक एवं ग्रंथालय में फेलो हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

विवेक

मनुष्य की स्वाभाविक विचार चेतना भौतिकतावादी होती है। वह जिस समाज में रहता है, उसके वातावरण का प्रभाव उस पर अवश्य ही पड़ता है। अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह जो संघर्ष करता है, उसका प्रभाव उसके मन-मस्तिष्क पर पड़ता ही है। इस भौतिक संसार में रहकर जीवन-जगत की स्वाभाविकता के कारण जो विचार और संकल्प मनुष्य बनाता है, पुरुषार्थ करने पर वह भौतिक वस्तुओं के रूप में उन्हें प्राप्त कर सकता है। यदि हम गहनता से विचार करें तो यह भौतिक उपलब्धियां मानव जीवन में स्थायी शांति प्रदान नहीं कर सकतीं। अविवेक के कारण हम इन्हें सुख मान लेते हैं और आनंद का साधन भी। वास्तव में आनंदमयी शांति की प्राप्ति के लिए विवेक का होना आवश्यक है। जीवन की यथार्थ दृष्टि विवेक से ही प्राप्त हो सकती है। कर्तव्य और अकर्तव्य का भेद विवेक से ही प्राप्त हो सकता है।

तुलसीदास जी कहते हैं कि विवेक सत्संग से प्राप्त होता है। गीता में वर्णन है कि किंकर्तव्यविमूढ़ महारथी अर्जुन अनिश्चय की स्थिति से बाहर निकालने के लिए अपने आराध्य भगवान श्रीकृष्ण से विवेक की प्रार्थना करते हैं। भगवान श्रीकृष्ण के उपदेश के बाद उनमें विवेक अर्थात यथार्थ ज्ञान जागृत हो जाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच उन्हें अनुकूल ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे भ्रम की स्थिति समाप्त हो जाती है।

वस्तुतः विवेक की परिभाषा ही यह है कि मोह जनित भ्रम का नाश हो जाए और यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो। इसे ही हम ईश्वरीय बोध कह सकते हैं। यह बोध मनुष्य को मानसिक चिंताओं से मुक्त कर आनंदमय जीवन प्रदान करता है। जिस प्रकार तैरने की कला में माहिर व्यक्ति डूबती हुई नाव से कूद कर सरलता से तैरकर अपने प्राणों की रक्षा कर सकता है। ठीक इसी प्रकार विवेक से परिपूर्ण व्यक्ति इस दुखमय संसार रूपी सागर को विवेक की सहायता से तैरकर पार कर सकता है।

डा. प्रशांत अग्निहोत्री

स्पिन के महारथी के सुनहरे युग का अंत

नृपेंद्र अभिषेक नृप

स्पिन गेंदबाजी को नई ऊंचाई देने के साथ ही अश्विन ने भारतीय क्रिकेट के प्रशंसकों को कई यादगार पल भी दिए हैं

भारतीय क्रिकेट स्पिन गेंदबाजों का गढ़ रहा है। इस परंपरा ने हाल के वर्षों में हमें अनिल कुंबले, हरभजन सिंह और रविचंद्रन अश्विन जैसे खिलाड़ी दिए हैं। अश्विन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। क्रिकेट में अपने कौशल का परचम लहराते हुए उन्होंने भारत को इस मामले में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया।

अश्विन ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2010 में जिंबाब्वे के खिलाफ बनडे मैच से की थी। इसके बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी अपनी जगह बनाई और अपने पहले ही टेस्ट मैच में नौ विकेट लेकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। अश्विन का गेंदबाजी स्टाइल उन्हें सबसे अलग बनाता है। उनकी आफ स्पिन गेंदबाजी में विविधता, फ्लाइट और गति का अद्भुत संयोजन देखने को मिलता है। उनकी 'कैरम बाल' ने कई बल्लेबाजों को परेशान किया और उन्हें विश्व क्रिकेट में खास पहचान दिलाई। उनकी गेंदबाजी में गहराई और बल्लेबाजों को पढ़ने की क्षमता उनकी सफलता का मूल कारण रही है। कुंबले और हरभजन सिंह के संन्यास के बाद भारतीय टीम में एक ऐसे स्पिनर की जरूरत थी जो टेस्ट क्रिकेट में विकेट निकाल सके और कठिन परिस्थितियों में टीम का साथ दे सके। अश्विन ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। कुंबले की तरह अश्विन ने भी टेस्ट क्रिकेट में निरंतरता और दृढ़ता दिखाई। हरभजन की तरह आक्रामकता और बल्लेबाजों पर मानसिक दबाव बनाने की कला सीखी।

अश्विन का संन्यास भारतीय क्रिकेट के लिए एक युग के अंत जैसा है। हालांकि उन्होंने आइपीएल में खेलना जारी रखने का संकेत दिया है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनकी अनुपस्थिति को महसूस किया जाएगा। उनके संन्यास का फैसला कई कारणों से लिया गया हो सकता है, जिनमें उम्र, शारीरिक थकान और युवा खिलाड़ियों को मौका देने की भावना शामिल हो सकती है। अश्विन ने युवा खिलाड़ियों को प्रेरित किया है और स्पिन गेंदबाजी की नई परिभाषा गढ़ी है। उनकी सोच, तकनीक और रणनीतियां भारतीय क्रिकेट के लिए एक धरोहर हैं। उन्होंने टीम इंडिया को कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाला और कई मैच जिताए। उन्होंने दिखाया कि एक स्पिनर भी आलराउंडर बन सकता है। अश्विन के संन्यास के बाद भारतीय टीम को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल जैसे स्पिनर टीम में हैं, लेकिन अश्विन जैसी विविधता और अनुभव हासिल करने में समय लगेगा।

अश्विन का करियर भारतीय क्रिकेट के स्वर्णिम अध्यायों में दर्ज रहेगा। उनके संन्यास के बाद टीम में उनकी कमी जरूर महसूस होगी, लेकिन उनके द्वारा स्थापित मानदंड आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

पारदर्शिता आवश्यक

'इंडीएम पर बेजा सवाल उठाने के खतरे' शीर्षक से लिखे आलेख में राहुल वर्मा ने इंडीएम पर कुछ दलों के रवैये को लोकतंत्र के लिए हानिकारक बताया। वैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की हमारी छवि केवल इंडीएम पर सवाल उठाने से ही कमजोर नहीं हो रही। हमारे नेताओं की तुच्छ राजनीति से भी यह प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। भारत में चुनाव आयोग हर चुनाव से पहले ईवीएम की उचित और निष्पक्ष जांच करता है, इसलिए ईवीएम में गड़बड़ी की जरा भी उम्मीद नहीं की जा सकती। इसके बावजूद किसी भी प्रकार के संदेह दूर किए ही जाने चाहिए। दुनिया के दूसरे कोनों में भी ईवीएम जैसी मशीनों को लेकर संदेह व्यक्त किए जाते हैं, उसे देखते हुए निर्वाचन आयोग को पूरे तथ्य सामने रखने चाहिए कि भारतीय ईवीएम कैसे सबसे अलग है और उसमें जरा भी हेरफेर की कोई गुंजाइश नहीं। इस दिशा में लेखक ने एप बनाने का जो सुझाव दिया वह सराहनीय है। जितनी पारदर्शिता बढ़ेगी, उससे उतना ही लाभ मिलेगा।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

रविचंद्रन अश्विन का संन्यास

दिग्गज स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। भारत के इस महान स्पिनर के संन्यास की घोषणा एक तरह से चौंकाने वाला बड़ा फैसला भी रहा, क्योंकि वह भारत के लिए कई बार मुश्किल परिस्थितियों में दमदार प्रदर्शन कर चुके हैं। अश्विन बालिंग के साथ-साथ बैटिंग में भी कमाल दिखा चुके हैं। वह भारत के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। उनके आगे केवल अनिल कुंबले हैं। इसके साथ ही अश्विन के नाम टेस्ट में 37 बार पांच विकेट लेने का रिकार्ड भी है, जो किसी भारतीय गेंदबाज द्वारा सबसे ज्यादा है। अश्विन ने इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लिए, इसके साथ ही अश्विन टेस्ट में सबसे ज्यादा प्लेयर आफ द सीरीज अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ी हैं। भारत के घरेलू मैदानों पर रविचंद्रन अश्विन की तूती बोलती थी। वह भारतीय स्पिन गेंदबाजी के आधार स्तंभ थे। भारत में उनके स्पिन गेंद का सामना करना विपक्षी टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती थी। भारत में कई बड़ी विजय के वह नायक रहे हैं। भारत अपनी जमीन पर इस दिग्गज स्पिनर की कमी को महसूस करेगा। एक बात का हमेशा क्रिकेट प्रेमियों को मलाल रहेगा कि कई महान खिलाड़ियों की तरह उन्हें भी विदाई मैच खेलने का अवसर नहीं मिला।

विजय किशोर तिवारी, नई दिल्ली

परीक्षा में पारदर्शिता

वर्ष 2024 की नीट की परीक्षा को लेकर नेशनल टेस्ट एजेंसी (एनटीए) विवादों के घेरे में आ गई थी। इस प्रकार से शिक्षा मंत्रालय द्वारा जांच कमेटी बैठाई गई और विभिन्न याचिकाएं विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय तथा देश की सबसे बड़ी अदालत उच्चतम न्यायालय में लगाई गईं। जिसके तहत इसरो के पूर्व अध्यक्ष डा. के. राधाकृष्णन के नेतृत्व में गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को अक्टूबर 2024 में सौंप दी थी। समिति ने एनटीए के कार्य पर विभिन्न तरह के सवाल भी खड़े किए थे। वर्ष 2024 में एनटीए ने विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन किया। इसी संस्था द्वारा विभिन्न पदों की भरने के लिए परीक्षाएं ली गईं थीं। विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालय में नियुक्तियों को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। एनटीए द्वारा ली गई नीट और जेईई की परीक्षा के साथ-साथ विभिन्न अन्य परीक्षाओं में विभिन्न तरह की खामियां पाई गईं। जांच समिति ने इस बात की सिफारिश की कि किसी भी तरह की भर्ती एनटीए द्वारा नहीं की जाएगी। समिति द्वारा सिफारिश की गई कि किसी भी निजी स्कूल में परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। यहां तक कि सभी परीक्षा केंद्र विश्वविद्यालय, कालेज, सरकारी स्कूलों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ही होंगे। प्रश्न पत्र लीक होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए कमेटी ने संस्तुति की है कि ऐसे मामलों पर सख्त करवाई हो तथा इसमें जिम्मेदारी भी तय की जाए।

मीना धानिया सिरसपुर, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचंद्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *सब जूडिस में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

हिन्दुस्तान
1936

कैंसर का मुफ्त टीका

रूस ने यह घोषणा करके दुनिया को चौंका दिया कि उसने कैंसर के इलाज के लिए अपना खुद का एमआरएनए-आधारित टीका विकसित कर लिया है, जो 2025 की शुरुआत से देश के मरीजों के लिए मुफ्त उपलब्ध हो जाएगा। यह टीका शरीर में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पैदा करेगा। यह प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पैदा करने के लिए मैसेंजर आरएनए (एमआरएनए) नामक अणु की एक प्रतिलिपि का उपयोग करेगा। खास बात यह है कि रूस में यह टीका सभी कैंसर रोगियों को मुफ्त में दिया जाएगा। ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में लगे रूस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। कामयाबी की पुष्टि वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी की है। यह रूसी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जो दो-तीन वर्षों से अच्छी खबरों के लिए तरस गए हैं। परीक्षणों में यह साफ हो गया है कि कैंसर का यह टीका शरीर में ट्यूमर के विकास और उसकी आशंका को दबा देता है। अगर वाकई ऐसा संभव हो जाएगा, तो यह दुनिया के लिए किसी क्रांति से कम नहीं होगा।

दूसरी खास बात यह है कि यह टीका व्यक्तिगत या मरीज की शारीरिक जरूरत के अनुरूप तैयार किया जा सकता है। मतलब एक ही टीका सभी को नहीं दिया जाएगा। कोरोना वैक्सीन को लेकर यह शिकायत बहुत आम रही थी कि इसके वैक्सीन ने किसी पर बहुत अच्छी तरह काम किया है, तो किसी को नुकसान पहुंचाया। ऐसे में, तमाम टीकों को लेकर यह नई चर्चा शुरू हो गई है कि कोई भी टीका मरीज को जरूरत के हिसाब से ही दिया जाए। यह व्यक्तिपरक या 'पर्सनलाइज्ड' टीका वक्त की बड़ी जरूरत है। लोगों के शरीर की क्षमता समान नहीं होती है, अतः किसी दवा को झेलने की क्षमता कैसे समान हो सकती है? वैज्ञानिकों के अनुसार, रूस में विकसित कैंसर का टीका लगभग एक घंटे के भीतर मरीज की जरूरत के अनुसार तैयार किया जा सकता है। पहले इस काम के लिए काफी समय लगता था, पर अब वैज्ञानिक इस समय को लगातार घटाते चले जा रहे हैं। अन्य दवाओं के मामले में भी ऐसे ही प्रयोग को आगे बढ़ाना चाहिए। नया दौर जरूरत के अनुरूप दवाओं के विकास का होना चाहिए और इस काम में एआई या तकनीक का बेहतर इस्तेमाल होने लगा है। कहना ही चाहिए कि रूस के वैज्ञानिक एक समय अपने प्रयोगों के मामले में बहुत आगे रहे हैं। युद्ध की वजह से वहां विज्ञान का बजट प्रभावित हुआ है, अतः यहां भी हम यह उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि युद्ध जल्दी खत्म होगा और रूस दुनिया को खुशहाल और सेहतमंद बनाने की दिशा में ज्यादा काम करेगा।

रूस में हुए वैज्ञानिक परीक्षणों में बहुत साफ हो गया है कि कैंसर का यह खास टीका शरीर में ट्यूमर के विकास और उसकी आशंका को दबा देता है।

ध्यान देने की बात है कि कैंसर के खिलाफ वैक्सीन बनाने की कोशिशें सौ साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। अभी भी दस से ज्यादा प्रकार के कैंसर के लिए दस से ज्यादा प्रकार के वैक्सीन उपलब्ध हैं। इसके बावजूद दुनिया में सौ से ज्यादा संस्थानों में कैंसर के इलाज पर प्रयोग जारी हैं। रूस की बात करें, तो साल 2008 में वहां किडनी के कैंसर का टीका तैयार किया गया था। कहना ही चाहिए कि कैंसर एक बड़ी महामारी बन चुका है। साल 2022 में दुनिया में इसकी वजह से 97 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई थी और कैंसर के दो करोड़ नए मामले सामने आए थे। ये आंकड़े डराते हैं और प्रेरित करते हैं कि दुनिया के विकसित देश अपने फिजूल के खर्च रोककर अपने ज्यादा से ज्यादा धन व संसाधन का उपयोग दवाओं के विकास में करें, ताकि यह दुनिया रहने लायक अच्छी जगह बनी रहे।

हिन्दुस्तान HinduStan | 75 साल पहले 19 दिसंबर, 1949

भारत से आशाएं

विश्व की गत सप्ताह की घटनाओं का सिंहावलोकन करने पर हमें स्पष्ट रूप से विदित होता है कि एशियाई घटनाक्रम तेजी से घूमता हुआ दुनिया के दूसरे देशों की गतिविधि को भी प्रभावित कर रहा है। चीन में साम्यवादियों की विजय ने कितनी ही नई समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं। इस तथ्य को हृदयंगम करते हुए संसार के विचारशील व्यक्ति तथा दूरदर्शी राजनीतिज्ञ यह अनुभव करने लगे हैं कि इस समय एशिया में भारत ही ऐसा देश है, जो अपनी सुव्यवस्थित स्थिति तथा सुदृढ़ता के कारण एशिया की लोकतंत्रात्मक शक्तियों के लिए आशा का आधार बन सकता है। किन्तु इसके साथ यह भी एक निर्विवाद तथ्य है कि एशिया तथा अफ्रीका अराजकता की विभीषिका से तभी मुक्त हो सकते हैं, जबकि दुनिया के ये सबसे बड़े महाद्वीप, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से ही प्रधान नहीं हैं, अपितु सभ्यता, इतिहास तथा संस्कृति की दृष्टि से भी बहुत प्राचीन तथा महत्वपूर्ण हैं, साम्राज्यवाद, जातीय भेदभाव तथा आर्थिक शोषण से मुक्त हो जायें।

संयुक्त राष्ट्र संघ कई मामलों में भले असफल रहा हो किन्तु दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका के प्रश्न पर उसने एक आदर्श कायम किया है। उसकी इस सफलता पर पादरी माइकेल स्काट ने भी उसे बधाई दी है। ''तूफान की काली घटाओं'' से स्पष्टस भयभीत हैं किन्तु इनके उठने का कारण मलान की वह शोषक तथा उत्पीड़क नीति है, जिसने अश्वेत जातियों को दासों की स्थिति में रख दिया है। उनकी दयनीय स्थिति का उल्लेख करते हुए पादरी स्काट ने बताया है कि दक्षिण अफ्रीका का जनसंख्या का तीन चौथाई भाग वहां की आदि जनता है किन्तु उसके पास केवल १३ प्रतिशत भूमि है। और दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में गोरों के पास ५८ प्रतिशत भूमि पड़ी हुई है। इस महाद्वीप की काली जनता राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक सभी रूपों में पददलित तथा शोषित है। सभ्य दुनिया तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए भी उसके पास कोई साधन नहीं। पादरी स्काट ने प्रेस-प्रतिनिधि से एक मुलाकात में कहा : ''यदि दक्षिण अफ्रीका की वर्तमान जाति उत्पीड़न नीति जारी रही, तो इसका परिणाम खून की नदी ही होगा।'' इस भविष्यवाणी में सारे सभ्य मानव समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी निहित है। एशिया तथा अफ्रीका के शोषित, पीड़ित तथा परतंत्र देशों के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उसके बाहर तो आवाज उठाई, वह व्यर्थ नहीं गई।

शीतलहर और प्रदूषण का दोहरा प्रहार

ब्रिटेन, आयरलैंड और नीदरलैंड में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों पर किए गए अध्ययन में पाया गया कि चार दिन की ठंड से भी दिल के दौरे की आशंका दोगुनी से अधिक बढ़ जाती है।

यहां स्कैन करें

राजीव दासगुप्ता | प्रोफेसर (कम्युनिटी हेल्थ), जेएनयू

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक बुधवार सुबह आठ बजे 481 अंकों के साथ फिर से 'गंभीर श्रेणी' में पहुंच गया। वायु प्रदूषण में इस कदर की वृद्धि करीब तीन सप्ताह के अंतराल के बाद हुई है, जब 'ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान' के चौथे चरण के तहत प्रतिबंध लगाए गए थे। प्रदूषण को ठंड का भी साथ मिला है। दिल्ली स्थित क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र ने सुबह में धुंध और मध्यम से घना कोहरा रहने, आंशिक रूप से बादल छाए रहने और न्यूनतम तापमान लगभग छह डिग्री रहने का अनुमान लगाया। जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के साथ ही दिल्ली में भी शीतलहर चलने की बात कही गई है।

दरअसल, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग शीतलहर की घोषणा तब करता है, जब किसी मैदानी इलाके में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या इससे कम हो जाता है, जबकि पहाड़ी इलाकों में तापमान शून्य डिग्री या इससे नीचे चला जाता है। सामान्य और मूल तापमान के बीच के अंतर के लिहाज से देखें, तो शीतलहर की स्थिति तब मानी जाती है, जब तापमान सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस कम हो, जबकि गंभीर शीतलहर में तापमान में सामान्य से 6.4 डिग्री सेल्सियस से अधिक की गिरावट आती है। वैसे, वास्तविक न्यूनतम तापमान (केवल मैदानी इलाकों के लिए) के आधार पर बात करें, तो शीतलहर में न्यूनतम तापमान चार डिग्री या इससे कम हो जाता है, जबकि गंभीर शीतलहर की स्थिति में यह घटकर दो डिग्री सेल्सियस या इससे कम हो जाता है। हालांकि, नवंबर से मार्च तक उत्तर भारत सहित अन्य क्षेत्रों में शीतलहर की स्थिति आम मानी जाती है, लेकिन दिसंबर से फरवरी के बीच इसकी मारकता हमें ज्यादा परेशान करती है। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है।

अत्यधिक गर्मी की तरह अत्यधिक सर्दी भी बेघरों, बुजुर्गों, आर्थिक रूप से विपन्न, दिव्यांगों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली स्त्रियों, बच्चों, किसानों, खुले में काम करने वाले मजदूरों और उन लोगों को परेशान करती है, जो बिना उचित गर्मांहट के या मौसम के प्रतिकूल हालात में काम करने के लिए मजबूर हैं। अगर एहतियाती उपाय नहीं किए गए, तो अत्यधिक ठंड कई तरह से नुकसान भी पहुंचा सकती है, यहां तक कि इंसान की मौत भी हो सकती है।

ठंड लगने से हाइपोथर्मिया, फ्रॉस्टबाइट, यानी अत्यधिक ठंड से सुन्न हो जाना, ट्रेंचफुट, चिलब्लेन जैसी परेशानियां हो सकती हैं। इनमें सबसे अधिक जानलेवा स्थिति हाइपोथर्मिया है, जो बहुत ठंडे तापमान के संपर्क में लंबे समय तक रहने के कारण होती है और शरीर जितनी गर्मी पैदा कर सकता है, उससे ज्यादा तेजी से खोने लगता है। इससे शरीर का तापमान बहुत कम हो जाता है, जिससे मस्तिष्क प्रभावित होता है और व्यक्ति ठीक ढंग से सोचने या चलने में असमर्थ हो जाता है। उल्लेखनीय है कि हाइपोथर्मिया तब भी खतरनाक बन सकती है, जब कोई व्यक्ति बारिश, पसीने या ठंडे पानी में डूबने से ठंडा हो जाता है।

होता यह भी है कि तापमान के नीचे गिरने के बाद हमारे शरीर की रक्त वाहिकाएं सिकुड़ने लगती हैं और हमारा रक्तचाप (बीपी) बढ़ने लगता है। इससे हमारे हृदय पर दबाव बढ़ने लगता है, जिससे स्वाभाविक तौर पर दिल के दौरे या हृदयाघात का खतरा बढ़ जाता है। अत्यधिक ठंड हमारे हृदय की धड़कनों को भी असामान्य बना देती है, जिससे खासतौर पर उन लोगों के लिए जानलेवा स्थिति बन सकती है, जो पहले से ही हृदय संबंधी बीमारियों से ग्रसित हैं। ब्रिटेन, आयरलैंड और नीदरलैंड में 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों पर किए गए एक व्यापक अध्ययन में पाया गया कि ठंड यदि चार दिनों का भी रहा, तो दिल के दौरे और हृदयाघात की आशंका दोगुनी से अधिक बढ़ जाती है। यह अध्ययन दरअसल महीने के बाकी दिनों की तुलना में विशेष रूप से ठंडे दिनों को परिभाषित करने के उद्देश्य से किया गया था। इसमें तापमान की पिछले दिनों की तुलना में गिरावट को हृदयाघात का मुख्य कारक माना गया, न कि महसूस होने वाले ठंड को।

शीतलहर और सर्द हवाएं कई तरह से हमारे फेफड़ों पर भी नकारात्मक असर डालती हैं। ठंडी हवा आम तौर पर शुष्क होती है और श्वसन-मार्ग को प्रभावित करती है, जिससे घरघराहट, खांसी और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। यह स्थिति अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) जैसी बीमारियों से ग्रसित लोगों के लिए विशेष रूप से खतरनाक हो सकती है। ठंडी हवा श्वसन-मार्ग की संकीर्ण और सख्त कर सकती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, जो विशेष रूप से छोटे बच्चों को प्रभावित कर सकती है। ठंड की स्थिति में हवा की गुणवत्ता भी खराब हो जाती है और पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन डाई-ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों जैसे प्रदूषकों के संपर्क में आने से फेफड़ों में जलन और श्वसन संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए पिछले दो दिनों में प्रदूषण बढ़ने के साथ ही लोगों में खांसी और सांस संबंधी समस्याएं बढ़ गई हैं।

जाहिर है, इस समय हमें कई तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। ठंड बढ़ने के साथ ही पर्याप्त गर्म कपड़े पहनने की सलाह डॉक्टर देते ही हैं। हाथ-पैरों की ठंड से बचाना चाहिए तथा जितना संभव हो सके, उतनी हमें अपनी खुली त्वचा को ढकना चाहिए। मास्क का प्रयोग भी किया जाना चाहिए, जो हमें प्रदूषण से भी बचाता है। पर्याप्त फल-सब्जियों का सेवन करना चाहिए और मोटे अनाज, फलियां, मेवे और पशु स्रोतों से प्राप्त खाद्य पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। नियमित व्यायाम भी आवश्यक है। इससे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बेहतर बनता है।

उम्रदराज लोगों, शिशु और पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों, दिव्यांगों एवं पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों पर खतरा अधिक होता है, इसलिए उनका विशेष ख्याल रखना आवश्यक है। अच्छी बात यह है कि कई शहरों में स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक प्रदूषण से निपटने के लिए कार्य योजनाएं तैयार की जा रही हैं, जो लघु, मध्यम व दीर्घ समयावधि की हैं। इनमें सड़कों के प्रदूषण से निपटना, निर्माण-कार्य वाले प्रदूषकों से पार पाना, अपशिष्टों के जलाने पर रोक जैसे उपाय किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कई तरह की एजेंसियों से भी संपर्क किया जा रहा है, ताकि प्रदूषण-मुक्ति के मार्ग की तमाम चुनौतियों से पार पाया जा सके।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

जादुई स्पिनर अश्विन ने विश्व क्रिकेट को कहा अलविदा

यहां स्कैन करें

मनोज चतुर्वेदी | वरिष्ठ खेल पत्रकार

भारत के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट ड्रॉ होने के बाद अश्विन ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की मौजूदगी में संन्यास की घोषणा कर दी। लोगों को यह लग रहा है कि उन्होंने अचानक संन्यास लिया है, पर वह कप्तान रोहित सभी साथी खिलाड़ियों से चर्चा कर चुके थे। यही नहीं, वह ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रवाना होने से पहले अपने परिवार से भी कह गए थे कि इस मुंखला में प्रदर्शन के बाद करियर को लेकर फैसला करेंगे। बेशक, यह फिट हैं और अभी भी क्रिकेट खेल सकते हैं, पर टीम में उनके लिए जगह का न बन पाना एक बड़ा कारण बन गया।

रविचंद्रन अश्विन को एक ऐसे क्रिकेटर के रूप में याद किया जाएगा, जो स्वभाव से शालीन थे, विवादों से दूर रहते थे। स्वभाव के मामले में उन्हें सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले की श्रेणी में रखा जा सकता है। वह ऑफ स्पिन गेंदबाज के रूप में जाने जाते थे, मगर जरूरत के मुताबिक अपनी गेंदबाजी बदलते रहते थे। उनका मुख्य मकसद विकेट लेना होता था। कुंबले भी इसी शैली के गेंदबाज थे, कभी धीमी गेंद, तो कभी तेज गेंद फेंककर धुरंधर बल्लेबाजों को चकित कर देते थे। कहा जाता है कि वह अपने पड़ोसी को टेनिस खेलते देखते थे और उसे देखकर ही उन्होंने कैरम बॉल ईजाद की थी। उन्होंने अपनी गेंदबाजी में लेग स्पिन को भी जोड़ा। अपनी इस खूबी की वजह से ही उन्हें बाएं और दाएं हाथ से खेलने वाले बल्लेबाजों को गेंदबाजी करने में कोई दिक्कत नहीं हुई।

न बड़बोलापन, न गुटबाजी, सिर्फ खेल से मतलब और जब लगा कि टीम में जगह नहीं रही, तो सबका आभार जताकर चुपचाप चल दिए।

कोई आश्चर्य नहीं कि वह 11 बार 'मैन ऑफ द सीरीज' रहे। 37 बार उन्होंने एक पारी में पांच विकेट लिए थे। भारत अगर लंबे समय तक टेस्ट फॉरमेट में टॉप पर रहा, तो इसमें अश्विन के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। जब-जब उनकी गेंदों ने काम नहीं किया, तब-तब भारतीय टीम संकट में आ गई। टीम एक तरह से संकट से ही गुजर रही है, जब उन्होंने संन्यास लिया है।

उनकी सामान्य विदाई ने बहुत लोगों को उदास किया है। भारत की ओर से अनिल कुंबले के बाद टेस्ट मैचों में सर्वाधिक 537 विकेट लेने वाले गेंदबाज अश्विन भी उन बदकिस्मत क्रिकेटरों में शामिल हो गए हैं, जो अपना विदाई टेस्ट मैच तक नहीं खेल सके। लोगों को पता होना चाहिए था कि यह अश्विन का आखिरी मैच देख रहे हैं। न बड़बोलापन, न किसी की चापलूसी, न गुटबाजी, सिर्फ खेल से मतलब और जब लगा कि अब टीम में जगह नहीं बन रही, तो सबका आभार जताकर चुपचाप चल दिए। उम्मीदों पर खरा न उतरे, तो टीम पर बोझ बनने से इनकार कर दिया। आम तौर पर देखा जाता है कि स्पिनर अच्छे बल्लेबाज नहीं होते हैं, पर अश्विन की बल्लेबाजी ने कई बार टीम को संकट से उबारा। कुल 106 टेस्ट मैचों में उन्होंने छह शतकों और 14 अर्द्धशतकों के साथ 3,503 रन भी बनाए थे। यह अफसोस रहेगा कि उन्हें पूरा सहयोग मिला होता, तो उनके खाते में कम से कम 15-20 टेस्ट और जुड़े होते।

भारत को अश्विन जैसे जादुई स्पिनर मिलने की कहानी कम दिलचस्प नहीं है। उन्होंने बल्लेबाज के तौर पर करियर की शुरुआत की थी। कभी-कभी तेज गेंदबाजी भी किया करते थे। 14 साल की उम्र तक वह ओपनर के रूप में खेलते रहे, पर एक मैच में चोट लग जाने पर उन्हें करीब आठ माह तक क्रिकेट से अलग रहना पड़ा। वह ठीक होकर लौटे, तो टीम में उनकी जगह किसी अन्य खिलाड़ी ने ले ली थी। वह बहुत निराश हुए, मगर मां के कहने पर उन्होंने स्पिनर बनने का फैसला किया और फिर उन्हें दुनिया ने पहचाना। अब 15 वर्ष भारतीय क्रिकेट की सेवा करने के बाद वह विदा हुए हैं, तो उनकी प्रतिभा का उपयोग क्रिकेट के विकास में जरूर होना चाहिए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

खुद को मंदिर बनाइए

जब दुनिया में लोग बहुत भटके हुए होते हैं; जब उनमें खुद को एक जीवंत मंदिर बनाने के लिए मेहनत करने की इच्छा नहीं होती, तो पत्थर का मंदिर बनाना जरूरी हो जाता है। मंदिर बनाने का बुनियादी मकसद खासकर उन लोगों को फायदा पहुंचाना है, जिनके जीवन में साधना नहीं है। खासकर उस इंसान के लिए बाहरी मंदिर अनमोल होता है, जो अपने शरीर को मंदिर बनाना नहीं जानता।

प्रतिष्ठा तमाम तरीकों से की जाती है, लेकिन आम तौर पर इसके लिए विधि-विधान, मंत्र, ध्वनियों, रूपों और दूसरी कई चीजों का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब यह है कि इसे लगातार देख-रेख की जरूरत होती है। प्राचीन काल से आपसे कहा जाता है कि पत्थर की मूर्ति घर में न रखें। अगर आप उन्हें रखते हैं, तो हर दिन आपको सही तरीके से पूजा और दूसरे विधि-विधान द्वारा इनकी देख-रेख करनी चाहिए। ऐसा इसलिए है, क्योंकि अगर किसी मूर्ति की प्रतिष्ठा मंत्रों से की गई है और हर दिन विधि-विधान और जरूरी देख-रेख नहीं की जाती, तो मूर्ति की ऊर्जा घटने लगती है। दुर्भाग्य से, हमारे देश में बहुत से मंदिरों की दशा ऐसी हो गई है, क्योंकि लोगों ने मूर्ति की देख-रेख गलत तरीके से की, क्योंकि वे मूर्ति की जीवंत रखना नहीं जानते थे।

प्राण-प्रतिष्ठा इससे अलग चीज है, क्योंकि इसके तहत किसी चीज की प्राण-प्रतिष्ठा के लिए आपकी ही जीवन-ऊर्जा इस्तेमाल होती है। जब आप इस विधि से किसी रूप को प्रतिष्ठित करते हैं, तब उसे किसी तरह के रखरखाव या देखभाल की जरूरत नहीं होती। यह शाश्वत होता है। इसी वजह से कोयंबटूर के ध्यानलिंग ध्यान-मंदिर में किसी तरह का विधि-विधान और पूजा नहीं की जाती। वहां इन सबकी कोई जरूरत ही नहीं है। याद रखिए, अधिकतर मंदिरों में होने वाले विधि-विधान भक्तों के लिए नहीं होते; इनको बस देवता को जीवंत रखने के लिए किया जाता है। लेकिन ध्यानलिंग में ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है; इसकी ऊर्जा कभी घटेगी-बढ़ेगी नहीं। अगर आप लिंग के पत्थर को हटा भी दें, तब भी वह वैसा ही रहेगा। अगर आप इस धरती को नष्ट भी कर दें, तब भी लिंग का ऊर्जा-स्वरूप गायब नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि असली लिंग अभौतिक आयाम से बना है, और आप अभौतिक को नष्ट नहीं कर सकते।

मंदिर बनाने का बुनियादी मकसद उन लोगों को फायदा पहुंचाना है, जिनके जीवन में साधना नहीं है। उनके लिए बाहरी मंदिर अनमोल होता है, जो अपने शरीर को मंदिर बनाना नहीं जानते।

आप जहां भी अपना अधिकतर समय बिताते हैं- आपका घर, आपकी सड़क, आपका ऑफिस, वे स्थान प्रतिष्ठित होने चाहिए। आपका भीतरी विकास डार्विन जैसे किसी पैमाने के अनुसार होना जरूरी नहीं है। अगर आप प्रतिष्ठित स्थान में रहते हैं, तो आप लंबी छलांग लगा सकते हैं। मेरा तो यह सपना है कि एक दिन सारी मानवता प्रतिष्ठित स्थानों में ही निवास करे।

सद्गुरु जग्गी वासुदेव

धर्मेंद्र प्रधान | केंद्रीय शिक्षा मंत्री

भारत सरकार की शिक्षा नीति में भारतीय भाषा व मातृभाषा प्राथमिकता के विषय हैं। आज हमारी प्रवेश परीक्षाएं असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, ओड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी- 13 भाषाओं में होती हैं।

काम ज्यादा करना कब सीखेंगे हम

जो समाज सिद्धांतों और किताबी आदर्शों पर अधिक ध्यान देता है, केवल सिद्धांत-कथन को ही बहुत बड़ी उपलब्धि मानता है, उसका विनाश निश्चित है। इसके विपरीत, जो लोग बातें करने और निष्फल बहसबाजी से दूर रहकर काम पर ध्यान लगाते हैं, वे अपने देश, समाज व समुदाय के बड़े हितैषी हैं। जापानी लोग इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं। वे बहुत कम बात करते हैं, किंतु अपने काम के प्रति उनमें गजब का समर्पण रहता है। अपने देश के प्रति उनका प्रेम अतुलनीय है। एक हम हैं। नारायण मूर्ति ने प्रति सप्ताह 70 घंटे काम करने की सलाह क्या दी, हम हाथ धोकर उनके पीछे ही पड़ गए। देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों के बयान सुनाई नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि वे अपने काम में जुटे हुए हैं। लघु उद्योगों के निमित्त गठित शीर्ष वित्तीय संस्था में काम करते हुए मैंने देखा कि लघु उद्योग संघों के अध्यक्ष, सचिव आदि पदों पर आसीन महानुभावों की इकाइयां प्रायः निष्क्रिय हैं। वे कोई भी माल या सेवा नहीं देतीं। उनका मुख्य काम नेतागिरी है। जाहिर सी बात है, या तो आप नेतागिरी कर लें या काम। हमारे देश में नेतागिरी सबसे अधिक लाभदायक पेशा है, क्योंकि उसके माध्यम से आप संसाधनों पर अवैध कब्जा कर सकते हैं। हम इस गलत काम की मुखालफत तो करते नहीं, फालतू का ज्ञान बांटते रहते हैं। नेतागिरी हर जगह है। इस दीमक से मुक्ति मिले, तो देश आगे बढ़े। गुरुओं में भी चेतना नहीं। इक्का-दुक्का अपवाद जरूर दिख जाते हैं। शिक्षक केवल नौकरी करते हैं। अपने सिलेबस से बाहर उन्हें नहीं जाना और हर सिलेबस कोरा सिद्धांत-कथन है। हमारे संस्थान डिग्री छापने के कारखाने हैं। उनके केवल 12-13 फीसदी छात्र काम के होते हैं, शेष सिर्फ डिग्रीधारक। ऐसी डिग्री का क्या मतलब? साफ है, हमने यदि पूरी व्यवस्था का पुनः-अभिमूर्तीकरण नहीं किया, तो हम शीघ्र नष्ट हो जाएंगे।

आर वी सिंह, रचनाकार

मूर्ति का मंतव्य

एक हफ्ते में 70 घंटे काम करने संबंधी नारायण मूर्ति के मत का मंतव्य समझना चाहिए। वह विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, जिसे हरेक भारतीय को अपना सपना बना लेना चाहिए। 'आराम हराम है' का नारा कभी प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तब उनका यही मानना था कि देश के निर्माण में हमें जी-जान से जुट जाना चाहिए। लोगों ने इस पर अमल किया और देश की इतनी अच्छी बुनियाद पड़ी। आज जब चुनौतियां पहले की तुलना में बढ़ गई हैं, तो हमें आरामतलबी त्यागकर नारायण मूर्ति की बातों पर अमल करना ही चाहिए।

शोभित, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

70 घंटे काम

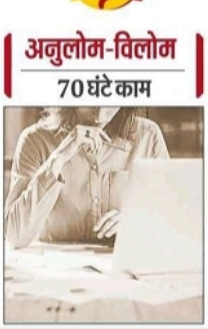

सप्ताह में 70 घंटे काम करना अव्यावहारिक

नारायण मूर्ति की बातों को मान लें, तो कर्मचारियों की दिनचर्या कुछ इस तरह से होगी- सप्ताह में पांच दिन, यानी रोजाना 14 घंटे ऑफिस का काम। अब बचे 10 घंटे। बड़े शहरों में घर से कार्यस्थल तक जाने-आने में कम से कम डेढ़ से दो घंटे का समय लगता है, क्योंकि सभी के कार्यस्थल घर के आसपास नहीं होते। वे आमतौर पर रिहायशी इलाकों से दूर, औद्योगिक क्षेत्रों में होते हैं। फिर, दफ्तर जाने से पहले तैयार होना, यानी नहाने-धोने, नाश्ता आदि करने में तकरीबन दो घंटे का समय लगता है। इसका मतलब है कि इन सब समय को खपाने के बाद आदमी के पास बमुश्किल छह घंटों का वक्त बचेगा, जिसमें वह अपनी नींद लेगा। कहने का मतलब है कि हफ्ते में 70 घंटे काम करने वाला नौजवान इंसान नहीं, मशीन होगा। विशेष परिस्थिति में तो कोई भी युवा क्या, उम्रदराज (60 साल के आसपास वाला इंसान) कर्मी भी अपने नियमित कामों में समय की कटौती करके कार्य के लिए 14 क्या, 16 घंटे निकाल सकता है, किंतु क्या नियमित रूप से यह सब संभव है? इतना समय तो कोई अविवाहित निकाल सकता है या फिर जिसका घर और दफ्तर एक ही जगह हो। मगर सच यही है कि हर कंपनी/ऑफिस घर के पास तो नहीं हो सकते और न ही कोई कंपनी इतने बड़े आवासीय क्षेत्र की व्यवस्था करके अपने कर्मचारियों को यहां समाहित कर सकती है। अतः नारायण मूर्ति अपने सुझाव पर फिर से गौर करें। वह शायद जानते भी होंगे कि रोजाना 14 घंटे कार्य करने से कर्मचारियों की कार्यक्षमता, गृहस्थी व स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। देश का विकास जरूरी है, पर अपने कर्मियों को बीमार बनाकर कोई राष्ट्र तरक्की नहीं कर सकता।

शकुंतला महेश नेनावा, टिप्पणीकार

ऐसा संभव नहीं

यह ठीक है कि राष्ट्र की उन्नति के लिए हमें सोचना चाहिए, पर इंसान सबसे पहले एक सामाजिक जीव है और समाज के प्रति भी उसकी जिम्मेदारी है। अगर कोई व्यक्ति रोजाना 14 घंटे काम करेगा, तो फिर अपने घर-परिवार और समाज के लिए कब वक्त निकाल सकेगा? दो दिन की छुट्टी तो थकान उतारने में ही जाया हो जाएगी। वैसे भी, एआई के इस दौर में जब कर्मचारियों पर से काम का भार कम करने का प्रयास हो रहा हो, तब हफ्ते में 70-70 घंटे काम करने की वकालत करने का क्या मतलब है? नारायण मूर्ति बेशक अपनी एक ही बात दोहराए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय परिस्थितियों में ऐसा अभी संभव नहीं जान पड़ता। उन्हें अपने सुझाव पर पुनर्विचार करना चाहिए।

स्वाति, टिप्पणीकार